हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 19 मार्च, 1980

		पृश्ठ संख्या
	तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(14)1
	नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(14)22
	अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(14)27
	चण्डीगढ़ में हरियाणा के कंधे व्यक्तियों के साथ अभिकथित बल प्रयोग तथा दुर्व्यवहार पर चर्चा उठाने सम्बन्धी	(14)31
	जिला हिसार के चौधरीवास गांव में हरिजन लड़के के कत्ल के बारे में कमेटी भेजने सम्बन्धी	(14)34
	औचित्य प्रश्न –	
	सदन में धरना देने सम्बन्धी	(14)36
	ध्यानाकर्शण सूचना –	

	अम्बाला छावनी में पीलिया की महामारी फैलने सम्बन्धी	(14)37
	वक्तव्य –	
	सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा आमतौर पर राज्य के सूखा क्षेत्रों में तथा विशेशतया मेहम के 15 गांवों में तालाबों में पानी सूखने सम्बन्धी	(14)38
	नियम 30 क अधीन प्रस्ताव	(14)40
	वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान बैठक का समय बढ़ाना	(14)40
	बैठक का समय बढ़ाना	(14)85
	वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(14)85
	राज्यपाल से सन्देश	(14)89

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 19 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबार, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर 1586

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौ. राम लाल वधवा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Shortage of Electricity and non-availability of Diesel in the State

***1633. Sh. Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad**: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that many factories in the State have been either forced to close or run much below their produciton capacity due to shortage of electricity and non-availability of diesal rendering large number of workers/labourers unemployed; if so, the

steps, if any taken or proposed to be taken by the Government to meet the demand of the factories for electricity and diesel?

Mr. Speaker: *Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under –

D.O. No. 13/12/80-IIB(1)

"Bhajan Lal,

CHIEF MINISTER,

HARYANA, CHANDIGARH.

Subject: Starred Assembly Question No. 1633-Shortage of electricity and non-availability of diesel in the State.

My dear Rao Sahib,

Starred Assembly Question No. 1633 asked by Sarvshri Fatech

* Final reply to this question appears as Annexure 'A' to this debate. (Page 90)

Chand Vij and Shiv Parshad, M.L.As. has been fixed for answer on 19-3-1980. The reply to this question is not ready as the required information is very lengthy and involves a lot of time and labour. Moverover, this information is to be collected from the field offices. So it is not possible to give the reply in time.

2. I shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question by one month, under proviso (ii) to Rule 41 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

With regard,

Yours sincerely,

Sd/-

(Bhajan Lal)

Col. Rao Ram Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी और इम्पौर्टेट मसला है इसका जवाब तो आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: गवर्नमैंट ने एक्सटेन्शन मांगी थी वह मैंने दे दी है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने पूछा है कि सारी स्टेट के अन्दर कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनको बिजली और डीजल न मिलने के कारण बन्द किया गया है। स्पीकर साहब हमारी स्टेट में 22 हजार के करीब फैक्ट्रियां हैं। इसलिये इनका डैटा कलैक्ट करने में काफी समय लगेगा। इसलिये

जब भी हमारे पास यह सारा डैटा कलैक्ट हो जायेगा तो इसका जवाब बाकायदा लिखकर आपको भेज दिया जायेगा। (व्यवधान)

Mr. Speaker: A note on sugar-distribute of levy sugar and measures taken to increase availability and to check rise in price of free sale sugar has been received from the Hon. Minister for circulation amongst the members. This has been circulated, and I am sure, all of you have got it. It is a very detailed note.

Damage to 1980 Rabi Crop

***1646. Swami Adityavesh**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether it is a fact that ye yiedl of present Rabi Crop is excepted to be 50% less and compared to the Rabi Crop of last year due to drought and short supply of electricity to the farmers in the State; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative whether there is any proposal under consideration of the Government to give relief to the farmers referred to above; if so, the details thereof?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) नहीं जी।

(ख) नहीं जी।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि क्या यह ठीक है कि सूखे के कारण तथा बिजली की कमी के कारण किसानों की पैदावार इस साल पिछले साल के मुकाबले 50 प्रतिशत कम होगी? अगर नहीं तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर कितना नुक्सान हुआ है और क्या सरकार किसानों को कोई राहत देने का प्रयास करेगी?

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल रिवाईज करके पूछ सकते थे। आपने स्पश्ट पूछा है कि 50 प्रतिशत नुक्सान हुआ है यह नहीं। अगर आप यह पूछते कि कितना नुक्सान हुआ है तो ये जवाब दे देते।

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जबवा देने के लिये बिल्कुल तैयार हूं। 21.3 प्रतिशत का नुक्सान हुआ है।

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब इस साल पैडी 8 क्विंटल फी एकड़ पैदा हुई है और इस हिसाब से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा का नुक्सान हुआ है मिनिस्टर साहब 21.3 प्रतिशत का नुक्सान बता रहे हैं। मैं मुन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने नुक्सान का क्या क्राईटेरिया रखा हुआ है?

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों की काफी मदद की है। किसानों को एकस्ट्रा पानी भी दिया है, बिजली भी दी है और डीजल भी 70 प्रतिशत के करीब दिया है। यह कहना कि बिजली किसानों को नहीं दी जा रही, यह ख्याल

इन लोगों का गल्त है। गेंहू में 64 हजार एकड़ में और चना 3.59 हजार हैक्टेयर में कम बोया गया है। इस वक्त गेहूं के नुक्सान का जो अनुमान लगाया गया है वह 3 लाख टन का है और चने का 5 लाख टन के करीब का है। स्पीकर साहब, यह गवर्नमैंट के आंकड़े हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 21.3 प्रतिशत का डैमेज हुआ है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि 21.3 प्रतिशत के नुक्सान को देखते हुए फारमर्ज को कोई रिलीफ देंगे?

सरदार तारा सिंह: जितनी फसल की बिजाई किसान ने की है अगर नैचुरल कलेमीटीज की वजह से किसान का 25 प्रतिशत नुक्सान हुआ है तो उस पर गवर्नमैंट जरूर रिलीफ देगी।

चौ. हरस्वरूप बूरा: क्या मंत्री जी बताएंगे कि 21.3 प्रतिशत का जो डैमेज हुआ है इसका कारण यह तो नहीं है कि फसल की बिजाई के समय तो पानी दे दिया गया हो और फसल की बिजाई होने के बाद पानी न आया हो?

सरदार तारा सिह: यह कहना गलत है कि फसल की बिजाई के बाद एक भी पानी ने आया हो। मैं सारे जिलों के अन्दर गया हूं। यह हो सकता हे कि एक–आध पानी कम आया हो लेकिन यह कहना कि पानी फसल की बिजाई के बाद बिल्कुल नहीं आया है, यह गलत है।

श्री मनी राम: अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई शक नहीं है कि फसल की बिजाई के समय पानी काफी आया है। लेकिन फसल की बिजाई कुी हो गई और पानी कम रह गया जिसकी वजह से 75 प्रतिशत का नुक्सान हुआ है। क्या सरकार किसानों के नुक्सान को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, कुछ हल्के ऐसे जरूर हैं जहां पर नैचुरल कलेमीटीज से नुक्सान ज्याद हुंआ है वरना पानी काफी मिला है। फसल इतनी बुरी नहीं है जितनी मेरे दोस्त बता रहे है।

श्री मूल चन्द मंगला: अध्यक्ष महोदय, विश्वास दिलवाया गया था कि डीजन और बिजली की कमी के कारण सरकार द्वारा ''हवाई पम्पिंग सैटस'' लगाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा. मंगल सैन: मंत्री महोदय ने सवाल के 'बी' पार्ट के जवाब में फरमाया है कि 'नहीं जी'। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का कोई रिलीफ देने का विचार है और अगर है तो किस हालत में यह रिलीफ देंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने पहले ही फरमाया है कि जहां पर 25 प्रतिशत फसल डैमेज होती है, वही पर सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले दिनों फैसला किया है कि जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान है वहां पर आबियाना और मालिया बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा।

चौ. रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी फरमाया था कि 21.3 प्रतिशत का फसलों को नुक्सान हुआ है और यह भी फरमाया है कि बिजली की भी कुछ कमी रही है तथा एकाध पानी की कम आया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली और पानी की कमी के कारण जिस फसल के अन्दर अभी तक दाने भी नहीं पड़े हैं क्या उन फसलों के अन्दर दाने न पड़ने से होने वाले नुक्सान का भी सरकार ने अन्दाजा लगाया है?

सरदार तारा सिंह: मैं अपने फाजिल दोस्त को बताना चाहता हूं कि अभी तक पूरी फसल में पूरे दाने नहीं पड़े हैं। इसलिये फसलों में दाने न पड़ने से कितना नुक्सान हुआ है, के बारे में कहना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब यह है कि 21.3 प्रतिशत कम बिजाई हुई है (व्यवधान) इनीशियल स्टेज पर ही इतनी बिजाई

कम हुई है क्या यह आपके अफसरान ने अन्दाजा लगा करके बताया है? (व्यवधान व शोर)

सरदार तारा सिंह: जी हां।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 21.3 प्रतिशत कम बिजाई हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह असैसमैंट करवाई गई है कि बिजाई के बाद कितनी फसल तबाह हुई है मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर सरकार को यह असैसमैंट करवाने के बाद पता लगे कि 25–30 या इससे भी ज्यादा परसैन्ट नुक्सान हुआ है, तो क्या सरकार किसानों को कोई रिलीफ देने का प्रबन्ध करेगी?

सरदार तारा सिंह: जैसे मैंने बताया है, अगर 25 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान हुआ होगा तो हम जरूर रिलीफ देंगे।

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अगर 25 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान हुआ तो हम रिलीफ जरूर देंगे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि नुक्सान स्टेट की वजह से हुआ होगा तो क्या फिर भी वह रिलीफ देंगे? मेरे इलाके नरवाना में 1200 क्यूसिक पानी पहले मिला करता था लेकिन इस बार वहां पर 650 क्यूसिक का कट लगा दिया गया है इस वजह से वहां पर किसानों की काफी फसलें तबाह हो चुकी हैं। क्या सरकार उनको भी कुछ मुआवजा देने पर विचार करेगी।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह सैपरेट क्वैश्चन है अगर यह मुझे पहले बताते तो मैं त्यार हो कर आता।

श्री टेक राम: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 21.3 प्रतिशत कम फसल की बिजाई बताई गयी है, यह अफसरों ने मौके पर जाकर इन्क्वायरी करके आपको बताई है या पिछला रिकार्ड देखकर ही बता दी है?

सरदार तारा सिंह: मेरे माननीय दोस्त को बहम हो गया। अफसरान हमारे पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। यह जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, यह ठीक दी है।

स्वामी आदित्यवेश: अभी मंत्री महोदय ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि जिन क्षेत्रों में 21.3 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान हुआ है, हम वहां पर कुछ न कुछ राहत अवश्य देंगे। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर सिर्फ आबियाना ओर मालिया माफ करेंगे या इसके अलावा कोई और रिलीफ भी देंगे?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैने तो 21.3 प्रतिशत कहा नहीं है। मैंने तो यह कहा है कि जहां पर 25 प्रतिशत या इससे ज्यादा नुक्सान होगा, वहां पर हम रिलीफ देंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वहां पर क्या क्या रीलीफ देंगे, इसके बारे में सरकार पालिसी बनायेगी।

श्री अध्यक्ष: इस क्वैश्चन पर 12 मिनट लगा दिय गये हैं। अब अगला सवाल होगा।

Taking over the Private Colleges in the State

***1472. Sh. Hira Nand Arya**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over all the affiliated private colleges in the State; if not, the reasons therefor?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शांति देवी): नहीं। पर्याप्त धन के अभाव के कारण राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि सभी अराजीय सम्बन्ध महाविद्यालयों को अपने नियंत्रण में ले।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं सी.पी.एस. साहिबा से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात इसके नोटिस में है कि बहुत से प्राइवेट कालेजिज ऐसे हैं जिनकी ऐसी खस्ता हालत है कि वे अपने एम्पलाईज को पूरी तनख्वाह तक नहीं दे सकते? क्या सरकार कोई फेज्ड प्रोग्राम बनाकर ऐसे कालेजिज को टेक–ओवार करने का विचार रखती है?

श्रीमती शांति देवी: स्पीकर साहब, इस वर्श हम 12 प्राइवेट कालेजिज टेक ओवर कर चुके हैं। आर्थिक अवस्था को देखते हुए इस वर्श और अधिक कालेजो को टेक–ओवर करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: मैं सी.पी.एस. साहिबा से यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर कोई गवर्नमैंट कालेज है और वहां पर दूसरा प्राईवेट कालेज ऐसा है जिसकी काफी खस्ता हालत है, क्या उस प्राईवेट कालेज को टेक–ओवर करने के लिये गवर्नमैंट कालेज का होना तो कोई रूकावट नहीं है?

श्रीमती शांति देवी: स्पीकर साहब, सरकार का निर्णय है कि जहां पर कोई भी सरकारी कालेज हैं, वहां पर हम किसी प्राइवेट कालेज को टेक–ओवर करने पर विचार नहीं करते।

चौ. ईश्वर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सी.पी. एस. साहिबा से यह जानना चाहूंगा कि लोग अगर कालेज बनाने के लिये जमीन भी दें और बिल्डिंग भी दें और जितनी दूसरी किस्म की मदद वे दे सकते हैं वे दे दें तो क्या सरकार वहां पर कालेज खोलने पर विचार करेगी?

श्रीमती शांति देवी: इस पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई नया कालेज खोल सकें।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सोनीपत जिले के अन्दर कोई भी गवर्नमैंट कालेज नहीं है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गोहाना में एक प्राइवेट कालेज है, उसकी हालत इतनी खराब है कि बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। क्या सरकार उस कालेज को टेक ओवर करने के लिये कोई प्रैफरेन्स देने के लिये तैयार है?

श्रीमती शांति देवी: यह मामला विचाराधीन है। फाइनैन्स में गया हुआ है। जल्दी ही इस पर फैसला हो जायेगा।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेजिज को टेक ओवर करने के लिये जो सर्वे कमेटी बनाई गयी थी, उसने संभालखा का जो एक प्राईवेट कालेज है, उसको टेक ओवर करने के लिए रिपोर्ट दी थी क्योंकि वह ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। क्या सी.पी.एस. महोदया बताने की कृपा करेंगी कि उस कालेज को टेक ओवर किया जाएगा।

श्रीमती शान्ति देवी: स्पीकर साहब, एक कमेटी श्री के. सी. शर्मा की अध्यक्षता में नियुक्ति की गयी थी। उस कमेटी ने यह कहा था कि गांधी मैमोरियल कालेज सम्भालखा को टेक ओवार कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद एक कमेटी श्री ओ.पी. भारद्वाज की अध्यक्षता में बनाई गयी थी। उसने यह कहा कि इसके टेक ओवर करना अभी इतना जरूरी नहीं है जितना कि दूसरे कालेजों को। हमने इसलिये इस साल 12 कालेजिज को टेक ओवर कर लिया है।

चौ. संत कंवर: मैं सी.पी.एस. साहिबा से यह पूछना चाहता हूं कि कहीं प्राईवेट कालेजिज टेक–ओवर करते वक्त यह क्राइटेरिया तो नहीं था कि जो कालेजिज चुनावों के दौरान गवर्नमैंट के साथ थे, उनको तो टेक ओवर कर लिया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये बाकायदा एक कमेटी श्री के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी। उसने जो सिुारिशात की हैं, मेरे ख्याल में उसके हिसाब से टेक–ओवर किये हैं।

श्रीमती शान्ति देवी: स्पीकर साहब, सरकार ने कुछ शर्तें लगायी थी जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां 20 किलोमीटर तक आस–पास कोई गवर्नमैंट कालेज न हो और वहां पर कम से कम 150 बच्चे हों, या फिर 10 किलोमीटर तक आस–पास कोई गवर्नमेंट कालेज न हो और वहां पर कम से कम 250 बच्चे हों। वहां पर कालेज खोला जाएगा। नगरों में जो प्राइवेट कालेजिज थे, उनको टेक–ओवर करने के लिये हमने विचार नहीं किया था।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, बहिन जी ने बताया है कि 12 कालेज टेक–ओवर किये हैं। यह सारे के सारे कालेज लोक सभी के इलैक्शन के दौरान टेक–ओवर किये गये हैं। अगर अब असैम्बली के चुनाव हो जायें तो क्या बाकी के सारे कालेजिज को टेक–ओवर करने पर सरकार विचार करेगी?

श्रीमती शांति देवी: स्पीकर साहब, जैसे कि मैंने बताया है कि श्री के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसकी सिफारिशात के हिसाब से हमने तक किया है। माननीय सदस्य को इस तरह का लांछन नहीं लगाना चाहिए।

डा. मंगल सैन: मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने यह बताया है कि आर्थिक अभाव के कारण और कालेजिज इस समय

टेक–ओवर नहीं किये जा सकते। क्या इनको यह भी पता है कि कई कालेजिज ऐसे है जिनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, उनको टेक ओवर करने की बजाये क्या सरकार उनको कोई विशेश सहायता या अनुदान देने के बारे में विचार करेगी?

श्रीमती शांति देवी: अनुदान और विशेश सहायता हम उन्हें पहले दी दे चुके हैं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अभी सी.पी.एस. साहिबा ने यह बताया कि धन के अभाव के कारण हम कालेजिज को टेक–ओवर नहीं कर सकते और डाक्टर साहब के सवाल के जवाब में उन्होंने यह बताया है कि हम उन्हें अनुदान दे चुके हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि जो 75 प्रतिशत अनुदान प्राइवेट कालेजिज को दिया जाता है, वह भी उनकी इन्कम में गिना जाता है। क्या वे इस बात पर विचार करेंगी कि इस 75 प्रतिशत अनुदान की राशि को उनकी इन्कम न ट्रीट किया जाये?

श्रीमती शांति देवी: यह तो आपका सुझाव है, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: यह सुझाव नहीं है, यह तो स्पैसिफिक क्वैश्चन है?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेजिज को पहले 35 प्रतिशत ग्रांट मिला करती थी। हमने यह महसूस किया कि इन कालेजिजकी खस्ता हालत को सुधारने के

लिये इन्हें और ज्यादा ग्रान्ट दी जानी चाहिए। इसलिये हमने इसे 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। जहां तक बहिन सुशमा जी की इस बात का ताल्लुक है, कि इसे भी उनकी इन्कम ट्रीट किया जाता है।

राव दलीप सिंह: क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सेक्रेटरी साहिबा बताने की कृपा करेंगी कि हमारे यहां एक सिघरावली कालेज है क्या उसको टेक–ओवर किया जाएगा?

श्रीमती शांति देवी: स्पीकर साहब, अभी तो कोई विचार नहीं है अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो भविश्य में विचार कर लिया जाएगा।

कामरेड शंकर लाल: क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जो प्राइवेट कालेजिज टेक–ओवर किए हैं, उन कालेजिज के अन्दर प्रोफेसर और दूसरे कर्मचारी काम करते हैं, उनको रैगुलर करने का क्या तरीका है?

श्रीमती शांति देवी: स्पीकर साहब, हमने कुछ योग्यताएं रैगूलर करने के लिये निर्धारित की थीं और जो कर्मचारी उन योग्याताओं को फुलफिल करते हैं उन्हें हम सेवा में ले चुके हैं।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने बताया है कि जहां पर गवर्नमैंट कालेज हैं और प्राईवेट कालेज भी हैं उस जगह पर प्राईवेट कालेज को टेकओवर नहीं किया जाएगा। स्पीकर साहब, गुड़गांव में गवर्नमेंट कालेज भी

है और एस.डी. कालेज भी है और उस एस.डी. कालेज को टेकओवर कर लिया गया है जबकि पलवल में एक प्राईवेट कालेज है उसमें बच्चों की संख्या उतनी ही है जितनी कि गुडगांव के एस. डी. कालेज में है। इस कालेज में प्रौफेसरों को कई महीनों से तनखाह भी नहीं मिल रही है और यह देहाती कालेज है। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बताने की कृपा करेंगी कि पलवल के कालेज को क्यों टेकओवर नहीं किया गया है और गुड़गांव के कालेज को क्यों टेकओवर कर लिया गया है?

श्रीमती शांति देवी: माननीय सदस्य अलग से नोटिस दे दें उस पर विचार किया जा सकता है। (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब इस सीरियस मैटर का जवाब मैं दे देता हूं। गुड़गांव का कालेज हमने टेकओवर किया है और वह इसलिये किया है कि उसमें बच्चों की तादाद साढ़े आठ सौ से ऊपर है और उस कालेज की हालत बहुत खराब चल रही थी। पच्चीस महीने से कालेज के प्रोफैसर्ज को तनखह नहीं मिल रही थी। जो गवर्नमैंट कालेज है उसमें जितनी सीटें हैं वे सब फल थीं। एक हजार बच्चों को पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं था। इसलिये गवर्नमैंट ने यह महसूस किया कि इसको एज ए स्पैशल केस टेकओवर कर लिया जाए।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने यह कहकर कि जहां गवर्नमेंट कालेज होगा वहां पर

प्राइवेट कालेज को टेकओवर नहीं किया जाएगा, हाउस को गुमराह किया है (व्यवधान)

श्रीमती शांति देवी: मैंने कोई हाउस को गुमहरा नहीं किया है। अगर सरकार आवश्यकता समझेगी तो प्राथमिकता के आधार पर ऐसा डिसीजन लेने का पूरा अधिकार रखती है।

चौ. भजन लाल: उस कालेज की हालत बहुत खराब थी। इसलिये जनता के हित में और गुडगांव के हित में हमने यह कदम उठाया है और ये कह रहे है कि सदन को गुमराह किया है।

श्री अध्यक्ष: जब मैं शिक्षा मंत्री था तो इस गुडगांव के कालेज की स्ट्रैथ एक समय दो हजार की होती थी और इस कालेज की बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि सरकार ने गुडगांव के कालेज को टेकओवर करके बहुत अच्छा कात किया है।

डा. मंग सैन: स्पीकर साहब, हमें इसमें एतराज नहीं लेकिन बहन जी ने सदन को गुमराज किया है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: She has given some guidelines but exceptions are always there.

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, एज ए स्पैशल केस किया है। गवर्नमैंट ने सारी लाएबिलिटीज अपने ऊपर ली हैं। (व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा है कि जहां गवर्नमैंट कालेज है वहां पर प्राईवेट कालेज को टेकओवर नहीं किया जाएगा। सवाल तो सिर्फ इतना है कि ऐसा क्यों कहा गया है और दूसरी तरफ प्राईवेट कालेज को जहां पर गवर्नमेंट कालेज भी है, टेकओवार किया जा रहा है। (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, जहां पर सरकार ने जरूरी समझा वहां कालेज टेकओवर कर लिया और भविश्य में अगर जरूरी समझेगी तो दूसरे कालेजिज भी टेक ओवर करेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सी.पी.एस. साहिबा ने बताया है कि बारह कालेज टेकओवर किए है। क्या सी.पी.एस. साहिबा बातने का कश्ट करेगी कि ये सारे कालेजिज वही हैं जो सर्वे कमेटी ने रिकमैन्ड किए हैं या उस लिस्ट से बाहर का भी कोई कालेज टेकओवर किया गया है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, सर्वे कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट में कालेजिज को टेकओवार करने के बारे में दी है लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां कमेटी का ध्यान नहीं पहुचा और लोगों की डिमाड थी कि उनके यहां के कालेज को टेक ओवार कर लिया जाए। लोगों की डिमांड को देखते हुए मैनेजमैंट की टेकओवार करने की अपील को देखते हुए और यह देखते हुए कि मैनेजमैंट उस कालेज का इन्तजाम नहीं कर सकता, प्रौफेसर्ज को

तनखाह नहीं दे सकता। स्पीकर साहब, इन सब चीजों को देखते हुए हमने कुछ और कालेजिज भी टेकओवर किए हैं।

Mr. Speaker: I think, the Government is not bound by the recommendations and the guidelines of any Committe. The Government is at liberty to take its decision.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, सदन में बताया गया है कि के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में एक सर्वे कमेटी बनाई गई थी। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या उस कमेटी ने कुछ कालेजिज को बन्द करने की रिकमेंडेशन की थी और अगर की थीं तो क्या उन कालेजिज को बन्द किया जाएगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि 20 मई 1979 में एक कमेटी जिसमें मैं था, बाबू मूल चन्द जैन थे और कई और आफिसर्ज थे, ने यह फैसला किया था कि कालेजिज की ग्रांट को इन्कम ट्रीट नहीं किया जाएगा। यह मई, 1979 का फैसला है। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बताने की कृपा करेगी कि कालेजिज की आर्थिक हालत को देखते हुए इस रिकमेंडेशन की अप्रैल, 1979 से लागू करने की कृपा की जाएगी? (व्यवधान)

Mr. Speaker: This supplementary is too long and is not clear.

Sh. Surrneder Singh: If you kindly permit, I will make it more clear, sir.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि मई, 1979 में इस मामले हो हरियाणा सरकार के फाइनेंस, ऐजुकेशन मिनिस्टर्ज, फाइनेंस और ऐजुकेशन सैक्रेटरीज ने मिलकर यह फैसला किया था और यह डिसिजन रिकार्ड पर भी है कि इस ग्रांटस को इन्कम ट्रीट न किया जाए और यह भी तक किया था कि यह फैसला अप्रैल, 1979 से लागू होगा। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि वह डिसिजन अप्रैल, 1979 से क्यों लागू नहीं किया गया?

चौ. भजन लाल: स्पीकर सहिब, अगर यह फैसला मई, 1979 में किया गया था तो उस वक्त बाबू मूल चन्द जैन वित्त मंत्री थे और आर्य जी ऐजुकेशन मिनिस्टर थे इन्होंने उस फैसले को लागू क्यों नहीं किया? अब हमने फैसला किया है कि 1 अप्रैल, 1980 के बाद जब हम ग्रान्ट देंगे तो उसको इन्कम ट्रीट नहीं किया जाएगा।

Prevention and control of water pollution

***1658. Sh. Mool Chand Jain**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the date on which the Haryana State board for the Prevention and Control of Water Pollution was set up in the State;

(b) the number of old and new factories, plants and mills which have so far applied to the Board to discharge their sewerage to trade effluents since its establishment;

(c) the number of cases; if any, in which ingradients of sewerage of trade effluents discharged by teh Industries referred to in part (b) above, were found to be injurious to Public Health;

(d) whether any factories, plants or mills out of those referred to in part (c) above, have set up plants for the proper treatment of the sewerage of trade effluents; if so, the number and names thereof;

(e) whether any directions have been issued to the industries located in the State directing them to get consent of the Board for the discharge of their trade effluents; if so, the number thereof; together with the number in which the consent was given; and

(f) the number of industries, if any, which failed to comply with teh conditions contained in teh directions referred to in part (e) above and the actin, if any, taken against such industries?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी):

(ए) 19.9.74

(बी) पुरानी 185, नयी 24

(सी) 104

(डी) 2, नाम यह है:–

1. मैसर्ज नैशनल फटिलाईजरज पानीपत।

2. मैसर्ज हरियाणा टैनरीज जीन्द।

(ई) हां, 1592 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए, 194 उद्योगों को सहमति दी गयी।

(एफ) 50 औद्योगिक इकाईयां हैं जोकि बोर्ड द्वारा दी गई सहमति की ट्रीटमैंट के लिए शर्तो का पालन करने में असफल रहे है। 12 उद्योगों के विरूद्ध प्रोसिक्यूशन कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। बाकी दूसरों के विरूद्ध कार्यवाही करने का मामला विचाराधीन है।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, इस बोर्ड को बने हुए छः वर्श हो गए हैं और इस बोर्ड का काम फैक्टरीज से जो गन्दा पानी निकलता है या दूसरी तरह की जो गन्दगी निकलती है उसको कन्ट्रोल करना था। लेकिन इस बोर्ड ने छः वर्श के अन्दर केवल 1592 इंडस्ट्रियलिस्टस को नोटिस दिए, जबकि हरियाणा के अन्दर बीस हजार फैक्टरीज हैं। स्पीकर साहब, इनमें से केवल बारह को प्रौसीक्यूट नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बोर्ड की परफौरमेंस तसल्लीबख्श है?

चौ. मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब चौ. देवी लाल गए तो वे हिदायत दे कर गए कि छः महीने तक इनके खिलाफ कोई ऐक्शन न लिया जाए। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: क्या यह हिदायत रिकार्ड पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगर ऐसा फैसला हुआ था तो क्या यह रिकार्ड पर है?

चौ. मेहर सिंह राठी: रिकार्ड पर नहीं है। हमारे इंजिनियर–इन–चीज ने मुझे बताया था। (व्यवधान) स्पीकर साहब, जो कुछ मैं कहता हूं वह ठीक कहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान से मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हो तो कृपया शान्तिपूर्वक उस जवाब को सुनने की कोशिश करें। बीच मैं कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए (व्यवधान) आप जवाब से सहमत हों या न हों, यह मैं नहीं कहता लेकिन कृपया उस जवाब को शान्तिपूर्वक सुनने का कश्ट जरूर करें। उसके बाद कोई बात हो तो सप्लीमेन्टरी कर सकते हैं।

चौ. मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, कोई गलत बात नहीं है, जो मैं कहता हूं वह ठीक बात है। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 6 साल पहले एक बोर्ड बना था और चौ. देवीलाल जी की सरकार 2 साल 6 दिन इस प्रान्त में रही। उन्होंने एक भी फैक्टरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, मैं यह रिकार्ड की बात कह रहा हू लेकिन हमारी सरकार ने आते ही यह महसूस किया कि यह ठीक बात नहीं है, हमने 26 फैक्टरियों के खिलाफ अदालत में केस दायर करवाने की कार्यवाही शुरू कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, 50 ऐसी फैक्टरियां हैं जो बहुत ज्यादा खराब हैं जिसमें से 26 के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है और 17 फैक्टरियों को हमने 3 महीने का नोटिस दिया है कि वे अपना इन्तजाम ठीक कर लें, अगर वे अपनी हालत न सुधारेंगे तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 26 फैक्टरियों के खिलाफ कार्यवाही का पग उइाना कोई छोटी बात नहीं है। पिछली सरकार चौ. देवी लाल जी के नेतृत्व में रही, अगर उन्होंने किसी एक भी फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही की हो तो कोई मैम्बर साहब इस बारे में बता दें। स्पीकर साहब, इससे जाहिर होता हे कि उनकी नियत ठीक नहीं थी।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो सितम्बर 1979 का इजजाम था, उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा था (शोर) लेकिन कोई ठीस पग अीाी तक भी नहीं उठाया गया है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा था कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, वह हमने करके दिखाई है। लेकिन पिछली सरकार, जिसमें जैन साहब भी मंत्री थे, उन्होंने अपने दो साल के बकफे में इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, बार बार पिछली सरकार का हवाला दे रहे हैं हालांकि ये खुद भी उसी सरकार में मैम्बर थे। ऐसा कहकर कैबिनिट की ज्यायंट रिसपान्सीबिलिटी की ओथ को वे ब्रेक कर रहे हैं (शेम–शेम) स्पीकर साहब, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं ताकि चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी बात न करें जिससे एक ज्वायंट रिसपान्सीबिलिटी की ओथ ब्रेक हो। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं तो केवल सवा साल उस कैबिनिट का मैम्बर रहा, इस काम की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी तो केवल मुख्यमंत्री जी की थी अगर मुख्यमंत्री चाहते या सम्बन्धित मन्त्री चाहते तो इन फैक्टरियों के खिलाफ ऐक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी नियत ठीक नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी आपकी तरफ से विरोधी भाईयों को यह रिक्वैस्ट है कि जब कोई माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब दे रहे हों तो वे कृपाया शान्त रहे ताकि

उनका जवाब हमें भी क्लीयर सुन सके। शोर में हमें कुछ सुनायी नहीं देता।

Mr. Speaker: Surrender Singh Ji, please take your seat. Hon'ble Members, I always appreciate a little bit of light-hearted humour being injected into the proceedings of the House. But do not make everything to go too far. I entirely agree with what Sh. Surrender Singh has said. सहेबान मैं सभी आनरेबल मैम्बर्ज से यह रिक्वैट करूंगा कि जब कोई मामनीय मंत्री महोयद जवाब दे रहे हों तो आप कृप्या शान्त रहिये ताकि सबको उनका जवाब सुनने का मौका मिले। उसके बाद जो सप्लीमैन्टरी आप पूछेंगे उनके लिये मैं आपकी बोलने का पूरा मौका दूंगा। इस विशय में साहेबान, मैं आज सैकिन्ड रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

उप–श्रम मंत्री (चौ. लाल ंसिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत श्री मूल चन्द जी जैन जोकि हमारे एक बुजुर्ग साथी हैं से कहना चाहता हूं कि यह जो बोर्ड है, यह 19–9–74 को बना था और उस बोर्ड को केवल इसी सरकार ने ही टच किया, इससे पहले किसी भी सरकार ने इसको टच करने की हिम्मत ही नहीं की क्योंकि पिछले जो मुख्यमंत्री थे, उनके होते हुए किसी भी मंत्री की इस सकीम को टच करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। दो फैक्टरियों से हमने मनवा लिया है और बाकियों को इस बारे में नोटिस जारी कर दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय ने यह बताया कि कुछ फैक्टरियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय और शायद आपको भी इस बात का पता होगा कि जी.टी. रोड पर हरियाणा ब्रूवरीज है, और दूसरी तरफ सोनीपत में शूगर फैक्टरी है, दोनों ही सरकारी फैक्टरियां हैं। हरियाणा ब्रूवरीज की तरफ से जब हम निकलते हैं तो वहां से कई बार कार भी निकालनी मुश्किल हो जाती है और वहां बहुत ज्यादा बदबू मारती है, उस फैक्टरी का पानी निकालने का कोई इन्तजाम नहीं है क्योंकि सड़क के साथ काफी गन्दा पानी खड़ा रहता है, और उसके खिलाफ अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उधर दूसरी तरफ सोनीपत में जो शूगर फैक्टरी है, उसका पानी भी खेतों और नहरों में डाला जाता हैं, इससे खेती खराब होती है और जो पशु वगैरह उस पानी को पीते हैं उन्हें भी काफी नुक्सान होता है। क्या सरकार इस बारे में कोई शीघ्र ही कदम उठाने जा रही है ताकि इन फैक्टरियों के पानी का निकास ठीक ढंग से सही जगह पर हो और नहरों का पानी भी खराब न होने पाये और खेती को भी यह पानी नुक्सान न करें?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब मैं हाउस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक साल के अन्दर अन्दर इस प्रान्त में कोई ऐसी फैक्टरी नहीं होगी जिसका गन्दा पानी किसी नहर या कैनाल में पड़े और उस पानी के पीने से किसी भी इंसान या

पशु को कोई नुक्सान हो। इसका पूरा इन्तजाम एक साल के अन्दर–अन्दर कर देंगे।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके लिये सरकार क्या स्टैप उठा रही है?

चौ. भजन लाल: मैंने पहले बताया कि एक साल के अन्दर अन्दर इस प्रान्त में कोई ऐसी फैक्टरी नहीं होगी जिस के गन्दे पानी के किसी को नुक्सान होगा। इस बारे में हमने बहुत सारी फैक्टरियों के खिलाफ केस भी दायर करवा रखे हैं और कईयों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। अभी एकदम तो इस तरह का इन्तजाम करना कठिन है लेकिन फिर भी हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि फैक्टरियों का गन्दा पानी किसी कैनाल, किसी खेत वगैरह में न पड़े जिससे कि लोगों को नुक्सान हो।

चौ. हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आगे से जो नई फैक्टरियां बनेगी उनका गन्दा पानी निकालने के बारे में क्या सरकार पहले ही कोई स्कीम बना लेगी ताकि बाद में लोगों को किसी किस्म का नुकसान न हो??

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, फैक्टरी लगाने से पहले यह कैसे कहा जा सकता है कि इसका पानी कहां जाएगा लेकिन फिर भी सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि फैक्टरियों का

पानी किसी नहर खेत या किसी ऐसी जगह पर न डाला जाए जिससे पशुओं को नुक्सान हो या जहां से इंसान पानी पीते हों, वहां किसी किस्म का सेहत को नुक्सान हो।

चौ. राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया में बहुत से यूनिटस का गन्दा पानी सिंचाई की नहरों में अभी तक डाला जा रहा है और हमारे क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन उसकी वजह से खराब हो गई। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे यूनिटस के खिलाफ कितने समय के अन्दर अन्दर प्रोसीक्यूशन प्रोसीडिंगज शुरू की जाएंगी और इसकी वजह से जिन किसानों की जमीन खराब हो गयी है क्या उनको मुआवजा देने का सरकार विचार रखती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी फैक्टरियां जिनका गन्दा पानी कैनाल्ज में डालने की वजह से फसलें खराब होती हैं, या नुक्सान हुआ है और इन्सान की सेहत के लिये वह पानी नुक्सान करता है वहां हम तीन महीने के अन्दर अन्दर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देंगे।

Amount outstanding against Milk Centre, Rohtak

***1600. Dr. Mangal Sein**: Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state –

(a) whether any amount due to farmers and Harijans for the milk supplied by them is

outstanding against the Milk centre, Rohtak, if so, since when; and

(b) whether any application or memorandum has been received by the Government in respect of non-payment of outstanding amount referred to in part (a) above; if so, the date on which it was received together with the action taken thereon?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) जी हां। 14–3–80 को दूध उत्पादकों को 949739.15 रूपये दूध की कीमत के देय हैं। हरिजनों के लिये अलग आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

(ख) जी नहीं।

डा. मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो दूध उत्पादकों को पैसा देना है, यह कितने पीरियड का है?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, डा. साहब को यह रकम बहुत बड़ी नजर आती है इसलिये इन्होंने यह सवाल पूछा है। पेमैंट करने के लिये हमारा कायदा यह बना हुआ है कि 10 दिन के अन्दर–अन्दर उनको पेमैंट कर देते हैं। यह रकम जो दूध उत्पादकों को देय है यह 21–2–80 के बाद की है। वैसे हमारी अकेले रोहतक की एक हफ्ते की पेमैंट 5 लाख रूपए बनती है।

इसलिये यह सारी पेमैंट केवल 10–12 दिन की है इससे ज्यादा की नहीं है।

डा. मंगल सैन: मंत्री महोदय ने जवाब मे दिया है कि हरिजनों के अलग आंकड़े नहीं दिए जा सकते। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं दिए जा सकते?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने रोहतक के बारे में दूध की पेमैंट का जिक्र किया। क्या इसके नोटिस में यह बात है कि दूसरी जगहों पर भी लोगों की पेमैंट रूकी पड़ी है और इस वजह से वे लोग अपने दूध को डेरी में बेचने की बजाये प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी जगहों पर भी सुधार किया जाएगा?

ठाकुर बीर सिंह: वैसे तो इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह सवाल रोहतक के बारे में पूछा गया था। लेकिन फिर भी मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि सभी मिल्क प्लांटस के अन्दर पेमैंट करने में कितना सुधार हो चुका है। मिल्क प्लांट भिवानी में 29–2–80 तक की सारी पेमैंट क्लियर की जा चुकी है ओर 29–2–80 के बाद की कुछ पेमैंट बाकी रहती है। जीन्द मिल्क प्लांट में 21–1–80 से 29–2–80 तक 92 हजार रूपये की अदायगी की जा चुकी है ओर

1–3–80 से 10–3–80 तक 5 लाख रूपये पेमैंट डयू पड़ी है। इसके बाद अम्बाला मिल्क प्लांट आता है इसकी 29–2–80 तक की सारी पेमैंट क्लियर कर दी गई है उसके बाद की पेमैंट इन डयू कोर्स होती रहेगी। बल्लभगढ़ प्लांट की 29–2–80 तक की सारी पेमैंट क्लियर हो चुकी है और रनिंग पेमैंट चल रही है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पहले हमारे पास बैंकों की क्रेडिट लिमिट नहीं भी अब हमने हरियाणा स्टेट कोआप्रेटिव बैंक में दो करोड़ रूपए की क्रैडिट लिमिट कर दी है। अब रैगुलर पेमैंट चलती रहेगी।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि आम तौर पर 10 दिन के अन्दर पेमैंट कर दी जाती है क्या ये हाउस को विश्वास दिलाएंगे कि जिसको 10 दिन से लेट पेमैंट मिलेगी उसको उसका इन्ट्रैस्ट भी दिया जाएगा?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

Mr. Speaker: This is an unreasonable question.

चौ. पीर चन्द: स्पीकर साहब, अभी डा. मंगल सैन जी ने हरिजनों के बारे में पूछा। क्या डा. साहब की यह भावना तो नहीं थी कि वे हरिजनों की भैंसों का दूध न पीते हों इसलिये यह सवाल पूछा?

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, श्री पीर चन्द हाउस में बे सिर पैर की बात कर रहे हैं। (शोर)

चे. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर किसी हरिजन ने या किसान ने सरकार का पैसा देना होता है तो उसे बतौर लैंड रैवेन्यू रिकवर किया जाता है और उनको जेल की सलाखों में डालने के लिये सरकार तैयार रहती है। क्या मी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर किसान या हरिजन को उसके दूध की पेमैंट समय पर नहीं की जाती तो क्या सरकार उस रकम पर ब्याज देगी?

चौ. सतबीर सिंह: स्पीकर साहब मैंने भी तो यही सवाल किया था लेकिन उस वक्त आपने कह दिया कि यह अनरीजनेबल सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आपने यह कहा था कि सरकार अश्योरेंस दे कि दस दिन के अन्दर अन्दर पेमैंट हो जाएगी।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: नहीं, स्पीकर साहब, मैंने ब्याज के बारे में ही पूछा था।

Mr. Speaker: Then, I am sorry.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, इसके बारे में मैं बताता हूं। वैसे तो मंत्री जी ने बताया कि फरवरी के बाद किसी मिल्क प्लांट की कोई पेमैंट बाकी नहीं है लेकिन मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी की पेमैंट एक महीने से ज्यादा दिन तक बाकी रह जाएगी तो उस पर उसे अवश्य सूद दिया जाएगा।

Flying Club at Rohtak

***1550. Ch. Sant Kanwar**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start a flying club at Rohtak; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Club is likely to be started?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौ. गजराम बहादुर नागर):

(अ) जी, नहीं।

(ब) 'अ' के सम्मुख समय सीमा को निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं अपने गांव मांडोठी की एक बात बताना चाहता हूं कि जब सैकिण्ड वर्ल्ड वार हुआ था उस वक्त वहां, आई:एनःएः का कैम्प बना था। 1945 से लेकर आज तक वह जमीन सरकार के नाजायज कब्जे में है। हमने हर सरकार से गुजारिश की ि कवह जमीन किसानों को वापिस लौटा दी जाए ....

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आई.एन.ए. कैम्प का सिविल एविएशन से क्या सम्बन्ध है?

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, वहां पर मिल्ट्री का एयर पोर्ट बना हुआ है और सरकार जमीन का फसलाना देती थी लेनिक पिछले 20 साल से कुछ नहीं मिल रहा है ओर न वह जमीन किसानों को काश्त के लिये मिल रही है। जब लिखा पढ़ी होती है तो चिट्ठी आ जाती है कि यह मैटर डिफैन्स मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। 30 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और गांव का डैपूटेशन भी टाईम टाईम पर सरकार से मिलता रहा है। अब तो हमारा यही कसूर है कि हम यू.सन.ओ. में नहीं गए (हंसी) मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह जमीन कब तक किसानों को वापिस कर देंगे और उसका मुआवजा कब तक देंगे?

श्री अध्यक्ष: यह जमीन मिनिस्ट्री आफ डिफैन्स के पास होगी। उसका सिविल एविएशन से क्या ताल्लुक है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य का सवाल खूब अच्छी तरह से समझ गया हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तये यह है कि वह जो एयरस्ट्रिप बना हुआ है वह मिनिस्ट्री आफ डिफैन्स का है, स्टेट का नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी कोशिश की थी और मिनिस्ट्री आफ डिफैन्स के साथ नैगोसिएशन भी किया लेकिन उन्होंने हमारी प्रोपोजल रिजैक्ट कर दी। उसके बाद सिविल ऐविएशन डिपार्टमेंट हरियाणा ने रोहतक में एयरस्ट्रिप बनाने का निर्णय लिया। मैं रोहतक खुद गया था ओर मैं उसके लिये सोनीपत रोड पर साइट सिलैक्ट करके आया हूं।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र में आल इंडिया से पिलअग्रिमज आते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर हवाई पट्टी बनाने की कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, एयरस्ट्रिप्स तो हम हर बड़े टाउन में बनाने जा रहे हैं। कौन से जिले का कब नम्बर आएगा यह फण्डज की अवेलेबिल्टी पर डिपैन्ड करता है। जहां तक क्लब का सवाल है उसके लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट अब ऐनकरेजमेंट नहीं दे रही है इसलिये उनकी इजाजत के बगैर हम फलाइंग क्लब कहीं भी नहीं खोल सकते हैं।

चौ. राम किशन: अध्यक्ष महोदय, जीन्द के अन्दर फौरेस्अ डिपार्टमैंट का जंगल काट कर हवाई पट्टी के लिये साइट चुनी गई थी लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कब तक काम शुरू हो जाएगा?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, जीन्द के अन्दर कच्चा एयरस्ट्रिप बनाया हुआ है। वह खास कर इसलिये बनाया गया है क्योंकि सिविल एविएशन डिपार्टमैंट क्राप्स के ऊपर सप्रे का काम भी करता है। ऐसे कामों के लिये हमें टैम्परेरी एयरस्ट्रिप्स बनाने की जरूरत पड़ती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भिवानी के फलाइंग क्लब की कंस्ट्रक्शन का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं खुद उस क्लब का उद्घाटन करके आया था जिसके बारे में मैम्बर साहब को पता है मैंने उनको न्योता भी दिया था कि आप मेरे साथ चलें लेकिन शायद उनकी कोई अपनी मजबूरी थी जिसके कारण वे नहीं आ सके। वहां पर काम शुरू को चुका है। जो वर्क चल रहा है उसके बारे में मैं आपके नोटिस में ला देता हूं कि भिवानी क्लव के लिये टैक्नीकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की जरूरत है जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिये कुछ समय लगेगा। Construction work has already been started and the work is going on. जितना टाईम कंस्ट्रक्शन के लिये लगना है वह तो लगेगा ही।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने सवाल के पार्ट (ए) के जवाब में कहा कि 'नहीं' लेकिन बाद में सप्लीमेंटरी का जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद रोहतक में साइट सिलैक्ट करके आया हूं। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा जवाब ठीक समझा जाए?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कल्ब के लिये 'नहीं' कहा था। Sir, the question is about the flying club, not for the air strip.

चौ. संत कंवर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि फलाइंग क्लब के लिये सैन्ट्रल गवर्नमैंट से इजाजत लेनी पड़ती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करैंगे कि क्या हमारी सरकार ने और जगहों पर फलाइंग क्लब खोलने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, हम बाकायदा सैन्ट्रल गवर्नमैंट से नैगोसिएशन कर रहे हैं लेकिन प्रौब्लम यह है कि हवाई जहाज बाहर से लाने की कोई मन्जूरी नहीं मिली है।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक स्कीम आई थी और वह पेपर में भी आई थी कि हमारी हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में कुछ इम्पौर्टैन्ट जगहों को बाई एयर कनैक्ट करेंगे और इस स्कीम को कामर्शियल बना कर चलायेंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस स्कीम के तहत क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, यह स्कीम सरकार के जेरे गौर है। हम इसके बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट से भी नैगोसिएशन कर रहे हैं क्योंकि इसके लिये सैन्टर से परमिशन लेने की जरूरत है। हम यह इरादा जरूर रखते हैं कि इसको कौमर्शियल सर्विस बना कर चलाया जाए। इस स्कीम से सारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज को जरूर कनैक्ट करेंगे।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब अभी मंत्री जी ने बताया है कि विमान बाहर से मंगाए जाते हैं लेकिन मेरी सूचना यह है कि वे हिन्दुस्तान में ही बनते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सिविल एविएशन कल्ब के अन्दर जो विमान इस्तेमाल होते हैं वे बाहर से मंगाए जाते हैं या हिन्दुस्तान में ही बनते हैं? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि नैगोसिएशन से इनका मतलब खतोखिताब करने से है या जुबानी बात करते हैं?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने खतोखिताब नहीं यिका बल्कि हमारे एडीशनल चीफ सैक्रेटरी इस बारे सैन्ट्रल गवर्नमैंट से खुद डिस्कस करके आए हैं और लिख करके भी दे कर जाए हैं।

चौ. उदय सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि रोहतक में जो मिल्ट्री एयर पोर्ट बना हुआ है वह डिफैन्स का है। क्या इनके नोटिस में यह बात है कि वहां से करोड़ों रूपए की रोड़ी उठाकर ठेकेदार सड़कों पर डालने लग रहे है?

श्री अध्यक्ष: इस बात के बारे में आप अपने एम.पी. साहब को लिखें।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब स्टेट की करोड़ों रूपये की सम्पति जाया हो रही है इसलिये सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए।

Mr. Speaker: Hon. Members, Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Tehsildars/Naib Tehsildars in the State

***1515. Ch. Satvir Singh Malik**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the total number of Tehsildars/Naib Tehsildars in the State at present;

(b) the total number and names to Tehsildars/Naib Tehsildars out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes/Backward Classes together with their station of posting districtwise; and

(c) the number of Tehsildars/Nain Tehsildars referred to in part (a) above posted on the revenue side and on the other sides, i.e. accounts, agrarian reforms and recovery side etc., separately?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह):

(ए)	तहसीलदार	नायब तहसीलदार

	48	117

(बी तथा सी) विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

				नाम	नियुक्ति सीाान	जिला
(बी)	(i)	**तहसीलदार**				
		5–अनुसुचित जाति से सम्बन्धित	1.	श्री बिशना राम	तहसीलदार, नरवाना	जीन्द
			2.	श्री मुसदी लाल	तहसीलदार, रोहतक	रोहतक
			3.	श्री हरधूल सिंह भोंलें	तहसीलदार, महम	रोहतक
			4.	श्री मंगल राम	तहसीलदार, टोहाना	हिसार

				भगवाड़िया		
			5.	श्री राम स्वरूप	तहसीलदार, पलवल	फरीदाबाद

नोटः कोई तहसीलदार पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित नहीं है।

	(ii)	**नायब तहसीलदार**				
		18—अनुसुचित जाति से सम्बन्धित	1.	श्री गुरसेवा सिंह	नायब तहसीलदार, (लेखा) जगाधरी	अम्बाला
			2.	श्री रामजी लाल	नायब तहसीलदार (महाल) रायपुर रानी	अम्बाला
			3.	श्री श्याम लाल	नायब तहसीलदार	अम्बाला

				तंवर	(महाल) कालका	
			4.	श्री पूरन चन्द	नायब तहसीलदार (महाल) करनाल	करनाल
			5.	श्री राधे श्याम	नायब तहसीलदार (लेखा) करनाल	क्रनाल
			6.	श्री बालक राम	नायब तहसीलदार (महाल) गोहाना	सेनीपत
			7.	श्री कुन्दन लाल	नायब तहसीलदार (महाल) गोहाना	सेनीपत
			8.	श्री गनपत राय	नायब तहसीलदार	फरीदाबाद

					(महाल) होडल	
			9.	श्री डी.एम. ढालिया	नायब तहसीलदार (महाल) गुड़गावं	गुड़गावं
			10.	श्री सरदारी लाल	नायब तहसीलदार खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी कार्यालय, गुहला	कुरूक्षेत्र
			11.	श्री सन्त लाल	नायब तहसीलदार (महाल) रोहतक	श्रोहतक
			12.	श्री चेत राम	नायब तहसीलदार बवानी खेड़ा	भिवानी
			13	श्री बेद कुमार	नायब	जीन्द

					तहसीलदार (लेखा) जीन्द	
			14	श्री शिव राम	नायब तहसीलदार (अग्रे) नरवाना	जीन्द
			15	श्री रामपाल सिंह	नायब तहसीलदार (महाल) महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
			16	श्री लक्ष्मी चन्द	नायब तहसीलदार (महाल) बावल	महेन्द्रगढ़
			17	श्री नाथी राम	नायब तहसीलदार (महाल) नारनौल	महेन्द्रगढ़
	(ii)	**पिछड़े से सम्बन्धित**				
			1.	श्री महाबीर	नायब तहसीलदार	भिवानी

				प्रशाद	(अग्रे) दादरी	
			2.	श्री कन्यैया लाल	नायब तहसीलदार (अग्रे) भिवानी	भिवानी
			3.	श्री लालवन	नायब तहसीलदार (अग्रे) सिरसा	थ्सरसा

(सी)	(i)		
(ए)		महाल	41
(बी)		अन्य अर्थात कालोनाईजेशन ग्राम तथा आयोजना विभाग भूमि अभिग्रहण (सिंचाई) तथा गृह रक्षी विभाग।	
	(i)	नायब तहसीलदार	
(ए)		महाल	47
(बी)		लेखा	27
(सी)		भू–सूधार	24

(डी)		लाई / माई	5
(ई)		अन्य अर्थात कालौनी, भूमि अभिग्रहण, लोक निर्माण विभाग स्पैशल क्लैक्टर आदि।	9

नोटः (i) एक तहसीलदार पंजाब वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ii) 5 नायब तहसीलदार हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं टयूबवैल निगम, नगरपालिका रोहतक तथा भारतीय तेल निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(iii) इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित नहीं है।

"Pucca" Streets for Harijan and Bajigar Colonies in the State.

***1528. Sh. Bhagi Ram**: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state –

(a) whether any scheme has been formulated by the Government to maek "Pucca" streets of the

colonies of Harijans and Bajigars in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid scheme is likely to be implemented?

विकास मंत्री (राव राम नारायण):

(क) हरिजनों तथा बाजीगरों की बस्तियों के लिये विशेश तौर पर सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई हैं।

(ख) (क) के सम्मुख, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Sainik School at Jhajjar

***1701. Capt. Mange Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a SAINIK School at Jhajjar; and

(b) if so, the time by which the above said School is likely to be set up?

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) इस स्टेज पर इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

New Building of Government High School, Barwala

***1636. Sh. Jai Narain Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building for Government High School at Barwala; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be constructed?

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) जी हां। विद्यालय का नया भवन समान अनुदान योजना के अन्तर्गत निर्मित किया जाना है। सरकार इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख रूपए की धन राशि रिलीज करेगी बशर्ते कि तुल्य धन राशि जनता द्वारा एकत्रित कर ली जाती है। समान अनुदान जनता से अभी तक एकत्रित नहीं किया गया है। नये भवन के लिये भूमि भी नगरपालिका समिति, बरवाला द्वारा उपलब्ध की जाती है।

(ख) जनता से समान अंशधन प्राप्त हो जाने तथा सरकार नगरपालिका द्वारा भूमि सरकार को स्थानान्तरण करने के पश्चात नये भवन का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

Down Gradation of Schools in District Sirsa

***1623. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the schools upgraded by the Government when Ch. Devi Lal was the Chief Minister during the years 1977-78 and 1978-79 have been down-graded-

(a) Roopawas Primary School to Middle School, Sirsa.

(b) Gusaina Primary School to Middle School, Sirsa.

(c) Jamal Primary School to Middle School, and

(d) Chaharwala Primary School to Middle School, Sirsa, if so, the reason therefor ?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

वर्श 1977–78 में जब चौ. देवी लाल मुख्यमंत्री थे, अपग्रैड़ किये गये स्कूलों में से किसी को डाउन ग्रेड नहीं किया गया। तथापि, वर्तमान सरकार ने वर्श 1979–80 के पूर्व भाग में

अपग्रेड किये गये स्कूलों पर पुनर्विचार किया था और परिणाम स्वरूप असंतुलन को दूर करने हेतु कुछ स्कूलों को सितम्बर, 79 में डाउन ग्रेड किया गया था, क्योंकि बहुत से ऐसे विधान सभा क्षेत्र थे जहां से एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया था।

रा.प्रा.पा. रूपावास, गुसाइना तथा जमाल को असंतुलन दूर करने के लिये डाउन–ग्रेड किया गया था। तथापि, रा.प्रा.पा. रूपावास के हाउनग्रेडिंग के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा स्टे कर दिया गया था। राजकीय प्राथमिक पाठशाला चहरवाला डाउनग्रेड नहीं किया गया।

Production of Butter and Ghee in the Milk Plants

360. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state-

(a) the total production of Butter and Ghee in each Milk Plant of the State as on 31-3-1977 and 28-2-1980, separately together with their sale per kg. separately ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the production of Ghee and Butter; if so, the steps, if any, so far taken and the results thereof ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) प्रत्येक दूध संयंत्र पर 31–3–77 और 28–2–80 को घी व मक्खन का उत्पादन निम्न प्रकार है:–

संयंत्र	31.3.77 (किलोग्राम में)		28.2.80 (किलोग्राम में)	
	घी	मक्खन	घी	मक्खन
रोहतक			3400	2349
जीन्द	990	2440	3880	4385
भिवानी				
अम्बाला			280	
बल्लभगढ़				
छरें (प्रति किलोग्राम) उत्पादन	26.25 रू.	20.50 रू.	29.75 रू.	23.80 रू.

(ख) घी और मक्खन के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। इनका उत्पादन बाजार की मांग और दूध की उपलब्धि के कारण कम व

ज्यादा होता रहता है। इनका उत्पादन अन्य उत्पादनों जैसे बिना चिकनाइ वाले दूध का पाऊडर व पूर्ण चिकनाई वाले दूध पाऊडर की मांग पर भी निर्भर रहता है। नया दूध संयंत्र सिरसा में लगाया जा रहा है जोकि आगामी दो साल या कुछ अधिक समय के उत्पादन प्रारम्भ करेगा। जब यह दूध संयंत्र उत्पादन शुरू करेगा तो इसमें 3.5 टन घी तथा 1.5 टन मक्खन प्रतिदिन क्रमशः उत्पादन करने की क्षमता होगी।

Life Prisoners in the Jails of Haryana

361. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Jails & Dairy Development be pleased to state-

(a) the jail-wise total number of life prisoners, undertrials and other convicts in the Jails of Haryana at present, separately ; and

(b) the year-wise general remission given by the State Government to the life prisoners during the period from the year 1966-67 to 1979-80 (to-date) separately?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौ. शिव राम वर्मा): अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

(क)		जेल का नाम	आजीवन कारावास बन्दी	विचाराधनी बन्दी	अन्य बन्दी	कुल
	1	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	255	153	184	592
	2	जिला जेल, हिसार	252	197	123	572
	3	जिला जेल, रोहतक	184	128	51	363
	4	जिला जेल, भिवानी	88	43	33	164
	5	जिला जेल, करनाल	62	94	26	182
	6	जिला जेल, गुड़गांवा	43	75	29	147
	7	बोस्टल जेल, हिसार	58	18	16	92

	8	उप जेल, महेन्द्रगढ़		24	10	34
	9	उप जेल, पानीपत		17		17
	10	उप जेल, सोनीपत		23		23
	11	उप जेल, दादरी		11		11
	12	उप जेल, पलवल		41		41
	13	उप जेल, रिवाड़ी		18		18
	14	उप जेल, नारनौल		20	5	25
	15	उप जेल, सिरसा		90	3	94
	16	उप जेल, कैथल		34	3	37
	17	उप जेल, नरवाना		13		13

			943	999	483	2425

(ख)	वर्श	प्रदान की गई माफी	
	1966–67	6 माह	(सभी जेलो के लिये)
	1967–68	3 माह	(सभी जेलो के लिये
		1 माह	(बोस्टल जेल हिसार)
	1968–69	6 माह	(सभी जेलो के लिये)
		1 माह	(जिला जेल रोहतक)
	1969–70	शून्य	
	1971–72	शून्य	
	1972–73	शून्य	

	1973–74	12 माह	(सभी जेलो के लिये)
	1974–75	शून्य	
	1975–76	शून्य	
	1976–77	शून्य	
	1977–78	12 माह	(सभी जेलो के लिये)
		7 माह	(केन्द्रीय जेल अम्बला)
		7 माह	(जिला जेल हिसार)
		3 माह	(जिला जेल करनाल)
		5 माह	(जिला जेल रोहतक)
		6 माह	(जिला जेल गुड़गांवा)
		6 माह	(जिला जेल भिवानी)

		4 माह	(बोस्टल जेल हिसार)
		6 माह	(उप–जेल महेन्द्रगढ)
		4 माह	(उप–जेल सिरसा)
		6 माह	(उप–लेज नारनौल)
1978–79		5 माह	(जिला जेल गुड़गांवा)
		4 माह	(उप–जेल महेन्द्रगढ़)
1979–80		3 माह	(केन्द्रीय जेल अम्बला)
		3 माह	(जिला जेल हिसार)
		3 माह	(जिला जेल करनाल)
		5 माह 15 दिन	(जिला जेल रोहतक)
		3 माह	(जिला जेल

			गुड़गांवा)
		5 माह	(जिला जेल भिवानी)
		3 माह	(बोस्टल जेल हिसार)
		3 माह	(उप–जेल महेन्द्रगढ)

Capacity of each Jail in the State

362. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state the total capacity of each Jail in the State at present separately?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौ. शिव राम वर्मा):

राज्य में प्रत्येक जेल की अलग अलग वर्तमान कुल संख्या निम्न प्रकार है :–

1	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	986
2	जिला जेल, हिसार	700

3	जिला जेल, रोहतक	350
4	जिला जेल, भिवानी	180
5	जिला जेल, करनाल	119
6	जिला जेल, गुड़गांवा	350
7	बोस्टल जेल, हिसार	317
8	उप जेल, महेन्द्रगढ़	86
9	उप जेल, पानीपत	26
10	उप जेल, सोनीपत	31
11	उप जेल, दादरी	50
12	उप जेल, पलवल	14
13	उप जेल, रिवाड़ी	24
14	उप जेल, नारनौल	14
15	उप जेल, सिरसा	24
16	उप जेल, कैथल	30
17	उप जेल, नरवाना	60

चण्डीगढ़ में हरियाणा के अन्धे व्यक्तियों के साथ अभिकथित बल प्रयोग तथा दुर्व्यवहार पर चर्चा उठाने सम्बन्धी

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने काल अटैन्शन मोशन दी है और आपने

10.00 बजे

कहा था कि मोशन देने के बाद ही बात कर सकते हैं। कल शाम को यहां पर अन्धे लोगों ` प्रदर्शन किया था और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई .....(व्यवधान)

Mr. Speaker: Kindly give notice.

डा. मंगल सैन: मेरे पास नोटिस है, वही पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Nothing will be read out and recorded. मैंने रिपीटिडली आपसे रिक्वैस्ट की है कि काइंडली नोटिस दें। (व्यवधान)

डा. मंगल सैन: मेरे पास कापी आ गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: काल अटैन्शन मोशन एडमिट करने के लिये कम से कम एक घंटा पहले नोटिस आना चाहिए। मगर आध घंटा पहले भी आ जाए तो भी मैं एडमिट कर लूंगा।

चे. गंगा राम: स्पीकर साहब, क्या मेरा नोटिस भी एडमिट हुआ है? (व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब मैंने एडजर्नमैंट मोशन दी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जहां चार मैम्बर बोलने के लिये इकट्ठे खड़े होंगे तो कुछ भी रिकार्ड नहीं हो सकेगा। (व्यवधान) Therefore, one at at time please.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, अंधों के साथ जो कल व्यवहार हुआ है, उसके बारे में मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया हैं। (व्यवधान)

Mr. Speaker: It has not reached me.

चौ. राम लाल वधवा: आप अपने सैक्रेटेरिएअ से पता कर लें।

Mr. Speaker: Either you trust me or do not trust me. I have told you that I have not received it. (Interruptions) मैंने सैकेटरी साहब से पूछा है, इन्होंने बताया है कि अभी अभी दो मिनट पहले आपका नोटिस मिला है। I disallow it on the ground

that sufficient notice as required under the rules has not bee given.

मैम्बर साहेबान सैशन के दिनों में हमें ओवर टाईम काम करना पड़ता है और इस पीरियड में हम यहां होते हैं। कल जो यहो पर ब्लाइंड मैन का इंसीडैन्ट हुआ है, उसके बारे में आपके पास नोटिस देने के लिये 24 घंटे का टाईम था लेकिन किसी ने नोटिस नहीं दिया इस इंसीडैन्ट के बारे में मैंने यू.पी. अथौरिटीज से रिपोर्ट मंगवा ली है, मुख्यमंत्री से भी रिपोर्ट मंगवा ली है और स्टेट पुलिस से भी रिपोर्ट मंगवा ली है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो साहेबान इस इंसीडैन्ट पर ऐडजर्नमैंट मोशन या काल अटैन्शन मोशन देना चाहते हैं उन्होंने कोई तकलीफ गवारा नहीं की है। उन्होंने यह मुनासिब नहीं समझा कि नोटिस टाईम पर दे दिया जाए। मेरे पाास दो मिनट पहले नोटिस आया है, मैंने इसको डिसअलाउ कर दिया है। (व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने नोटिस आज दिया है, आप इसको कल के लिए कंसीडर कर लें।

Mr. Speaker: They why are you raising it now and wasting the time of the House? आप नोटिस को लेकर मेरे चैम्बर में आइए, मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग इस बात पर चाहता हूं कि आमतौर पर मेरे लोक दल के भाई और आम तौर पर सारे अपोजीशन के

मैम्बर लिखने से गुरेज करते हैं। जहां तक ऐडजर्नमैंट मोशन और काल अटैन्शन मोशन लिखने की बात है, वे लिख नहीं सकते, इसलिये उनको लिखने में ऐग्जम्पशन दे दी जाए क्योंकि लिखना–पढ़ता इसके बस की बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने लिख कर दिया हुआ है।

Mr. Speaker: Doctor Sahib, please take your seat. I will give due consideration to your calling attention notice.

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। (व्यवधान) चौ. गंगा राम जी ने जो कुछ अब कहा है वह न तो मैंने हाउस में सुना है और न ही रिकार्ड किया जाए। (व्यवधान) गंगा राम जी आप बैठ जाइए। आप सारे हाउस को डिस्टर्ब करते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं इस बातचीत का न तो हाउस नोटिस भेजा, न ही रिकार्ड किया जाएगा और न ही मैं कोई प्वायंट आफ आर्डर एन्टरटेन करूंगा।

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं * * * *

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): * * * *

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: * * * * आन ए प्वायंट आफर आर्डर। स्पीकर साहब, पार्लियामेंट में एक मिनअ में हाउस का खर्चा 900 रूपए बैठता हैं हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है, इसमें विधान सभा का खर्चा 900 रूपए पर–मिनट न लगाकर अगर 9 रूप्एपर–मिनट भी लगाया जाए तो 10 मिनट में 90 रूपए बैठता हैं चौ. गंगा राम जी कम से कम 10 मिनट हाउस का टाईम रोज जाया करते हैं, इसलिये हर रोज इनसे 90 रूप्ए वसूल किए जाएं।

Mr. Speaker: I will have to consider.

चौ. उदय सिंह दलाल: * * * *

चौ. संत कंवर: कोई इम्पोर्टैन्ट बात यह कोई बुरी बात, जो हाउस के बाहर घटित होती है, उसको हाउस में उठाने के लिए नोटिस दिया जाता है ओर आपको नोटिस इसलिए दिया जाता है कि जो बात हाउस से बाहर हुई है, वह आपके नोटिस में आ जाए और आप उस बात को सदन के नोटिस में लाकर सरकार का ध्यान उस घटना की तरफ दिलाएं। स्पीकर साहब, आपका यह कहना कि नोटिस समय पर नहीं दिया, ठीक नहीं क्योंकि यह बात आपके नोटिस में पहले ही थी, इसलिये नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। जो बात पहले से ही आपके नौलेज में है, उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। नोटिस देने का यही मतलब नहीं है कि मेरे नोटिस में बात आये। मेरे नोटिस में आने के बाद में गवर्नमैंट के नोटिस में लाता हूं क्योंकि गवर्नमेंट से जवाब–तलब करने की बात है। नोटिस के बगैर मैं कोई चीज इन्टरटेन नहीं करूंगा। (व्यवधान)

Dr. Mangal Sein: On a point of order, Speaker Sahib.

Mr. Speaker: No more point of order on this subject is allowed now. (Interruption)

जिला हिसार के चौधरीवास गांव में हरिजन लड़के के कत्ल के बारे

में कमेटी भेजने सम्बन्धी

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, यहां पर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि चौधरीवास गांव में हुए इंसीडैन्ट के बारे में तीन एम.एल.एज. की एक कमेटी बनाकर भेजी है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

क्या है? (व्यवधान) हाउस भी जानना चाहेगा कि उस कमेटी की फाईडिग्ज क्या है? (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, न तो हाउस की कोई कमेटी बनी है और न ही कोई औफिशियल कमेटी बनी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरीवास गांव में एक हरिजन का कत्ल हुआ था।

श्री कंवल सिंह: करवाया गया (शोर)

चौ. भजन लाल: आप लोग एम.एल.एज. हैं। आपको जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। (विघ्न) अगर यह बात साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना आप इस्तीफा दे दें। अध्यक्ष महोदय, चौधरीवास गांव मेरे हल्के में है। उसमें ांव के एक हरिजन का कत्ल हो गया। कुछ लोगों ने बहका कर उनको यहां बैठा दिया। (विघ्न) इस हाउस में यह बात पहले भी कही गई थी और मैंने पहले भी जवाब दिया था कि जिस आदमी ने कत्ल किया था उसको दफा 302 के तहत अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर कहा गया कि उसमें दो तीन मुलजिम और इनवैलव्ड हैं लेकिन उन सबको पकड़ा नहीं गया। मैंने इन्क्वायरी करवाई। एस.पी. वहां श्री लछमन दास हैं जो हरिजन जाति से ताल्लुक रखते हैं। वे मौके पर गए और डी.आई.जी. भी मौके पर गये। उन्होंने मौके पर तहकीकात की। (विघ्न एवं शोर)

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, यह जो कत्ल का मसला है इसकी मैरिट ओर

डिमैरिट पर कौमैन्ट करना टोटली रौंग है क्योंकि यह केस सबजुडिस है।

Mr. Speaker: Alright, no more discussion on this.

Shri Baldev Tayal: I have not yet completed, Sir.

Mr. Speaker: I have understood your point of order.

Shri Baldev Tayal: Before I completed my point ?

Mr. Speaker: I have catched your point. I will get the matter that has been raised be Ch. Kanwal Singh, M.L.A. examined. If there is anything on record, I will get it examined and take appropriate action, otherwise, on this point there will be no further discussion.

माननीय सदस्यगण मुझे श्रीमती सुशमा स्वराज की तरफ से अम्बाला छावनी में अचानक ऐपिडैमिक जौंडिस की बीमारी फेलने के मुताल्लिक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला है।

औचित्य प्रश्न –

सदन में धरना देने सम्बन्धी

चौ. गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: मेरी अनांउसमैंट के ऊपर?

चौ. गंगा राम: नहीं जी। मुख्यमंत्री जी चूंकि अन्धे व्यक्तियों के सात हुई ज्यादती के सम्बन्ध में जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। * * * * (शोर)

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

चौ. गंगा राम: फिर तो हम हाउस में धरना देते हैं। (शोर)

(इस समय सर्वश्री गंगा राम और संत कंवर ने हाउस में धना दिया।)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मिसबिहेव किया हैं। यह सारे हाउस की तौहीन है। मेहरबानी करके इसके खिलाफ एक्शन लीजिए।

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): स्पीकर साहब, इन लोगों ने यह तो तरीका अख्तियार किया कि अपनी सीटस से उठकर इस तरह से हाउस में बैठे, यह कटैम्पट आफ दी हाउस है। (शोर) Action must be taken against them for this.

श्री कंवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप सदस्यों का इस तरह से हाउस में बैठना कंटैम्पट आफ दी हाउस है तो ये जो बार बार सदन में झूठी बातें बताते हैं क्या वह कंटैम्पट आफ दी हाउस नहीं है? (विघ्न एवं शोर)

चौ. रामल लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, यह जो पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने फमाया कि मैम्बर्ज का अपनी सीटस से उठकर हाउस में धरना देकर बैठना कंटैम्पट आफ दी हाउस है, यह बात ठीक नहीं है। लोक सभा, पंजाब असैम्बली और दूसरी असैम्बलीज में भी इस तरह के प्रैसिडेन्टस हैं। कंटैम्पट आफ दी हाउस तो तब होता है अगर हाउस के मैम्बर्ज के खिलाफ कोई बात बोली जाए।

Mr. Speaker: This is no point of order. Please sit down.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मैं आनरेबल मैम्बर्ज से यह रिक्वैस्अ करता हूं कि वे हाउस की इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपसे यह भी रिक्वैस्ट करता हूं कि जो चेयर की तरफ से डायरैक्शंज होती है उनको फालो करने की कृपा करें। क्रिकेट में एक टर्म होती है 'हैट ट्रिक'। जो तीन विकेटस बराबर ले ले उसे 'हैट ट्रिक' कहते हैं। तो चोधरी गंगा राम जी दो दफा तो यह बात हो ली, तीसरी दफा के लिए मुझे मजबूर न करें। (विघ्न)

Ch. Khurshid Ahmed: Sir, my point remains unreplied. I wanted to know whether such a behavior that they should rise in their seats and then stage a dharna can be permitted in the House while it is in session and whether it constitutes a contempts of the House or not?

Mr. Speaker: I reserve my ruling. I will examine it and then give my ruling.

ध्यानाकर्शण सूचना–

अम्बाला छावनी में पीलिया की महामारी फेसने सम्बन्धी

श्रीअध्यक्ष: मुझे श्रीमती सुशमा स्वराज की तरफ से अम्बाला छावनी में अचानक ऐपीडेमिक जौंडिस की बीमारी फेलने के मुत्ताल्लिक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला हैं। मैं उसे मन्जूर करता हूं। आनरेबल मैम्बर कृप्या अपना नोटिस पढ़ दें और मंत्री महोदय उसका जवाब यदि आज देना चाहे तो दे दें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन का ध्यान हाल ही के और अत्यन्त लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर आकर्शित करना चाहती हूं कि हरियाणा के जिला अम्बाला के नगर अम्बाला दावनी में अकस्मात ऐपिउेमिक जौउिस का रोग भंयकर रूप से फेल गया है। ऐसा, वहां के पीने के पानी में कुछ गन्दे और बीमारी फेलाने वाले तत्वों के समावेश से हुआ है। पानी में कुछ ऐसी गन्दगी आई है कि उस पानी को पीने से अम्बाला छावनी के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है और प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति तो इस बीमारी की गिरफत में आ ही चुका है। साईन्स उद्योग के लिये पूरे देश में विख्यात हरियाणा के इस नगर में ऐसी नामुराद बीमारी का फेल

जाना बहुत गम्भीर चिनता का विशय है। ऐपिडैमिक जैंडिस गम्भीर मर्ज है जिसके कारण अनगिनत इन्सानों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अम्बाला छावनी निवासियों को इस बीमारी से छुटकाना दिलाने का प्रयत्न किया जाये और निम्नलिखित राहतें प्रदान की जायें :–

(1) पानी में कीटाणुनाशक दवाई डालकर फौरन पानी की शुद्ध करवाया जाए।

(2) वे लोग जो आज तक किसी तरह इस बीामरी से बचे रहे हैं उनको कोई प्रिवैन्टिव मैडिसिन दिलवाई जाये ताकि वे इस बीमारी की पकड़ में न आ पायें।

(3) इस बीमारी से जकड़े हुए लोगों को फौरन डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराई जाये।

(4) निर्धन मरीजों को सरकार की तरफ से पूरी खुराक व दवाईयां उपलब्ध कराई जायें।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, राहतें वहां जरूर दी जाएंगी लेकिन इसका डिटेल्ड जववाब में कल दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज 17 तारीख को चौ. हरस्वरूप बूरा के काल अटैन्शन *नोटिस नं. 18 के ऊपर इरीगेशन

एंड पावर मिनिस्टर साहब ने आज स्टेटमैंट देने के लिए कहा था। अब वे अपनी स्अेटमैंट दें।

वक्तव्य –

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा आम तौर पर राज्य के सूखा क्षेत्रों में तथा विशेशतया महम के 15 गांवों में तालाबों में पानी सूखने सम्बन्धी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, संजग्न सूची अनुसार मेहम क्षेत्र के विभिन्न गांवों के जोहड़ों को बहुत सी नहरों से भरा जाता हैं। इन जोहड़ो को समय समय पर गांव के नम्बरदार या ग्रांम पंचायत के सरपंच द्वारा लिखित मांग पर भरा जाता है। जैसे और जब भी मांग की गई है इन जोहड़ों को विशेश मोघों द्वारा नहर के पानी की सप्लाई की गई हैं। गांवों के जोहड़ों को नियम 17 (i) (ii) के अधीन भरा जाता है। जिसमें व्यवस्थित है कि उस गांव का नम्बरदार या सरपंच जिसके एक या अधिक जोहड़ों को नहर के पानी से भरा जाना हे, डिविजनल कैनाल आफिसर या सब डिविजनल कैनाल आफिसर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें जोहड़/जोहड़ों की संख्या, नाम तथा अंदाजन सामान्य लम्बाई चौड़ाई बयान करेगा ओर इस पर डिविजनल कैनाल आफिसर विशेश या सामान्य आदेश पारित करेगा कि जोहड़ों को किस समय ओर कितना भरा

जाना है जैसा कि डिविजनल कैनाल आफिसर अनुमोदन करेगा। हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट की इस आज्ञात्मक व्यवसाि के अन्तर्गत डिविजनल कैनाल आफिसर जोहड़ों को नहर का

* Call Attention-motion appears in Hvs Debates Volume 1, N. 12 dated 17-3-1980.

पनी देने के लिये विशेश मोघों की व्यवस्था करने के लिये सक्षम है तथा गांवों के जोहड़ों को भरने के लिये पानी की सप्लाई अविलम्ब उपलब्ध की जाती है।

Village Ponds of Meham area served by Causal Supply

Sr. No.	Name of village	Name of Channel from which supply was released for filling village pond	Date of supply of water for village pond	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Kheri Meham	Meham Minor	29-1-80	

	Nidana	Meham Minor	20-2-80	
	Ganga Nagar	Meham Minor	20-11-79	
	Kishangarh	Meham Minor	23-2-1980	
	Farmana Badashahpur	Meham Minor	21-2-80	
	Bhaini Chanderpal	Bhaini Chanderpal Minor	13-12-7 & 17-3-80	
	Bhaini Surjan	Bhaini Chanderpal Minor	11-12-79	
	Sisar	Behalba Minor & Bhiwani Disty	20-2-1980	
	Behlabas	Bhiwani Disty & Behlaba Minor	21-2-1980	
	Bhaini Bhairon	Behlaba Minor	22-2-1980	

	Meham	Behlaba Minor	28-1-1980	
	Basana	Dadri Feeder	24-2-1980	
	Matu Bhaini	Bhaini Bhairon Minor	23-2-1980	
	Madina	Mokhra Minor	25-2-1980	

चौ. हरस्वरूप बूरा: मंत्री महोदय ने बताया है कि स्पैशल मोघा मिल सकता हैं, इसका तो हमें पता है लेकिन एक्स. ई.एन. यह कह कर इन्कार कर देता है कि एक हफ्तें के लिये नहर आयी है और जमीदारों को खेती में पानी देने के लिये जरूरत है इसलिये स्पैशल आउटलैट तालाब भरने के लिये नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसान चिल्लाते हैं। इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश ळे कि क्या महीने में एक हफ्ते के लिये नहर चलायी जायेगी जिससे जोहड़ों में पानी दिया जा सकें।

चौ. मेहर सिंह राठी: जब भी किसी गांव से मोघे के लिये डिमांड आयी है, हमने जोहड़ों के लिय मोघे दिये हैं और इसके लिये तो कानून भी बना हुआ है।

श्री अध्यक्षः मेरा ख्याल है कि मवेशियों के लिये यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर जोहड़ों में पानी सूख जाये तो मैं भी सिफारिश करूंगा कि इरीगेशन महकमें को हिदायत करें कि जिस गांव के जोहड़ का पानी सूख गया है उसमें फौरन पानी दिया जाये। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): हमने पहले ही इन्स्ट्रक्शन दे रखी है।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री निमय 30 के अधीन प्रस्ताव पेश करेंगे।

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 20 माच्र 1980 को सरकारी कार्य किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 20 माच्र 1980 को सरकारी कार्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 20 माच्र 1980 को सरकारी कार्य किया जाए।

वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: अब साहेबान वर्श्र 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर डिस्कशन और वोटिंग होगी। पहले भी प्रैक्टिस रही है तथा हाउस का समय बचाने के लिय आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज फार ग्रान्टस एक साथ पढ़ी गई और पेश की गई समझी जायेंगी। आनरेबल मैम्बर किसी भी डिमान्ड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलते समय उस डिमान्ड का नम्बर बता दें जिसपर वे बोलना चाहते हैं। गिलोटीन एक बजे एप्लाई होगा।

That a sum not exceeding Rs. 12821670 for revenue expenditure and Rs. 1135914670 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 454924135 for revenue expenditure and Rs. 713801040 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 40339890 for revenue expenditure and Rs. 14139000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No.16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 311903550 for revenue expenditure and Rs. 15318000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 60658000 for revenue expenditure and Rs. 1135914670 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6977400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 34184650 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 200309660 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 22828000 for revenue expenditure and Rs. 72190100 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 432231500 for revenue expenditure and Rs. 76200000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 4279800 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 614697000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

मेरे पास श्री मूलचन्द जैन की तरफ से डिमान्डज न. 16 तथा 23 पर कट मोशंज आई है। वे भी पढ़ी तथा पेश की गई समझी जायेंगी तथा डिमांडज के साथ डिस्कस की जा सकती है।

Demand No. 16 (Industries)

1. **Sh. Mool Chand Jain**: That the Demand be reduced to Re. 1/-

Demand No. 22 (Transport)

2. **Sh. Mool Chand Jain**: That the Demand be reduced to Re. 1/-

श्री मूल चन्द जैन (समभालखा): स्पीकर साहब पेशतर इसके कि मैं आज पेश हुई डिमान्डज के बोर में अपने विचार रखूं, मै रूलिंग पार्टी के और अपोजीशन के मैम्बर साहेबान से कहना चाहता हूं कि हाउस में बहुत दफा पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर बात करनी चाहिए। जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं तो मैं पाट्री लाइन से ऊपर उठ कर बात करता हूं। स्टेट की जो भी समस्यायें हैं हमारी और उनकी अलग अलग नहीं हैं। वे सभी मुश्तरका हैं। स्पीकर साहब डेमोक्रेटिक सैट–आप में इस बात की आवश्यकता है कि रूलिंग और अपोजीशन ग्रुप अपनी स्टेट की समस्याओं को पहले रखें और अन्य चीजों को बाद में रखें। मैं कोई आपको नसहियत नहीं कर रहा हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह हम पर भी लागू होता है और आप पर भी लागू होता है। (विघ्न) आप इतनी इनफिरयरिटी कम्पलैक्स क्यों महसूस करते है।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। हम इनफिरयरिटी कम्पलैक्स महसूस नहीं करते। जो बातें

जैन साहब कह रहे हैं ये आपके चैम्बर में जाकर करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आुर आर्डर नहीं।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम न हो तो अपोजीशन के लीउर को रिकगनाइज क्यों किया जाये और क्यों उसे मंत्री जैसी सहुलियत दी जाये? यह कानून लोक सभा और दूसरी स्टेटस में भी है कि लीडर आफ दी अपोजीशन को रिकगनीशन दी जाती है। ये केवल इसलिये है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब इन कट–मोशन्ज पर जो मैंने दी है ओर जो डिमान्डज हाउस के सामने रखी हैं, उन पर अर्ज करना चाहता हूं। इन डिमान्डज पर जो कहना चाहता हूं उसको यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं सरकार की नुक्ताचीनी की गर्ज से कह रहा हूं। मिसाल के तोर पर हमारा जो एकाउंटिग सिस्टम है यानी जिस तरह से बजट के आंकड़े दिये गये हैं, मेरी राय में ये मुनासिब नहीं है। मैं यह नुक्ताचीनी केवल नुक्ताचीनी की गर्ज से नहीं कर रहा हूं। यह बात मेरे पर भी लागू होती है क्योंकि मैं भी दो बार हरियाणा में फाइनेन्स मिनिस्टर रहा हूं और आज के जो फाइनेन्स मिनिस्टर हैं उनपर भी वह लागू होती है। जब मैं फाइनेन्स मिनिस्टर था तो मैं भी उस कमी को न देख सका। एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है उसी के मुताबिक काम

चलता रहा है। अब जो मैं हाउस को सुझाव दे रहा हूं उसको एग्जामिन करवा कर, अगर सुझाव स्वीकार करने योग्य हो तो स्वीकार करें। मैं ये बातें नुक्ताचीनी की गर्ज से नहीं बल्कि सहुलियत की गर्ज से कह रहा हूं।

स्पीकर साहब, मैं एक तो बजट प्रेजेन्टिग के मैथड़ के बारे में कहना चाहता हूं। जितनी भी हमारी डिमान्डज हैं नकी एक किताब है जिसको ''डिमान्डज फार ग्रान्टस विद डिटेल्ज आफ एस्अीमटस आन एक्सपैन्डीचर'' कहते हैं। सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी डिमान्ड ले लीजिए उसमें वोटिड ओर चार्ज्ड अमाउन्अ दिया हुआ है। जैसे आप इन्डस्ट्री की डिमान्ड नम्बर 16 ले लीजिएं इसके अन्दर वोटिड में प्लान एक्सपैन्डीचर कितना है और नान–प्लान एक्सपैन्डीचर कितना है। अलग अलग नहीं दिया है अब स्पीकर साहब, प्लान एक्सपैन्डीचर और नान–प्लान एक्पैन्डीचर को देखने के लिये इतनी मेहनत करनी पड़ती है जिसका कोइ ठिकाना नहीं। जब इनके पास आंकड़े तैयार है तो ये हर आइटम के सामने दे सकते हैं कि नान–प्लान में इतना खच्र है और प्लान में इतना खच्र है। बड़ी आसानी से दे सकते है। हां इसमें शायद फाइनेन्स मिनिस्टर और उसके एडवाइजर सैक्रेटरी वगैरह यह कह सकते है कि सदस्यों को भी तो मेहनत करनी चाहिए जैसे कि आप फरमाया करते है कि होम टास्क करो तो कुछ और चीजों का भी पता लगेगा। स्पीकर साहब यह जरूरी इसलिये है कि नान प्लान एक्सपैन्डीचर बढ़ता रहता है

लेकिन जाो प्लान एक्सपैन्डीचर है उससे डिवैल्पमैंट के काम होते हैं। अगर प्लान और नान–प्लान को अलग अलग नहीं दिखाते हैं तो प्लान एक्सपैन्डीचार जो डैडवेट होता है, वह बढ़ता रहता है और प्लान एक्सपैंडीचार का भी चालीस प्रतिशत काउन दि ड्रेन जाता हैं फिर विकास के कामों को बढ़ावा कैसे हो। कई दफा हम कम्पैरीजन करते हैं जैसे कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बजट बहस के जवाब में अपनी स्पीच में कहा है कि एग्रीक्लचर में, इरीगेशन में, एजुकेशन में पैसा बढ़ा दिया है। वास्तव मे यह पैसा बढ़ा है या नहीं, इसका कोई पता नहीं चलता है क्योंकि जो नान–प्लान एक्सपैंडीचर है उसमें आइटम्ज की बढ़ौतरी होती रहती है जिसके कारण से स्टेट की डिवैलपमैंट के लिए रूप्या कम रह जाता है। इसलिए डिमान्डज की अमाउन्टस के साथ साथ प्लान व नान प्लान खर्चे अलग अलग दिए जायें। दूसरा सुझाव टूरिज्म की मांग नम्बर 24 के बारे में देना चाहता हूं। अगर फाइनेन्स मिनिस्अर साहब उस मांग को गौर से देखें तो उसमें दो डिपार्टमेंटस हैं। एक हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन है और दूसरा टूरिज्म डिपार्टमैंट दोनों का हमारे सामने जब तक पूरा नक्शा न हो तो कुछ पता नहीं चलता। हमें पता होना चाहिये कि हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन क्या कर रही है और डिपार्टमैंट क्या कर रहा है। दोनों अलग न होने से कन्फयूजन पैदा होता है। आठ–साल डाकूमैंटस हैं इनमें हम लोग वहां तलाश करते रहे। मैं खासतौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से टूरिज्म कार्पोरेशन है इसी प्रकार से और भी बहुत सी कार्पोनेशंज हैं उनका हिसाब

किताब, मुनाफा नुक्सान हाउस के सामने बजट के साथ–साथि रखा जाना चाहिये। (**इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदसय श्री कन्हैया लाल पोसवाल पदासीन हुए**) जिस प्रकार गवर्नमैंट आफ इंडिया की जितनी भी अन्डरटेकिन्गज हैं सबकी बैलेन्स सीट हाउस में रखी जाती हैं उसी प्रकार से यहां भी रखी जानी चाहिए। ताकि हम देख सकें कि यह कार्पोरेशन स्टेट को फायदा कर रही है या सफेद हाथी है। खर्चा ही खर्चा कर रही है या कुछ फायदा भी हो रहा है।

एक और बड़ी कमी मेरे नोटिस में आई है। मुझे गलती लगी हो तो फाइनेन्स मिनिस्टर बता दें। चेयरमैन साहब एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम आन दी बजट के सफा 17 पर लिखा है कि 65 लाख रूप्या टूरिज्म डिपार्टमैंट पर खच्र होगा लेकिन जो आज हमारे सामने डिमान्ड है वह केवल 42 लाख रूप्ये की हैं। मैंने भी काफी होम वर्क किया परन्तु इस साढ़े 22 लाख रूप्ये का पता नहीं चल पाया कि वह कहां से पूरा करेंगे। मैं अपनी भी इसमें कमी मानता हूं क्योंकि मैं दो बार फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुाक हूं लेकिन मुणे इन आंकड़ों का पता नहीं लगता था। इसलिए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपने एडवाइजरों से पूछ कर बतायें कि यह कहां से पूरा करैंगें। वैसे तो यह बहुत जरूरी था कि पहले ही पता होता क्योंकि मैम्बर साहेबान ने कोई टीका–टिप्पणी करनी हो तो वे नहीं कर पायेंगे। इसलिए इन बातों का साफ तौर पर लिखा होना चाहिये। इसी तरह से इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट हैं। प्लान स्कीम

मेमोरन्डम के पेज 101 पर देखें तो पता चलेगा कि कैपिटल ले–आउट आन विलेज एंड स्माल स्केल इन्डस्ट्री के पार्ट वन में 19 लाख 71 हजार 2 सौ रूप्या रखा है और पार्ट दो में 2450800 रूपया रखा है और दोनों को मिलकर 4422000 बनता है परन्तु पार्ट थ्री में दोनों को मिला कर 5025000 कर दिया है।

चौ. रिजक राम: चेयरमैन साहब यह जो बजट की किताब है, यह किस तरह से तैयार होती है, क्या कर रहे हैं और क्या क्या इसमें कमियां हैं इसका जवाब देने में ही लीडर आफ दी अपोजीशन ने काफी समय ले लिया। वे खुद फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं। इनकी उस वक्त समझ में नहीं आया तो अब भी समझ में नहीं आयेगा। ये बाद में चैम्बर में बैठ कर वित्त मंत्री महोदय से या कमिश्नर से डिस्कस कर लें तो अच्दा रहेगा। इनकी यहां पर समझ में नहीं आयेगा।

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब असल में चौ. रिजक राम बाज दफा नान–सीरियस हो जाते हैं, उनके नान–सीरियस होने की यह एक मिसाल है। मैं उनका शुक्रगुजार हूंगा, अगर वे इसको एक्सप्लेन कर दें क्योंकि उनका बोलने का नम्बर भी मेरे बाद ही आने वाला है।

चेयरमैन साहब मैं टूरिज्म कार्पोरेशन और टूरिज्म डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। डिमांड पर इस आंकड़ों से जाहिसार होता है कि टूरिज्म डिपार्टमैंट ने नान–प्लान

स्कीम के अन्दर बड़खल झील पर वर्श 1979–80 तक 105 लाख रूप्ये खर्च किये, सूरजकुन्ड पर 57 लाख, पिंजौर पर 53 लाख, ऊचाना पर 46 लाख, पीपली कप्पलैक्स पर साढ़े तेरह लाख ओर पानीपत पर सवा तेरह लाख रूप्ये खर्च किये हैं। यानी कुल मिलाकर दस करोड़ 62 लाख यप्या इन सारे टूरिज्म कम्पलैक्स पर खर्च किया है और इनसे आमदनी नहीं के बराबर है। कुल एक लाख रूप्ये दिखाए हैं। अब 11 लाख रूप्या फरनीशिंग के लिए मांग रहे हैं। बहुत से तो पहले ही फरनिश्ड हैं लेकिन 35 कमरे रह गये है उनको फरनिश्ड कराना है और एक दो रेस्टोरेन्ट हैं उनको भी फरनिश्ड करना है लेकिन कमाई वहां से कुछ हो नहीं रही है। कुछ कमाई इन्होंने एक लाख रूपया दिखायी है। अगर गलती हो तो चौ. रिजक राम या फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जवाब दे दें। चेयरमैन साहब कहा जा सकता है कि हरियाणा में जो टूरिज्म डिपार्टमैंट के कम्पलैक्स बनाये हैं वे बड़े अच्छे हैं। उन पर हम आप गौरव अनुभव करते हैं कि इस डिपार्टमैंट ने हरियाणा की शोहरत बढ़ाइ हे लेकिन दु:ख तो इस बात का है कि ये टूरिस्ट कम्पलैक्स किसको सर्व करते है। यहां पर कहा जाता है कि दिल्ली से और चारों तरफ से बहुत लोग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से और चारों तरफ से बहुत लोग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिली से कोई आदमी इन कम्पलैक्स में नहीं जाता है जो पावर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनकी आबादी शहरों में चालीस फीसदी है और गांवों में 48 फीसदी है इसलिये उन गरीब लोगों द्वारा इन कम्पलैक्स का फायदा उइाने का तो

कोई सवाल ही नहीं है लोअर मिडिल क्लास वाले भी वहां नहीं जा सकते। अगर कोई अमीर आदमी दिल्ली की आबोहबा से तंग आकर बड़ाल या सोहना लेक पर जाता है तो उसको पूरा पे करना चाहिये। जब वह दिली के अशोका होटल में सौ–दो सो या पांच सौ का कमरा लेकर रह सकता है तो फिर हरियाणा के अन्दर दो–चार या दस रूप्ये में कमरा क्यों ले? इस चीज का टूरिज्म महकमा क्यों नुक्सान उठाता है। लाखों रूप्या टूरिज्म कार्पोरेशन नुकसान का भरती है। टूरिज्म डिपार्टमैंट, कार्पोरेशन को एक लाख 80 हजाार रूप्या ग्रान्अ दे रहा है और दो अढ़ाई लाख टूरिज्म कार्पोरेशन कज्र के रूप में ले रही है। इन सारे के सारे कम्पलैक्सिज का खच्र तो टूरिज्म डिपार्टमैंट को करना पड़ता है। पहले टूरिज्म डिपोर्टमैंट बनता है और फिर उसको कार्पोरेशन को हैंडओवर कर देता है। जब हम टूरिज्म कार्पोरेशन से पूछते हैं, क्या पोजीशन है तो वे कहते है कि नो–प्रौफिट नो–लौस पर चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप तो चला रहे हो, लेकिन यह घाआ किसको होगा? यह सारा घाआ हमारी स्टेट को होगा। इसलिए जो टूरिज्म आयें यह सारा खर्चा उन पर डालिए। टूरिज्म कार्पोरेशन घाटे में चल रही है उसको टूरिज्म डिपार्टमैंट कर्जा देता है, ग्रान्ट देता है और सुविधाये देता है फिर भी घाटा क्यों उठायें। इसलिए इस चीज को खासतोर पर चैक किया जाये।

श्री सभापतिः इस मामले में जो आंकड़े है, वे तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ही बतायेंगे लेकिन बाबू जी मैं आपको

यह बताना चाहता हूं कि हमारी टूरिज्म कार्पोरेशन हिन्दुस्तान की बेहतरीन कार्पोरेशन्ज में से एक है। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह घाटे में नहीं है। तीसरी बात जो आपने यह कहा कि अमीरों के लिये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर गरीब आदमियों के बच्चे भी जाते हैं। वे उसी एन्वायरनमैंट को एन्जाय करते हैं जिसको दूसरे लोग एन्जाय करते हैं। उनको भी वैसे ही रखा जाता है जैसे कि अमीरों को।

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, टूरिज्म कार्पोरेशन में कितनी इन्वैस्टमैंट हुई है, उसके आंकड़े तो फाइनेन्स डिपार्टमैंट ही बतायेगा लेकिन जो आंकड़े मुझे पता लगे हैं वे, यहां पर आईटम न. 9 हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन के सामने दिये हुए हैं, वे ये हैं कि 1975–76 में 5 लाख 46 हजार रूपये का घाटा हुआ हइै 1976–77 में 5 लाख 48 हजार रूपये का घआ हुआ है और 1977–78 में 3 लाख 28 हजार रूपये का घाटा हुआ है। 1978–79 और उसके बाद के आंकड़े इसमें नहीं दिये गये है। जितने आंकड़े यहां पर दिये गये हैं, वे मैंने बता दिये हैं। चेयरमैन साहब, यह जो घाटा हुआ है, इसमें मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहता क्योंकि मैं भी इसके लिये जिम्मेवार हूं। मैं अकेले फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को या इस सरकार को इसके लिये जिम्मेवार नहीं ठहराता। लेकिन मैं गुनार मृडाल इकोनौमिस्ट की यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के पढ़े लिखे धनवान या ईलाइटस इतने विलासी हो गये हैं कि वे बात तो समाजवाद की

करते हैं लेकिन जब कोई गरीब के भले की बात आती है तो उसमे ंरोड़े अटकाते हैं और सब खर्चे अपने आराम के लिये करते हैं। चेयरमैन साहब, मैं भी ऐसे लोगों मं शामिल हूं। आप सब भी उसमें शामिल हैं और अफसरान भी उन ईलाइटस में शामिल है।

श्री दीप चन्द भाटियाः हमारे मूल चन्द जैन साहब, एक बड़े आनरेबल मैम्बर हैं और बड़े बुजुर्ग नेता है। ये अपने आपको तो उनमें शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे शामिल नहीं कर सकते।

श्री मूल चन्द जैनः वह अगर उनमें शामिल न होना चाहें तो न हों, मेरी तरफ से उनको इजाजत है। वे अकेले ही लाईन से अलग खड़े होना चाहते है तो बेशक हो लें। मैं बार बार इस हाउस में वही कहता हूं जो एक मशहूर इकौनोमिस्ट श्री गुनार मृडाल ने कहा है कि हिन्दुतान का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर ईलाइटस समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन जब कोइ गरीबों के भले की बात आती है, गवर्नमैंट कोई उनके भले के लिये कदम उइाने की बात करती हे तो वे इलाइटस बीय में तरह–तरह के रोड़े अटकाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे अस्पतालों में मरीजों के लिये दवाईयां नहीं हैं, उनके लिये पट्टियां नहीं हैं, स्कूलों में बच्चों के लिये टाट का इन्तजाम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम टूरिज्म कार्पोरेशन आदि में घाटे पर घाटा उठाते जा रहे हैं। मैं जब फाइनेन्स मिनिस्टर था, तो मैंने एजूकेशन सैक्रेट्री से कहा था कि आप बच्चों के लिये टाट्स का

प्रबन्ध करवाओं, जितने भी पैसे की जरूरत होगी, मैं दूंगा। मुझे खुशी हुई जब श्रीमती शान्ति राठीक ने यहां पर यह बताया कि उनके लिये टाट का प्रबन्ध करने का फैसला हो गया है। अभी वह इम्पलीमैंट होगा या नहीं यह तो बाद की बात है। हमारे हरियाणा में कितने हजार प्राईमरी स्कूल हैं जहां पर छोटे–छोटे 6–6, 7–7 और 8–8 साल के बच्चे जब अपना बस्ता उठाकर चलते हैं तो अपने साथ वे एक टाट या बोरी का टुकडा भी ले जाते है। देखिये, एक तरफ तो हमारे यहां हालत यह है कि स्कूलों में टाट का भी प्रबन्ध नहीं है और अस्पतालों में अगर कोई बीमार चला जाये या जख्मी हो जाये तो उसके लिये दवा दारू या पट्टी तक का प्रबन्ध नहीं है और दूसरी तरफ हम अमीरों के लिये यह फिजूलखर्ची कर रहे हैं और यह फजूलखर्ची भी हम वहां पर करें, जैसे टूरिज्म कम्पलैक्सिज बनाकर उन लोगों को दें जो कि सिर्फ ईलाइटस हैं, सिर्फ उन लोगों के फायदे के लिये फिजूलखर्ची करें जैसे एम.एल.एज. हैं या मिनिस्टिर हैं या अफसर हैं या ईलाइटस हैं। अगर हम इस प्रकार पैसा खर्च करते जायें तो यह फिजूलखर्ची नहीं तो और क्या कहेंगे?

अब मैं इंडस्ट्रीज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन के मौके पर भी मैंने इसके बारे में कहा था। अब कुछ आंकड़े मुझे मिले हैं क्योंकि मैंने इसको जरा डिटेल में एग्जामिन किया है। वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चेयरमैंन साहब, जो ज्वायंट सैक्टर में इंडस्ट्रीज लगाई

हुई हैं, उनमें हमारी स्टेट की इन्वैस्टमैंट लगभग डेढ़ करोड़ रूपया हैं। ज्वायंट सैक्अर में जो इंडस्ओज लगी हुई हैं, उनकी हैल्प करने के लिये यानी शेयर कैपिटल के नाम से या पता नहीं किस–किस तरह से इतना पैसा हमारा इनके अनदर लगा हुआ है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन बनी हुई हैं, हमने यह पैसा उस कार्पोरेशन को दिया हुआ है और इसके अलावा 30 लाख रूप्या हम इस बजट द्वारा और देंगे ताकि वे इनमें लगा सकें। हम वर्श 1967–68, 1969–70 से लेकर 1978–79 तक एक करोड़ 76 लाख रूपया ज्वायंट सैक्टर के लिये दे चुके हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से यहा पैसा इन ज्वायंट सैक्टर अन्डरटेकिंज को दिया जा चुका है। हरियाणा में ऐसी कुछ 23 कन्सर्न्ज है। यह जवाब महकमें का दिया हुआ है जो मुझे पब्लिक अन्डरटेकिंज कमेटी का एक सदस्य होने के मिला था। इन 23 में से 3 कन्सर्न्ज हमने पब्लिक सैक्टर में ले ली हैं वे हैं हरियाणा ब्रूवरीज, हरियाणा कौन्कास्ट लिमिटिड और हरियाणा टेनरीज लिमिटेड। 26 लाख रूपया हमारा इनमें लगा हुआ हैं। डेढ़ करोड़ रूप्या हमने प्राईवेट कम्पनियों को दिया हुआ है और यह पैसा प्राईवेट कम्पनी वालों को इसलिये दिया है क्योंकि अगर हम उन्हें यह पैसा नहीं देते तो हमारी स्टेट इन इंडस्ट्रीज से महयम रह जाती। इसके लिये 30 लाख यप्या इस बजट में और मांगा गया है। आप देखें अगर यह 30 लाख यप्यो ओर एड कर दिया जाये तो हमारी कुल इन्वैस्टमैंट 2 करोड़ के करीब बन जाती है। जहां तक इस पैसे की रिटर्न का ताल्लुक है आपने यह देखा होगा कि

शायद ही कभी सूद के तौर पर किसी कन्सर्न से पैसा आया हो? मेरे ख्याल में तो कभी आया नहीं है, यदि कभी आया भी होगा तो 10, 15 या 20 हजार रूपये से ज्यादा नहीं आया होगा। पिछले 10 वर्शो से डेढ़ करोड़ रूप्ये की हम इन्वैस्टमैंट कर चुके हैं लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि हमने जो यह डेढ़ करोड़ रूपए की इन्वैस्टमैंट की हुई है, इसको वापिस ले लेना चाहिए। इसी तरीके से इस डिमान्ड में एक करोड़ 8 लाख रूप्या हमने मांगा गया है कि हम इस पैसे को हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन के लिये दें ताकि कार्पोरेशन आगे और पब्लिक सैक्टर में यूनिटस लगा सके। इस कार्पोरेशन ने पहले से ही जो 7–8 प्रौजैक्टस लगाये हुए हैं, उन प्रौजैक्टस की हालत के बारे में मैं तफतीस में नहीं जाना चाहता क्योंकि दूसरे मैम्बर साहेबान भी बहुत उतावलले हो रहे हैं कि मैं जल्दी खत्म करूं क्योंकि उन्होंने भी बोलना है लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि दो–तीन पब्लिक अन्डरटेकिंज को छोड़ कर बाकी सबकी सब घाटे में चल रही है। उनकी बहुत खराब हालत है। जब हम उन वजुहात में गए कि क्यों इनमें घाटा हो रहा है जबकि सीनियर आई.ए.ए. अफसर यहां पर एम.डी. और चेयरमैन लगे हुए है, तो एक बात जो हमें समझ आयी वह यह है कि एक तो आई.ए.एस. अफसर को एक कार्पोरेशन में 5–6 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देते। वह तो पोलीटिकल लैवल की बात है। मैं भी उसके लिये जिम्मेवार हूं क्योंकि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर भथा उस समय भी ऐसी ही हालत थी। मैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर

तो इसके लिये जिम्मेवार नहीं था लेकिन क्योंकि मेरे जमाने में भी वही हालत थी, इसलिये मैं भी इसके लिये जिम्मेवार हूं। हमारी जो पब्लिक अन्डरटेकिंज कमेटी है उस कमेटी में कार्पोरेशन्ज के एम.डीज. से और चेयरमैनों से बातचीत हुई है। बातचीत से हमें यह मालूम हुआ कि कितने ही चेयरमैन ओर एम.डीज. ऐसे लगा दिए जाते हैं और उनकी रूचि नहीं देखी जाती। इसलिये मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के अलावा हमारा इन कार्पोरेशन्ज में 60—70 करोड़ रूप्ए के करीब लगा हुआ है हमें, सबसे पहले जो अफसर वहां पर लगाते हैं, उसकी रूचि देखनी चाहिए कि बिजनैस के मामले में उसकी यचि हे भी या नहीं। अंग्रेज के जमाने के चीफ सैक्रेटरी की यह डियूटी होती थी कि वह अपने सीनियर अफसरों के स्वभान को, उनके रूझान को देखे और यह पता लगाये कि उनका रूझान किस तरफ है। ओवर ए पीरियड आफ ईयर्ज यह पता लगाया जा सकता है। कि किसकी रूचि किस तरफ है। एक अफसर अगर एक अच्छा खिलाड़ी है या अच्छा फौजी है, अगर उसको बिजनैस में डाल देंगे तो वह कैसे काम कर सकेगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों को एक कार्पोरेशन में तीन वर्श का मौका दिया जाना चाहिए। जब हम जिम्मेवारी किसी की फिक्स करना चाहते हैं तो ऐसी हालत में किसी की भी हम जिम्मेवारी फिक्स नहीं कर सकते। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें पार्टी लाईन्ज से ऊपर उइकर यह बात सोचनी चाहिए कि इनके घाटे को कैसे प्रौफिट में बदला जा सकता है। (व्यवधान) पहले तो

इस सरकार को तीन–चार महीने ट्रान्सफर्ज में लग गए। जुलाई के आखिर में तो इनको पता ही नहीं था कि ये टिक भी सकेंगे या नहीं। सितम्बर के सैशन के बाद इनको पता लगा कि शायद हम स्टिक कर जाएं लेकिन उसके बाद ये ट्रांसफर्ज में उलझ गए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब तो आप जरा ध्यान से इस बात को ऐग्जामिन करें। चेयरमैन साहब अब मैं एक बात सम्भालखा के बारे में कहना चाहता हूं और यह बात ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित है। मैं विस्तार से ट्रांसपोर्ट महकमें को एग्जामिन नहीं कर रहा हूं। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सम्भालखा में बस स्टैंड बनना था और करन्ट ईयर के बजट में उस बस स्टैंड के लिये पचास हजार रूप्ये प्रोवाईड किया हुआ है। चेयरमैन साहब, आज 19 तारीख हो गई है और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने में बारह दिन रह गए हैं। मुझे पता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस काम में दिलचस्पी ली है लेकिन मेरी और से बहुत तेजी से लिखाई पढ़ाई करके इस केस को परसू करने के बावजूद ट्रासपोर्ट डिपार्टमैंट टस से मस नहीं हुआ है। (व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): बाबू जी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।

श्री मूल चन्द जैन: जो कुछ आपने कहना है वह मैं ऐन्टीसिपेट कर सकता हूं। आपने यह कहना है कि उस जगह का झगड़ा हे जहां पर यह बस स्टैण्ड बनना है। चेयरमैन साहब मैं कहना चाहता हूं कि वह जगह न मेरी है और न सिकी और की

है। वह जगह स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. ओर सेन्ट्रल पी.डब्ल्यू.उी की हैं। वहां पर बस स्ट्रैउ बनाने में सिी को क्या ऐतराज हो सकात है। चेयरमेन साहब, होता यह हे कि जो दुकानदार वहां पर बैठे हैं उनमें से एक दुकानदार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट वालों को कुछ कह देता हैं और दूसरा कुछ दे देता है। चेयरमैन साहब, कह क्या देता है सब लोगों को पता है कि क्या होता है। मेरा यहां कहना शोभा नहीं देता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के लोग कितने लापरवाह हैं कि मिनिस्टर के हुक्म को भ नजरअन्दाज कर दिया जाता है। चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं हैं इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

चौ. रिजक राम (राई): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नम्बर 17 जो एग्रीकल्चर से सम्बन्धित है तथा इससे मुतहदा डिमांडज जैसे ऐनीमल हसबेन्डरी, इंडस्ट्रीज हैं इन पर अपने विचार रखूंगा। चेयरमैन साहब, बजट पर जनरल डिस्कशन के दौरान बाबू मूल चन्द जैन ने अपने विचार प्रकट किए थे और आज भी उन्होंने कुछ नुक्ताचीनी दबे दबे शब्दों में की और ऐसा मालूम होता है कि वे और वित्त मंत्री एक दूसरे की मुखालिफ बैचों पर जरूर बैठे हैं मगर गांधीवादी होने के नाते वे एक दूसरे के नजदीक हैं। चेयरमैन साहब, उन्होंने कोई 17 बारे यह कहा कि इसके लिये वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली .....

श्री मूल चन्द जैन: यह भी गांधीवादी विचारधारा है (व्यवधान)।

श्री सभापति: चौधरी साहब मुझे तो आप तीनों ही एक जैसे लगते हैं।

चौ. रिजक राम: आपने यह ठीक कहा है लेकिन .....

श्री बलदेव तायल: जनाब आपका मतलब कही महात्मा गांधी के तीन बन्दरों से तो नहीं है।

श्री सभापति: हमारा नसीब ऐसा कहां है।

चौ. रिजक राम: चेयरमैन साहब, बाबू मूल चन्द जैन भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बारे में सख्त लफ्ज कह गए। बाबू मूल चन्द ने जनरल डिस्कशन पर बोलते हुए और आज भी एक बात पर विशेश जोर दिया कि इस देश में स्वतन्त्रता मिलने के बाद पूंजीपति और सरमायदार लोग ओर अमीर हुए हैं। इन्होंने बिरला की मिसाल दी और इंडियन एक्सप्रैस का हवाला दिया। चेयरमैन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि भारतवर्श और खासतौर पर हरियाणा प्रान्त एक कृशि प्रधान प्रान्त है। इसमें 85 फीसदी किसान जमीन पर निर्भर करते हैं और 75 फीसदी लोगों का गुजारा चाहे वे मजदूर हैं चाहे दस्तकार हैं और चाहे किसान हैं और चाहे वे भूस्वामी हैं, उनका गुजारा खेती पर है और अन्तिम समय के आंकड़ों से साफ जाहिर है कि देहात में गरीबी की रेखा के नीचे 40–50 परसेन्ट लोग हैं जिनमें किसान, मजदूर शामिल

हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि जो अमीर लोग हैं वे ज्यादा अमीर हो गए। इस बात से कोई असहमत नहीं है। श्री मूल चन्द जैन ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह हालत पैदा क्यों हुई? (व्यवधान)

चौ. संत कंवर: चेयरमैन साहब, एक मिनिस्टर साहब आपके सामने से गुजर कर गए हैं यह ठीक नहीं है (व्यवधान)

चौ. रिजक राम: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि आखिर यह हालत क्यों पैदा हुई (व्यवधान) मुझे पता है कि तुमने इधर वोट दिया है (व्यवधान)

चौ. संत कंवर: चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चौ. रिजक राम ने कहा है कि मैं राय उधर देकर आया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि चौ. रिजक राम को कैसे पता लगा कि मैंने कांग्रेस (आई) को वोट दिया है। चुनाव जो होता है वे सीक्रेट होता है। अगर इनको पता लगा है तो फिर सीकरेसी क्या रही और इसलिये दुबारा चुनाव होना चाहिए (व्यवधान)

चौ. रिजक राम: मुझको तो किसी ने नहीं बताया लेकिन इन्होंने कहीं वायदा तो कर रखा था।

श्री सभापति: मुझे तो ऐसा लगता है और किसी ने कहा भी है–

वही जिन्दगी वही मरहले वही मन्जिलें वही फासले

लेकिन अपने मुकाम पर कभी हम नहीं कभी तुम नहीं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, इसी सम्बन्ध में मैं भी एक शेर कह देती हूं–

इन्ताह गरदिशे तूफां भी देख ली,

मन्जिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे।

चौ. रिजक राम: चेयरमैंन साहब, ऐसे हालात पैदा हो जाते है कि जब मैं बोलता हूं

11.00 बजे

तो उस वक्त सुशमा जी बीच में जरूर बोलती हैं। खैर चेयरमैन साहब, मैं इन सब बातों को छोड़कर दो चार बातें यहां पर कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, इस देश को आजाद हुए लगभग 30–32 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी देहातों में किसानों की वही दशा है जो पहले थी। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है और इसकी सारी जिम्मेवारी अगर देखा जाए तो हमारे प्लानर्ज की है जोकि ऊपर बैठे इन बेचारे देहाती भाइयों किसानों, गरीबों के लिये प्लानिंग का काम करते है। जिन लोगों ने 31 साल योजना भवन में बैठकर इस तरह की प्लानिंग की है, यह सारी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की है। चेयरमैन साहब इसके साथ साथ ऊपर बैठे लोगों ने यह किया कि देश आजाद होने के बाद सर्विजिज में रदोबदल किया और जो उनकी

आइडिआलोजी के मुताबिक लोग थे, उनकी बातों को मानने वाले लोग थे, उनको सर्विस में लिया गया। यहां पर जो लोग सर्विसिज में थे, चाहे वे सरमाये दार के लड़के थे, चाहे किसी जागीरदार के लड़के थे, उनका सर्विसिज पर पूरा कब्जा था। उनके हाथ में सारी सत्ता थी, और आप हैरान होंगे कि इन 30–32 सालों के अर्से में यहां पर देहातों में बसने वाले 85 परसेन्ट लोगों के लिये वे लोग योजना बनाते रहे लेकिन फिर भी देहातों में बसने वाला किसान, मजदूर या दूसरा गरीब किसी को भी आजतक उनकी योजनाओं से कोई फायदा नहीं हुआ है। गरीब किसान और मजदूर हमेशा से पिसता आ रहा है और उसकी हालत दिन ब दिन ज्यादा खसता होती जा रही है।

ठसी तरह से चेयरमैन साहब, एग्रीकलचर प्राईम कमिशन में आप देखेंगे कि कोई आदमी ऐसा वहां पर नहीं है जोकि गरीब किसानों और मजदूरों से हमदर्दी रखता हो बल्कि वहां पर बड़े बड़े सरमायेदारों के जागीरदारों के लड़कें बैठे हैं। वे ही गरीब किसान और गरीब मजदूर के लिये योजना बनाते हैं। मैं थोड़े शब्दों में आपको बताना चाहता हूं और आप सुनकर हैरान होंगे कि श्री धर्मनारायण जी, एग्रीक्लचर प्राईस कमिशन के चेयरमैन थे और उनका खुले तौर पर एलान था, अकीदा था, विश्वास था कि यह जो योजना चल रही थी उसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि देहात में लोगों के पास किसान हो मजदूर हो, धन इकट्ठा न हो जाए। अगर इन लोगों के पास धन इक्ट्ठा हो

गया तो यह देश के लिये सबसे बड़ा खतरा होगा। फिर इसके बाद उन्होने यह तजवीज की कि सरकार को सबसे बड़ी कोशिश इस बात की करनी चाहिये कि किसानों के पास धन इक्ट्ठा न हो और वह कोशिश यह हो सकती है कि किसान की जो जिन्स है, उसकी कम से कम कीमत लगाई जाए और जो माल किसानों को खरीदना हो चाहे वह मशीनरी हो या खाद हो या दूसरी चीजें हो उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा लगाई जाएं और इतना करने के बावजूद फिर भी किसान के पास धन इक्ट्ठा होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाएं जाएं।

चेयरमैन साहब, 1942 से लेकर आजतक आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त मार्किट में जो चीजों का भाव था, उसमें से सबसे कम भाव अब अनाज का लगाया गया है जोकि किसान की जीन्स है और इससे किसानों को नीचा करने की कोशिश की गई। ए.पी.सी. वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि किसान को उसकी जिन्स पर कितना अधिक खर्चा करना पड़ता है और इसलिये उसकी जिन्स की कीमत भी उसे ज्यादा से ज्यादा दिलवाई जानी चाहिये। इस ओर कीी भी ए.पी.सी. वालों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीजों की निस्बत, अनाज की कीमत सबसे कम लाई गई। चेयरमैन साहब इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, उनकी दिक्कतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। चेयरमैन साहब, एग्रीक्लचर प्राइस कमिशन ने जो अनाज की कीमत

मुकर्रर की है, वह इसलिये कम की है कि आम आदमी को सस्ते भाव पर अनाज मिले। इसमें दो राय नहीं है कि आम लोगों को सस्ते भाव पर अनाज मिलना चाहिये लेकिन साथ ही कमिशन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि किसान को भी उसकी जिन्स का सही भाव मिले। कमिशन ने ऐसा न करके किसानों के साथ कोई इन्साफ की बात नहीं की है। चाहिये तो यह था कि गरीब मजदूरों को सस्ते भाव पर चीजें दी जाएं। लेकिन ऐसा न करके सारा बोझ किसान पर ही डाल दिया गया। ऊपर योजना भवन में बैठे लोगों ने योजनाएं बनाकर इस देश का नक्शा जैसे खींचा उससे किसान और मजदूर दोनों बुरी तरह से पिसते रहे और सरमायेदार और पूंजीपति और अमीर होते चले गये। चेयरमैन साहब, आप देखेंगे कि पिछले 25–30 सालों में अनाज, चावल वगैरह की जिन्सों की कीमतों में इजाफा जरूर हुआ है। गेहूं और पैडी से 43 परसेन्ट, 44 परसेन्ट या 50 परसेन्अ तक का इजाफा हुआ है। 1971 से आज तक 42 परसेन्ट गेहूं में और चावल की कीमतों में 50 परसेन्ट का इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ जो चीजें किसानों को खरीदनी पड़ती हैं उनमें कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। आप एक ट्रैक्टर की आइटम को ही ले लीजियेगा। जो ट्रैक्टर 1966–67 में 8–9 या 10 हजार रूप्ये का था आज वही ट्रैक्टर 60 से लेकर 80 हजार तक का बिक रहा है ओर अगर उसके साि कही ट्राली ले ली जाए तो वह जाकर 1 लाख से कम नहीं पड़ता । उस पर फिर किसान को एक साल में 5 हजार रूप्ये मुरम्मत के लगाने पड़ते हैं। इससे जाहिर है कि

किसान को पूरा ट्रैक्टर ट्राली समेत कोइ लगभग सवा लाख का पड़ता है। इस तरह से आप देखें कि पहले की निस्बत आज ट्रैक्टर ट्राली की कीमत 15 गुणा बढ़ गई है। मतलब यह है कि जिन्स की कीमत जोकि किसान पैदा करता है, कम बढौतरी की हैं इसके साथ साथ, चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहात हूं कि दूसरी चीजें जोकि किसान की जरूरत की हैं, जैसे लुब्रीकेन्टस, फर्ीलाइजर्ज और एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्टस और दूसरी और भी कई चीजें हैं जोकि किसान मजदूर ओर गरीब आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे कपड़ा वगेरह इन सब कीमतों में बहुत ज्यादा बढौतरी हुई है। जब किसान को अपनी चीजें सस्ते भाव पर बेचनी पड़ती हैं तो वे बेचारे सोचते हैं क्योंकि उसको अपनी जरूरत की जब चीजें खरीदनी पड़ती हैं तो महंगी मिलती है और जब अपनी उपज मंडी में ले जाता है तो उसकी सबसे कम कीमत मिलती है। ए.पी.सी. के चेयरमैन को सरकार किसान की उपज का अधिक भाव दिलाने के लिये राजी करती रही, पर वह किसान के लिये कुछ भी न कर सकी। उसके बाद लोकदल की सरकार आ गई। श्री जैन श्री हमारे नेता हैं वे भी इस सिस्टम को तबदील नहीं कर सके क्योंकि जो लोग सर्विसिज में थे, उनको ये लोग आसानी से हटा नहीं सकते थे। इसलिये चेयरमैन साहब, मेरा कहना है कि जब तक सर्विसिज में ऐसे लोग बैठे हैं जोकि गरीब किसान और मजदूरों के साथ हमदर्दी नहीं रखते तब तक कोई भी सरकार इस सिस्टम को बदल नहीं सकती बल्कि इसके साथ साथ गरीब आदमियों और किसान मजदूरों की एक्सपलायटेशन होती रहेगी।

चेयरमैन साहब, वित्तमंत्री महोदय ने एक बात कही जिसके बारे में मैं थोड़ा सा यहां हाउस के सामने कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों से हम इसलिये ज्यादा वसूल कर रहे हैं कि उन पर बजट का 45 प्रतिशत खच्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ एकसाइज और टैक्सेशन से ये 140 करोड़ रूप्ये वसूल करते है और उस पर मुश्किल से डेढ़ परसेन्अ खर्च होता है। इसके बारे में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर कोई वित्तमंत्री यह समझता है कि किसान सिर्फ लैंड टैक्स ही देता है तो यह उसकी भूल है। वैसे तो अको लैंड टैक्स भी कोई कम नहीं है लेकिन किसान लैंड टैक्स के अलावा दूसरे टैक्सों में भी सबसे ज्यादा हिस्सेदार है जेसे पैसेंजर टैक्स है और सेलज टैक्स है। इसलिये देहात का रहने वाला जो किसान है, जमीदार है, दस्तकार है या मजदूर है वह सबसे ज्यादा टैक्स देता है। चेयरमैन साहब, सौ रूप्ये से कम आमदनी वाले लोग इस देश में और प्रान्त में 8 फीसदी हैं और वे लोग 55 प्रतिशल टैक्स देते हैं और बाकी 92 प्रतिशत लोग 45 प्रतिशत टैक्स देते हैं। इसलिए टैक्सों का जो ज्यादा बोझ है वह देहातों के मजदूर और किसान पर है, अमीर लोगों पर नहीं हैं दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने इस प्लान में पिछले प्लान की निसबल कृशि ओर इरीगेशन के लिये रूपया बढ़ाया है। यह बात भी छिपने वाली नहीं है। इस साल इन्हौंने 227 करोड़ या 220 करोड़ की बजाये 240 करोड़ रूपये की योजना बनाई है। इसके साथ साथ इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि इस साल के दौरान कीमतें 25 प्रतिशत बढ़ी

हैं। तो 25 प्रतिशत कीमतों में बढौतरी को देखते हुए 4–5 करोड़ रूप्ये प्लान में बढ़ाना कोई मायने नहीं रखता है। इन्होंने कहा कि पिछले साल एग्रीक्लचर और इरीगेशन के लिये कम रकम रखी गइ थी और कहते हैं कि इरीगेश और पावर को यह सरकार बढ़ावा दे रही है। मैं पावर के बारे में बताता हूं कि पावर केवल किसान के लिये ही नहीं दे रहे हैं बल्कि इससे और कंज्यूमर भी फायदा उठा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं। फिर ये आये साल 6 करोड़ या 10 करोड़ रूप्येा एक.वाई.एल. के लिये रख देते हैं सिर्फ यह दिखाने के लिये कि हमने इरीगेशन के लिये इतना रूप्यो रखा है। वर्श 1978–79 में एस.आई.एल. के लिये 16 करोड़ रूपये रखा गया था उसमें से इन्होंने 8 करोड़ रूप्या तो सरैंडर कर दिया और 8 करोड़ रूपया और कामों पर खर्च कर दिया। इसी तरह से इस साल भी एस.वाइ.एल के लिए 6 करोड़ रूप्या रखा गया है। इस बात का तो अभी पता नहीं कि वह बनेगी भी या नहीं लेकिन यह दिखाने के लिये पैसा रख दिया कि इरीगेशन पर हम इतना खर्च करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप एग्रीक्लचर के बारे में देंखें। इसके लिये जो रूप्या रखा गया है उसके लिये अलग मदें शामिल कर दी गई हैं जैसे लैंड रिफार्म, एम.आई.टी.सी, एनीमल हसबैंडरी, डेरी डिवैल्पमैंट, फिशरीज, फारैसटस और कम्युनिटी डिवैल्पमैंट एंड पंचायतस वगैरह वगैरह। इस तरह से सबको मिलाकर एग्रीक्लचर के लिये 61 करोड़ रूपया रखा गया है। (घंटी) चेयरमैन साहब, मैं थोड़े ही समय में समाप्त करता हूं। इस 61 करोड़ में से 20 करोड़ रूपया तो अन्तोदय प्रोग्राम के तहत है।

ऊपर मैंने जितने महकमें गिनाए हैं ये सारे इन्होंने एग्रीकल्चर में डाल दिये हैं। अगर आप देखें तो असली मायनों में एग्रीकल्चर के लिये 30–31 करोड़ रूपया बनता है। इस प्लान में 15 प्रतिशत खच्र पुलिस के लिये रखा है और 43 परसेन्अ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज के लिये रखा है। तो यह कहां का इन्साफ है कि 15 परसेन्ट खर्चा हम पुलिस के लिये रखें ओर 15 परसेन्ट ही एग्रीकल्चर के लिये रखें जिस पर 75 परसेन्अ लोगों का गुजारा है। (घंटी) हमारा कृशि प्रधान सूबा है लेकिन यह प्लान उसके मुताबिक नहीं बनाया गया। इसमें कृशि को बढ़ावा देने के लिये ज्यादा रूपया खर्च करना चाहिये। (घंटी) चेयरमैन साहब, आप बार–बार घंटी बजा रहे हैं। मैं तो बजट की जनरल डिस्कशन पर भी नहीं बोला लेकिन फिर भी मैं एक बाात और कह कर खत्म करूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमिशन की शुरू से यही कोशिश रही है कि किसानों की जिन्स की कीमतें न बढ़ाई जाएं। इसके लिये इधर उधर के तरीके अख्तियार किये गये। जैसे फारेन ट्रेडिन्ग है। इसके अलावा बैंकों में अनाज के स्टाक पर कर्जे देने बन्द किये गयें तीसरी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट थी वह बन्द की गई चाहे वह वैजीटेबल की थी या अनाज की थी।

श्री सभापति: चौधरी साहब, अब आप बैठिये आपको काफी टाइम दिया जा चुका है।

चौ. रिजक राम: चेयरमैन साहब, अगर आप और टाइम नहीं दे सकते तो मैं बैइ जाता हूं।

चौ. संत कंवर: * * * *

श्री सभापति: यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, आज सदन में मांग सख्या 14 से लेकर मांग संख्या 25 तक चर्चा चल रही हैं। मैं मांग संख्या 16, 17, 23 ओर 24 पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मांग संख्या 16 को लूंगी जोकि उद्योग के बारे में है। सभापति महोदय, उद्योग की मांग के तहत तकरीबन 5 करोड़ 45 लाख रूप्ये की मांग की गई है। सभापति महोदय, यह जो 1980–81 की नई स्कीम है इसके तहत जो पैसा खर्च किया जाना है वह केवल मात्र है। इसके बारे में जो सन्देह बाबू मूल चन्द जैन जी ने रखा था मैं भी उसमें शामिल होती हूं। क्योंकि इन्डस्ट्रीज मद में 5 करोड़, 44 लाख, 78 हजार 890 रूपया खर्च करने का जिक्र किया गया है। सभापति महोदय, मैं इस मांग के तहत कुछ स्कीमों का जिक्र करना चाहूंगी। सभापति महोदय, न्यू एक्सपैंडीचर प्लान स्कीम के पृश्ठ 105 पर आप देखेंगे कि इस मांग के तहत इंडस्ट्रियल एस्टेटस/डिवैल्पमैंट आफ कालोनीज के यि 20 लाख रूपए की मांग रखी गई है। यह सरकार कह रही हे कि हमें फिरोजपुर झिरका, कैथल और गोहाना के अन्दर इंडस्ट्रियल एस्टेट और डिवैल्पमैंट आफ कालोनीज करनी हैं। सभापति महोदय, मैं यह भी मानती हूं कि ये एरियाज बहुत बैकवर्ड हैं और इस तरह की जगहों पर यह काम होना भी चाहिये। इसमें यह भी बताया गया है

कि अम्बाल कैन्ट, पंचकूला, जींद, जाखल, कुण्डली और सम्मालखा में ये कालोनीज सैट अप की जा चुकी है। सभापति महोदय, मैं अम्बाला के बारे में बड़े अधिकार के साथ कहना चाहती हूं कि वहां इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिये जो जगह कागजों में ईयर मार्क की है वह बिल्कुल टांगरी नदी के लो लाईग एरिया के पास है जहां पर कि फल्ड बहुत जयाद आते हैं और इन फल्डज की रोकथाम के लिये सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हें जिस वजह से अम्बाला का एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाकर आबाद नहीं हो सका है। सभापति महोदय आप भी जानते हैं क्योंकि आपका हल्का छछरोली भी अम्बाल जिले में ही पड़ता है। इस सरकार ने अम्बाला जिले के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौ. प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुए) सभापति महोदय, आप जानते है कि अम्बाला जिले में साईस का बहुत ज्यादा सामान बनता है और यह औद्योगिक नगर भी है। वहां पर साईस इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं और वहां से साईस का सामान एक्सपोर्ट भी होता है जिसकी वजह से अम्बाला जिले ने हरियाणा का नाम भारत के नक्शे में बहुत ऊंचा किया है लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट न होने की वजह से हरेक आदमी को अपने छोटे–छोटे घरों में ही मशीन लगा कर काम करना पड़ता है जिससे कि वातावरण काफी खराब हो जाता है। इसलिये वे लोग चाहेते है कि उनको अच्छा वातावरण मिले। पता नहीं यह सरकार इस प्रगति की ओर कदम क्यों नहीं उठाना चाहती है? सभापति महोदय, मेरी सरकार से गुजारिश है कि वह

एच.एस.आई.डी.सी. को कहे कि वह पैसे को इनवेस्ट करें और इस झगड़े को समाप्त करके वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट को आबाद करने की कोशिश करे। सभापति महोदय आप यह सुनकर हैरान होंगे कि एक दिन यहां हाउस में प्रश्नोत्तर काल के समय में एक प्रश्न खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में आया था जिसमें यह पूछा गया था कि खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को साढ़े 23 लाख रूपये की ग्रांट दी गई थी तो उसमें से टोटल कितना पैसा लोगों को दिया गया? उसके जवाब में यह बताया गया कि केवल अढ़ाई लाख रूपए ही बांटे जा सके हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह बोर्ड बहुत इनएफिशिएंट है। सभापति महोदय, बम्बई खादी कमीशन ने खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़वा देने के लिये अपने बजट में बहुत ज्यादा ग्रांट देने का प्रोविजन किया है इसलिये इस बोर्ड को अपना काम फैलाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी इस बोर्ड के पास काफी ज्यादा पैसा आएगा और यह अपनी योजनाओं को फैलाएगा। लेकिन इसके साथ ही मुझे बड़ा दु:ख होता है कि पिछले साल इस बोर्ड ने साढ़े 23 लाख रूपऐ में से केवल अढ़ाई लाख रूपए ही बांटे। सभापति महोदय, मुझे इस बोर्ड की प्रगति बताते हुए शर्म आती हैं यदि यह बोर्ड सारा पैसा बांट देता तो सैंकड़ो और हजारों लोगों को फायदा हो सकता था। इस बोर्ड की हालत को देखते हुए बम्बई खादी कमीशन चाहे कितनी ही ग्रांट बढ़ा कर इसको दे दे फिर भी हरियाणा को कोई लाभ होने वाला नहीं है इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि बम्बई

खादी कमीशन से जितनी ग्रांट हरियाणा को मिले यह सारे का सारा पैसा समय पर लोगों को बांटा जाना चाहिए। सभापति महोदय, इसके अलावा इस किताब के पेज 107 पर आप देखेंगे कि एच.एस.आई.डी.सी. को एक करोड़ 10 लाख रूपया पब्लिक सैक्टर में अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिये दिया गया है। मुझे याद है कि कल हाउस में प्रश्नोत्तर लगाने के लिये और उसकी फिजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये ही खर्च करने हैं। सभापति महोदय, उनको यह मालूम नहीं कि फिजिबिल्टी रिपोर्ट क्या होती है और कैसे तैयार की जा सकती है? फिजिबिल्टी रिपोर्ट वहहोती है जिससे कि किसी यूनिट को वायबल बनाया जा सके। सभापति महोदय, हरियाणा टेनरीज में पिछले तीन साल का घाटा दिखाया गया है एक करोड़ 9 लाख 84 हजार और यह घाटा केवल तीन साल का ही है यदि इस यूनिट का जब से यह सैअ–अप की गई है, उस समय से घाटे का हिसाब लगाया जाए तो इस घाटे के आंकड़े करोड़ों में जा सकते हैं। सभापति महोदय, इस घाटे का कारण यह बताया गया है कि जब यह यूनिट सैट–आप की गई थी उस समय इसकी क्षमता दो हजार स्किन की थी। अब ये कहते है। कि यदि इस क्षमता को 5 हजार स्किन तक बढ़ाया जाए तो यह यूनिट वायेबल बन सकती है। सभापति महोदय, मैं वित्तमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जिस समय इसकी फिजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार की गई थी यदि उसमें 5 हजार स्किन पहले ही लिख दी होती तो यह यूनिट वायेबल बन सकती थी। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि एक

अनवायेबल यूनिट लगाई ही क्यों गई और यह दो हजार स्किन वाली फिजिबिल्टी रिपोर्ट किसने बनाई और इस घाटे के लिये कौन जिम्मेदार है? सभापति महोदय, इसी किताब के पेज 112 पर इनट्रैस्ट फ्री लोन के लिये 6 लाख रूपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का जिक्र यिका गया है। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Chairman: Please wind up.

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, अगर हम इस तरह से बड़े–बड़े उद्योगपतियों को इन्ट्रैस्ट फ्री लोन देने लग गए तो आप जानते हैं कि हरियाणा के फाइनैंशियल इंस्टीच्यूशन और बैंक जोकि गरीब हरिजनों और कमजोर वर्गो को पैसा देने की हैसियत रखते हैं उन गरीबों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा क्योंकि यह स्कीम तो केवल गरीब हरिजनों और कमजोर वर्गो के लिए ही है। इस किताब में यह लिखा गया है कि 6 लाख रूपए में से 4 लाख रूपया तो इनट्रैस्ट फ्री लोन दिया जाएगा और बाकी का 2 लाख रूपया एस्टेबलिशमैंट पर और इस स्कीम को इम्पलीमैंट करवाने पर खर्च होगा। सभापति महोदय, वही बात हुई कि धेले की बुढ़िया टका सिर मुण्डाई। सभापति महोदय, 4 लाख रूपए की मशीनरी लगाने के लिए 2 लाख रूपए एस्टेबलिशमैंट का खर्चा आ जाए तो क्य वित्तमंत्री जी इस बात का कोई जवाब देंगे? सभापति महोदय, इसी किताब में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम का जिक्र आया है। मुझे याद है कि इससे संबंधित मांग पर बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक कट मोशन भी दिया है परन्तु समय के

अभाव के कारण बाबू जी ज्यादा इस स्कीम को एक्सप्लेन नहीं कर सके। सभापति महोदय, मैं वित्तमंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि केवल देहातों में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये यह स्कीम बनाई हुई है और देहाती बेरोजगारों को ही इस स्कीम के तहत कर्जा देना था परन्तु अब ऐसा पता लगा है कि यह शर्त हटा दी गई है और यह कर दिया गया है कि अगर कोई शहर का आदमी भी गांवों में इंडस्ट्रीज लगाएगा तो उसको भी पैसा दिया जाएगा। क्या वित्तमंत्री जी यह स्पश्टीकरण देंगे कि पैसा देहात वालों को दिया जाएगा या शहर वालों का दिया जाएगा? सभापति महोदय, इसी किताब के पेज 3 पर 50 योजनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें से 10 सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीमें हैं और 40 स्टेट ग्रांट की स्कीम के अन्दर बदली गई हैं। इनमें काफी ज्यादा स्कीमें ओवरलेपिंग हैं। सभापति महोदय, इनमें 5 स्कीमें तो स्टोरेजके बारे में हैं जिससे कि लोग अपना माल गोदामों में सुरक्षित रखे सकेंगे। लेकिन देहात में आज तक लोगों को यह नहीं पता कि स्टोरेज कैसे किया जाता है? सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों एक गावं में गई थी। जब मैं उस गांव के सरपंच के घर में गई तो उसका गुड आंगन में बह गया था। मैंने यह कहा कि यह सारा आंगन कैसे खराब हुआ है तो सरपंच ने कहा कि अन्दर गुड़ रखा हुआ है। सभापति महोदय, इसलिये मैं बताना चाहती हूं कि गांव के एक सरपंच को भी अब तक यह पता नहीं कि उसको अपना माल कैसे सुरक्षित रखना चाहिये। फिर इन 5 स्कीमों का क्या फायदा है?

यह एक मात्र खोखला उदाहरण है और इन बुनियादी स्कीमों की कोई उपयोगिता नहीं हेा पा रही है।

सभापति महोदय, पृश्ठ 3 पर 1 लाख रूपए की एक योजना बनाई गई थी और यह राशि वर्श 1979–80 के लिऐ रखी गई थी लेकिन इस योजना का इम्लीमेंटेशन नहीं हो गया। इसमें लिखा है "Scheme for the installation of gas plants on night soils from community latrines." सभापति महोदय, इस योजना का बुनियादी मुद्दा यह था कि देहातों में महिलाओं के लिये पाखाने बनाये जाएं लेकिन किसी भी देहात के अन्दर कोई पाखाना नहीं बनाया गया। इसके साथ ही साथ गोबर गैर प्लाट स्थापित करने की योजना थी, इस योजना की भी इम्पलीमैंटेशन नहीं हुई। केवल एक लाईन लिख देने से स्कीम नहीं बन जाती, उसका इम्पलीमैंटेशन होना जरूरी था लेकिन सरकार इसमें असफल रही। इसके साथ ही साथ इसी पृश्ठ पर लिखा है – "Scheme for Agricultural Information Service." मैं कृशि मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या एक लाईन लिख देने से जनता की तसल्ली हो जाती है? आप सदन को स्पैसिफिक्ली बतायें कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी किन वजुहात के कारण इन योजनाओं को चालू नहीं यिका गया? क्या इनको अगले वर्श चालू किया जाएगा या लैप्स यिका जाएगा? चेयरमैन साहब, अब मैं अपने हलके के बारे में कुछ बातें सदन के ध्यान में लाना चाहती हूं। मांग सं. 23 में ट्रासंपोर्ट के लिये पैसा रखा गया है। नई प्लानिंग

स्कीम में लिखा है कि 80 लाख रूपया नये बस स्टैन्ड बनाने पर खर्च किया जाएगा। सभापति महोदय, पिछले बजट अधिवेशन में मैंने यह बात बार बार सदन में उठाई थी कि अम्बाला कैंट का बस–स्टैंड बहुत छोटा है। जब आप दिल्ली से चण्डीगढ़ आते हैं तो देखते होंगे कि अम्बाला बस स्टैण्ड पर बसों का कितना जमघट होता है। यह बस स्टैन्ड जी.टी. रोड पर पड़ता है। जिस समय यह बस–स्टैन्ड बनाया था उस वक्त बड़ा बस स्टैण्ड बनाने की जरूरत नहीं समझी गई थी लेकिन अब नैशनल हाई वे होने के कारण तमाम बसें अम्बाला बस स्टैण्ड पर रूकती हैं। जी.टी. रोड पर बाकी जितने भी बस स्टैन्ड हैं, करनाल बस स्टैन्ड है, वह इससे बड़ा है लेकिन अम्बाला बस स्टैन्ड सबसे छोटा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस वित्तीय वर्श में इस बस स्टैन्ड को चौड़ा किया जाए।

सभापति महोदय, मांग न. 24 के तहत टूरिस्ट कौम्पलैक्स बनाने के लिये 65 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं यह मानती हूं कि हमारे पर्यटन कौम्पलैक्स बहुत अच्छे हैं और जब आप चण्डीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में घरौंडा, करनाल, पीपली, पानीपत और सम्भालखा के टूरिस्ट कौम्पलैक्स मिलते हैं लेकिन अम्बाला मैं कोई टूरिस्ट कौम्पलैक्स नहीं है। सरकार ने 65 लाख रूपये का जो प्रावधान किया है, इसमें अम्बाला में एक टूरिस्ट कौम्पलैक्स जरूर बनाया जाए। अम्बाला जी.टी. रोड पर स्थित है, नैशनल–हाई वे होने के कारण बहुत

अच्छा टूरिज्ट कौम्पलैक्स बन सकात है और मुझे उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री सुमेर चन्द भट्ट (नग्गल): चेयरमैन साहब, जो डिमांडज हाउस के सामने रखी हैं, मैं इनके बारे में एक जनरल बात आपके सामने रखना चाहता हूं। डिमांड प्रेजेंट करने का जो तरीका है वह ठीक नहीं लगता, इसके बारे में मैंने पिछले साल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कई कई डिमांडज एक ही बार इकट्ठी हाउस में रख दी जाती हैं और हर डिमांड पर बोलने के लिये मैम्बर्ज को टाईम नहीं मिलता। इसके साथ ही साथ, हमारे मिनिस्टर्ज को साल में एक भी दिन ऐसा नहीं मिलता जिस दिन वे अपने अपने महकमों की स्कीमों को हाउस के सामने रख सकें, अपने विचार रख सकें और इन विचारों को सुनकर सदस्य अपने सुझाव मिनिस्टरों के सामने रख सकें। चेयरमैंन साहब, पिछली सरकार में जो कुछ होता रहा, वह आप सब जानते हैं लेनिक नई सरकार से मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि अगली बार डिमांडज को हाउस में रखने का नया तरीका जरूर अख्तियार करेगी।

चेयरमैन साहब, सरकार ने हमारे सामने बजट पेश किया। मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि बिना नये टैक्स लगाये एक ऐसा ढांचा सदन के सामने पेश किया जिसमें विकास के कामों के लिये ज्यादा प्रावधान कर दिया गया और जो तजवीजें पेश की गई हैं उनके लिये नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके

लिये मैं फाइनैंस मिनिस्टर को मुबारिकबाद देता हूं और इसके साथ ही एक सुझाव भी देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पैसा इक्ट्ठा करने का जो ढंग है उसमें बहुत लीकेज होती है। इस लीकेज को बन्द करने के लिए सदन की तरफ से कुछ मैम्बर्ज की कमेटी बना दी जाए जो लीकेज को बन्द करने में कंसर्न्ड डिपार्टमैंटस की मदद करे। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट जो खर्च करता है, उसमें बड़ी वेस्टेज होती है। मैं वित्तमंत्री महोदय से विनेदन करूंगा कि लीकेज को चैक करने के लिये और वेस्टफुड एक्सपैन्डीचर को रोकने के लिए सदन के सदस्यों को एक कमेटी बना दी जाए। इस कमेटी के पास सजा देने की पावर्ज होनी चाहिए ताकि जो इतना वेस्टफुल एक्पैन्डीचर हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। चेयरमैन साहब, अब मैं इरीगेशन के बारे में एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते है कि हमारा प्रदेश एक कृशि प्रधान प्रदेश है और कृशि के लिये पानी का होना बहुत आवश्यक है। हमारी पूरी कोशिश है कि पंजाब से अपने पानी का पूरा हिस्सा हासिल करें जो हमें नहीं मिल रहा है और अपने हिस्से को लेने के लिये हमारी कोशिशें मुतवातिर जारी रहनी चाहिएं। लेकिन जो पानी कुदरत हर साल हमें देती है, क्या उसको इकट्ठ करके हम इस्तेमाल कर पाये हैं या नहीं, यह देखने वाली बात है। चेयरमैन साहब, लगभग तीन महीने बरसात होती है अैर कुदरत हमें पानी देती हैं लेकिन इन तीन महीनों में हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि यह पानी हमारे राज्य से बाहर निकल जाए। जब यह पानी निकल जाता है तो 9 महीने का जो पीरियड होता

है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि एक–एक बूंद पानी हमें मिल जाए। चेयरमैन साहब, मैं चाहूंगा कि इरीगेशन डिपार्टमेंट कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नजरसानी करे जिससे तीन महीने की बरसात का पानी एक बूंद भी स्टेट के बाहर न जाने पाये ताकि जमींदार लोग 9 महीने में, जब पानी की सख्त जरूरत होती है, इस्तेमाल कर सकें। मैं अम्बाला जिले के बारे में एक मिसाल देता हूं। अम्बाला जिला की पानी के बिना बहुत बुरी हालत हैं। जहां तक आबपाशी का ताल्लुक है, बावजूद इस बात के कि कुदरत से सबसे ज्यादा पानी अम्बाला जिले को दे रखा है, लेकिन 9 महीने पानी की एक बूंद भी आबपानी के लिये अम्बाला जिले को नहीं मिलती। जो पानी के जखीरे हैं यानी स्टेट में नहरे हैं वह सारी स्टेट में हैं लेकिन नहरों में जो पानी है उसका इकुयल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता। जितना पानी नहरों में हैं, उसका 2 परसैन्ट पानी भी अम्बाला जिले को नहीं मिलता। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आज नहरों में जो एग्जिस्टिंग पानी है, उसमें से पूरा हिस्सा अम्बाला जिले को मिलना चाहिए, चाहे इसके लिये कैरियर सिस्टम बनाया जाए, चाहे कोई और तरीका अख्तियार किया जाये, लेकिन अम्बाला जिले को इरीगेशन के मामले में प्राथमिकता देनी निहायत जरूरी है। चेयरमैन साहब, सरकार की तरफ से अम्बाला जिले के लिये नहरी पानी दस्तयाब करने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से लगभग 100 करोड़ रूपए की स्कीम बनाई जा रही है। आज यह जो डिमांड इरीगेशन की हमारे सामने है इससे यह नहीं पता लगता कि उस स्कीमों की फेट क्या होगी। यह जो भेदभाव खत्म

होना चाहिए और टांगरी तथा मारकंडा आदि नदियों पर प्राथमिकता के आधार पर बांध बनने चाहिएं ताकि अम्बाला जिले की खुशहाली के लिए सरकार कुछ कर सके। चेयरमैन साहब, एक बहुत बड़ा सवाल इरीगेशन से ताल्लुक रखता है। एक पानी वह हे जो किसानों को नहरों के जरिए दिया जाता है और दूसरा पानी वह है जो टयूबवैल्ज के जरिए यिदा जाता है। चेयरमैन साहब, इन दोनों पानी के रेटस में कई गुना फर्क है। जिन जिलों में टयूबवैल्ज के जरिए पानी दिया जाता है उनको कई गुना ज्यादा रेट देकर टयूबवैल्ज से पानी मिलाता है। मेरी वजीर आबपाशी से दरखास्त है कि अपनी पालिसी पर फिर से नजरसानी करें और जिस रेट से नहरी पानी किसनों को मिलता है उसी रेट पर टयूबवैल का पानी उन जिालें के किसानों को मिलना चाहिए जहां नहरों का पानी दस्तयाब नहीं है। नहरी पानी से जब इरीगेशन नहीं होती तो आबियाना माफ किया जाता है लेकिन टयूबवैल्ज से पानी यदि न मिले तो आबियाना माफ नहीं होता। इससे हमारे जिले को खास तौर पर नुकसान होता है। चेयरमैन साहब, एक अर्ज मेरी और है। फल्ड कंट्रोल के लिए बहुत से इन्तजामात हमारी सरकार ने किए है, बहुत सा पैसा उसके लिए खर्च भी हो चुाक है लेकिन कई काम अधूरे पड़े हैं। मुझे डर है कि अगर इस दफा भी बाढ़ आ गई तो जितना पैसा उस काम के लिए खर्च किया गय है वह वेस्ट जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि उन कामों को पूरा करने के लिए अगर कुछ पैस बजट में और डालने पड़ें तो अवश्य डालने चाहिएं। (घंटी)

चेयरमैन साहब, इस सैशन में चूंकि मैं पहली बार बोल रहा हूं इसलिए मेरी अर्ज यह है कि मुझे समय थोड़ा और ज्यादा दिया जाए। (शोर)

आवाजें: चेयरमैन साहब, इनको बोलने दीजिए।

श्री सुमेर चन्द भट्ठ: चेयरमैन साहब, मैं तो कंक्रीट सजैशन्ज दे रहा हूं। इरीगेशन के मुताल्लिक एक और सुझाव मेरा यह है कि जो हमरा अन्डर–ग्राउन्ड वाटर का पोटैन्शियल है और जिसको ऐक्सप्लायट करने के लिए स्टेट में टयूबवैल्ज लगाए जा रहे है, उसमें से तकरीबन 75 परसैंट की ऐक्सप्लायटेशन हो चुकी है और केवल 25 परसैंट जखीरा बचता है। जिस तेजी से टयूबवैल्ज लगाए जा रहे हैं उससे तो अगले तकरीबन दो तीन साल में यह अन्डर–ग्राउन्ड वाटर का पोटैन्शियल खत्म हो जाएगा। मेरा अपनी सरकार को सुझाव है कि इस पोटैन्शियल को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े स्केल पर कदम उठाए जाने चाहिएं। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल मैथडज अपनाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अगर और पैसे का प्रावधान करना पड़े तो स्टेट की इकौनोमी के इंट्रैस्ट को सामने रखते हुए उसके लिए दरिया दिली से वजीर आबपाशी को काम लेना चाहिए।

अब चेयरमैन साहब, मैं इंडस्ट्रीज के बारे में दो शब्द कहूंगा। अभी सुशमा जी ने भी बताया कि स्टेट में इंडस्ट्रीज की

ग्रोथ का जहां तक ताल्लुक है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी एच. एस.आई.डी.सी. पर डाली गई थी। इस साल भी केवल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान बजट में किया गया है। चेयरमैन साहब, इस कार्पोरेशन की वर्किंग को देखने का थोड़ा सा मौका मुझे मिला है और उसके आधार पर मैं यह कह सकता हू कि करोड़ों रूपया इस कार्पोरेशन को दिया जा चुका है लेकिन अभी किसी ने यह देखने की तकलीफ गवारा नहीं कि कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया है, जिस फैक्टरी या कौम्पलैक्स के लिए दिया गया है वह वहां इस्तेमाल भी हुआ है या नहीं। करोड़ों रूपये देकर सरकार ने सिर्फ इस बात से तसल्ली कर ली कि हमने इतना कर्जा लोगों को दे दिया। कभी यह देखने की तकलीफ गवारा नहीं की कि उस पैसे का इस्तेमाल हुआ भी या नहीं। मैं चाहूंगा कि जब इंडस्ट्रियालाइजेशन की तरफ तेजी से कदम उठाने की बात हम करते हैं तो पुरानी पालिसी पर भी हमें नजरसानी करनी चाहिए और आगे इस बात की ऐहतियात बरतनी चाहिए कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाए वह उसी काम पर खर्च हो।

चेयरमैन साहब, हमारी स्टेट में एक मिनरल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन है। उसके द्वारा हमें बताया गया कि हमारी स्टेट में मिनरल्ज का पोटेन्शियल बहुत कम है परन्तु जब हम साईट पर गए तो गए तो हमने देखा कि बहुत सा जखीरा हमारे यहां ऐसा है जिसकी तरफ स्टेट ने ध्यान नहीं दिया। मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर

से दरख्ववास्त करूंगा कि वह इस कार्पोरेशन की तरफ खासतौर पर ध्यान दें। इस काम के लिए भी अगर हमें और पैसे का प्रावधान बजट में करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। (विघ्न)

श्री सभापति: कृपया वाइन्ड–आप करें।

श्री सुमेर चन्द भट्ट: चेयरमैन साहब, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में वाइन्ड–आप करें।

श्री सुमेर चन्द भट्ठ: चेयरमैन साहब, ट्रांसपोर्ट की डिमांड न. 23 हैं। आज देहात में जितनी संख्या में बसिज चलनी चाहिएं वे हम नहीं चला पाते क्योंकि इतना बसिज का फ्लीट हमारे पास नहीं है। मेरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को सुझाव है कि छोटे–छोटे देहात में बेरोजगार नौजवानों को टैम्पों चलाने के परमिट दें ताकि देहात में जो लोगों को बसिज का घंटों इंतजार करना पड़ता है व न करना पड़े, स्टेट के बसिज के फ्लीट को कुछ रिलीफ मिले और बेराजेगारों को रोजगार मिले।

चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में चीफ मिनिस्टर साहब ने जनसुई हैड पर टूरिज्म कौम्पलैक्स कायम करने का एलान किया था। मैं वजीर साहब से चाहूंगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्न्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति: ब्रिगेडियर रण सिंह।

श्री हीरा चन्द आर्य: सभापति महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिन मैम्बर्ज को अभी बोलने का टाईम नहीं मिला है, आप कृपया उनको टाईम दें।

श्री सभापति: जैन साहब ने जो लिस्ट दी है उसी के मुताबिक मैं टाईम दे रहा हूं।

श्री हीरा चन्द आर्य: मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि आप कृपया उसके मुताबिक ही टाईम दें।

Mr. Chairman: Kindly sit down. Leader of the Opposition Babu Mool Chand Jain has sent a request to me that Brig. Ran Singh, who has been Agriculture Minister, wants to participate in the discussion on demands for grants and he may be given some time. I have, therefore, called Brig. Ran Singh to speak.

ब्रिगेडियर रण सिंह (बेरी): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 17 पर अर्ज करना चाहता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा एग्रीकलचर डिपार्टमैंट की परफारमैंस पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी अच्छी है तो फिर हमारे ए.डी.ओ. के पे–स्केल उनसे कम क्यों हैं? मिसाल के तौर पर हमारे ए.डी.ओज. के पे–स्केल जो अब नया दिया है वह 525–900 दिया है लेकिन दूसरी स्टेट पंजाब और हिमाचल में

700–1250 दिया है यानी हमारे ए.डी.ओज. और इन्सपैक्टर्ज की तन्खाह शुरू में 175 रूपये कम है और आखिर में जाकर 300 रूपये कम है। चेयरमैन साहब बहुत से भाइयों ने शायद आज अखबार में पढ़ा होगा कि चाइना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पंजाब एग्रीकलचर डिपार्टमैंट की बड़ी भारी सरहाना की है क्योंकि पंजाब ने 15 साल के अन्दर गेहूं की पैदावार तीन गुनी कर दी है लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो बड़े फख्र की बात है कि हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने दस साल में यानी सन् 1965–66 से सन् 1975–76 तक तीन गुनी पैदावार की है और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि तेरह साल के अन्दर सन् 1978–79 तक चौगुनी कर दी। यह कमाल क्यों और कैसे हुआ? हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के ए.डी.ओज. बड़ी मेहनत करते हैं, फारमर्ज को जानकारी देते हैं, सुझाव देते हैं, डिमान्सट्रेशन देते हैं। कहते का मतलब यह है कि हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने भारी तरक्की की है। हिन्दुस्तान में सब प्रान्तों से ज्यादा तरक्की हरियाणा प्रान्त ने की है। मैं समझता हूं कि ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा इनसैन्टिव और सहूलियतें देनी चाहिएं। मिसाल के तौर पर पांच साला योजना के तहत सन् 1982 तक का जो टारगैट व्हीट का था वह सन् 1978–79 तक ही पूरा कर दिया। पांच साल का टारगेट दूसरे साल में ही पूरा कर दिया।

इसके अलावा एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ए.डी.ओज. की तन्खाह हमारी सरकार ने 1.4.79 को बढ़ दी थी। उनका ग्रेड 320–750 कर दिया था लेकिन बड़े अफसोस और दुःख की बात है कि इस ग्रेड को जो हरियाणा सरकार ने मन्जूर किया था, पे–कमीशन ने उसे भी नहीं माना। यह बहुत ही नाजायज बात की। ऐसे कर्मचारी जो एग्रीकल्चार में इतनी बड़ी भारी बढ़ौतरी करके दिखायें उनको सिर्फ शाबासी ही नहीं बल्कि और भी इन्सेन्टिव और सुविधाएं दी जानी चाहिएं परन्तु पे–कमीशन ने उनकी तन्खाहें पहले से भी कम कर दी हैं। हिमाचल जैसे छोटे प्रान्त के अन्दर पंजाब के बराबर पे है, इसलिए मैं वित्तमंत्री से निवेदन करूंगा कि इसमें कुद भी फाइन्शियल इम्पलीकेशन्ज हों लेकिन उनको पंजाब और हिमाचल प्रदेश से कम कम पे–स्केल नहीं दिये जायें। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वे भी इस तरफ पूरी तवज्जोह दे क्योंकि हमारे ए.डी.ओज. को काम फील्ड में दिन को भी और रात को भी है। ये गर्मी और सर्दी में भी गांवों में काम करते हैं। इन लोगों को गांवों में ही रहना पड़ता है जैसे आप जानते है कि वहां पर पढ़ाई और दूसरी सहूलियतें भी बहुत कम उपलब्ध हैं, बल्कि कई स्थान तो ऐसे हैं, बिल्कुल ही नहीं हैं। इनकी सर्विस कन्डीशन्ज और डिपार्टमैन्ट की बनिस्बत बहुत ही कश्टदायक है। आखिरी निचोड़ यह है कि इन ए.डी.ओज. की तन्खाह हरियाणा सरकार ने बड़ी सोच–विचार के पश्चात बढ़ाई थी जिसके विशय में चीफ मिनिस्टर महोदय ने तथा एग्रीकलचर

मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था। हमारे हाल के मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन थोड़े ही दिन पहले हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भाशण करते हुए दिया था।

एक और जरूरी चीज जिसके बारे में मैंने पहले भी अपनी बजट स्पीच में सुझाव दिया था। चेयरमैन साहब, सरकार की ओर से कम्यूनिटी लैटरीन स्कीम के लिए छः लाख रूपया दिया गया था लेकिन यह रूपया कई सालों से पड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि गांवों के अन्दर कितनी भारी गन्दगी है, वे लोग वहां पर नर्क में रहते हैं इसलिए ये कम्युनिटी लैटरीन अवश्य बनायी जानी चाहिए। मुझे पता लगा है कि इसमें कोर्ठ टैक्नीकल हिच है। उसकी गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अब तक टैक्नीकल ऐप्रूवल नहीं दी है। अगर यह हो जाये तो बड़ी भारी अचीवमेंट होगी। एक तो गांव की सफाई होगी दूसरे स्त्रियों को बड़ी भारी सहूलियत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि यह काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाये।

चेयरमैन साहब, एक और चीज भी सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि चाइना डेलीगेशन ने कहा है कि चाइना के अन्दर 95 परसैंट फैमिलीज के पास गोबर गैस प्लांट हैं जो गेहूं और धान के भूसे से चलती हैं। एक तो इन गोबर गैस चूल्हों से देहात में सफाई अच्छी होगी दूसरो खाना पकाने में भी बड़ी भारी सुविधा होगी और साथ ही साथ खेती के लिए बहुत अच्छा खाद मिलेगा। इसलिए मुझे बड़ा

दु:ख है कि इस स्कीम पर पहले तो बड़ा भारी जोर दिया गया था। हरियाणा में इस हजार गोबर गैस प्लांटस लगाये गये थे। मैंने सुना है कि अब उनमें से चार हजार बोगस है।, वे बने ही नहीं और 3500 डिफैक्टिव हैं, केवल अढ़ाई हजार बाकी रह गये। जब ऐसी हालत हो तो कैसे काम चल सकता है। सन् 1956 में मुझे चाइना जाने का अवसर मिला था। मैं वहां के कई गांवों में गया था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह सकात हूं कि वहां हमारे गांवों के मुकाबले में उनके गांवों की तीन चार गुना बुरी हालत थी लेकिन अब वहां पर 95 परसैंट फैमिलीज के पास गोबर गैस के चूल्हे हैं। इस बात से साफ जाहिर है कि हम ओर हमारी गवर्नमैंट कितनी लापरवाह और ना–अहल है, क्योंकि जहां चाइना में शून्य से 95 परसैंट परिवारों के पास गैस चूल्हे हो गये हैं तो हमारे यहां जब यह तहरीक छः सात साल पहले आरम्भ की थी तब से अब तक केवल एक परसैंट परिवार के पास ये चूल्हे हैं। वह बड़ी दु:ख की बात है। यह बहुत ही उन्नति का काम है इससे एक तो हमारी एग्रीकलचार पैदावार में बढ़ौतरी होगी क्योंकि अच्छा खाद मिलेगा और गांव की सफाई बड़ी अच्छी हो जायेगी। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं आजकल हमारे यहां ईधन की भी बड़ी भारी कमी है, वह भी दूर हो जायेगी।

चेयरमैन साहब जब हम लामनी कर लेते हैं तो उसके बाद जो अन्न का नुक्सान होता है वह बहुत ज्यादा होता है। चाइना में यह नुक्सान एक परसैंट होता है लेकिन हमारे यहां चार

से 15 परसैंट है और गांवों में लीजिए तो यह 30 परसैंट तक है। आपको पता है कि कितनी मेहनत से हम अनाज पैदा करते हैं और फिर इस तरह से जाया हो जाये तो बड़े दुःख की बात है। हमारा धर्म यह कहता है कि अनाज बरबाद करना पाप है। तीस परसैंट का नुक्सान बहुत भारी नुक्सान है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए स्टोर्ज बनाये जायें। वैसे तो सरकार ने दूसरी फूड ग्रेन बिन की स्कीम के तहत काफी सबसिडी दी है और देनी भी चाहिए ताकि जो अनाज हम पैदा करते हैं वह खराब न हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार के सम्मुख जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर जल्द और कारगर कदम उठाये जिससे हमारे प्रान्त की जनता को अधिक से अधिक लाभ हो।

चौ. राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़): चेयरमैन साहब, मैं वर्श 1980–81 के बजट

12.00 बजे

की डिमान्डज पर जो चच्र रही है उस पर बोलना चाहता हूं। मैं खासकर डिमांन्ड न. 14, 15, 16, 17 की चर्चा चल रही है उस पर बोलना चाहता हूं। चेयरमैन साहब सबसे पहले मैं डिमान्ड न. 14 पर बोलना चाहता हूं। जहां तक इस डिमांड का संबंध है इस पर सदन के सबसे ज्यादा माननीय सदस्य बोले है। इस डिमांड पर बोलने वालों में हमारी तरफ के सदस्य तथा अपोजीशन की तरफ से भी सदस्य बाले हैं। चेयरमैन साहब, जहां तक फूड एण्ड

सप्लाईज का सम्बन्ध है यह बहुत ही आवश्यक है। चेयरमैन साहब हमारा देश कृशि प्रधान देश है और हमारे देश की प्रधानमंत्री की ओर से रोजाना ही या दूसरे–तीसरे दिन अखबारों में स्टेटमेंट आती रहती है कि जनता पार्टी के राज में हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी है इसलिए उसको ठीक करके सारे देश के अन्दर एक अच्दी और साफ–सुथरी वितरण प्रणाली देंगे। मैं सारे सदन का ध्यान और खासकर मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि हमारी स्टेट के अन्दर विवरण प्रणाली बड़ी डिफेक्टिव है। इसलिए इस विवरण प्रणाली में सुधान किया जाना चाहिए। मैं इस डिमांड पर ज्यादा समय न लेते हुए सदन का समय खराब नहीं करना चाहता क्योंकि पहले ही काफी सदस्य इस डिमांड पर बोल चुके है। सभी सदस्य जानते हैं कि हमारे देश के अन्दर सभी चीजों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इन जरूरी चीजों जोकि लोगों द्वारा रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं, की विवरण प्रणाली का संबंध हैं, वह ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन आवश्यक चीजों का विवरण अच्छे ढंग से होना चाहिए। चेयरमैन साहब, चाहे कोई गरीब आदमी है, छोटे वर्ग का आदमी है, गांवों के अन्दर हरिजन भाई हैं और किसान भाई हैं उन सभी को अच्छी वितरण प्रणाली तैयार करके ये आवश्यक चीजें पहुंचाई जानी चाहिएं। जो चीजें आसानी से लोगों को उपलब्ध नहीं होती वे उन्हें मिलनी चाहिएं। नागर साहब मेरे बड़े भाई हैं। नागर साहब को मैं बड़ा आदर करता हूं। लेकिन में उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे अपने बल्लभगढ़ के हल्के में वहां पर एक फूड

एण्ड सप्लाईज का इंस्पैक्टर है जिसका नाम * * * * है। वह इंस्पैक्टर * * * * है खुले आम लोगों से रिश्वत लेता है और लोगों को परेशन करता है।

चौ. संत कंवर: क्या मंत्री जी का भी उसमें हिस्सा है?

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. सुरशीद अहमद): चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह इस हाउस से रिलेट नहीं करता इसलिए उन्हें किसी बाहर के आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए।

चौ. राजेन्द्र सिंह: यदि किसी बाहर के आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए था तो मैं उसका नाम वापस लेता हूं।

श्री सभापति: जो शब्द फूड एंड एप्लाईज इंस्पैक्अर के बारे में तथा नागर साहब के बारे में कहे गए हैं वे एक्सपंज कर दिए जाएं।

चौ. राजेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने प्रान्त के अन्दर वर्तमान वितरण प्रणाली को ठीक करके एक सुदृढ़ वितरण प्रणाली बहुत ही जल्दी लागू की जाये ताकि आम आदमी को जरूरी चीजें ठीक समय पर मिल सकें।

चेयरमैन साहब, डिमान्ड न. 15 जो इरीगेशन की हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड है। हरियाणा प्रान्त एक कृशि

प्रधान प्रान्त है। यहां के 80 प्रतिशत से अधिक लोगों का जीवन किसी न किसी प्रकार खेाती से सम्बन्ध है। चेयरमैन साहब सभी माननीय सदसरू जानते है कि एक सिकान के व्यवसाय में जो लोग खेती का पेशा करते हैं, उनके इस पेशे में इरीगेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सारा देश जानता है कि हमारे हरियापणा के किसान भाई बहुत ही मेहनती है। हमारे प्रान्त के किसानों, ने अपनी मेहनत के कारण प्रदेश में अन्न पैदावार को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया है। हमारे किसानों ने न केवल अपने प्रदेश की पैदावार को बढ़ाया है अपितु सारे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। चेयरमैन साहब, हमारी फरीदाबाद जिले में एक आगरा कैनाल है जो यमुना और ओखला से निकलती है। यह कैनाल बल्लभगढ़ तहसील और पलवल तहसील से होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जाती है। चेयरमैन साहब इस कैनाल के द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए पानी दिया जा रहा है। इसलिए मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो पीन इस कैनाल द्वारा दिया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा पानी हमारे क्षेत्र के किसानों को नहीं दिया जाता। इस कैनाल के द्वारा जितना पानी मिलना चाहिए, वह पानी अगर मिल जाता है तो इस क्षेत्र के किसानों को पानी की और अधिक सुविधा होगी जिससे प्रदेश की पैदावार में बढ़ौतरी होगी और किसान अपनी सारी भूमि को बो लेंगे। चेयरमैन साहब यह भी देखते में आया है कि इस कैनाल का जो मैनेजमैंट है वह सारे का सारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। इसलिए हमारे यहां के किसानों के साथ

डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो मैं अपनी सरकार से और खासकर सी.एम. साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाये ताकि वहां के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो।

चेयरमैन साहब, बल्लभगढ़ के गांवों में एम.आई.टी.सी. के सैकड़ों टयूबवैल लगे हुए है। आज उन टयूबवैलों की वजह से हमारे वहां के कई गांव उजडने जा रहे हैं। जब एम.आई.टी.सी. के टयूबवैल चलने लगते हैं तो जो टयूबवैल किसानों ने लगा रखें हैं उनका पानी सूख जाता है और उनसे पानी बिल्कुल नहीं निकलता क्योंकि एम.आई.टी.सी. के टयूबवैल ज्यादा गहराई तक लगे हुए हैं। इस संबंध में वहां के किसानों के एक डैपूटेशन ने हमारे मंत्रियों से भी मिलने की कोशिश की है और वह डैपूटेशन वहां के डिप्टी कमिश्नर से भीा मिला है। उस डैपूटेशन ने अनुरोध किया था कि उन टयूबवैल्ज को या तो बन्द कर दिया जाये या उनको चलाने का कोई टाईम फिक्स कर दिया जाये ताकि जो दूसरे लोगों ने टयूबवैल्ज लगा रखे हैं उनको भी अपने टयूबवैल्ज से पानी मिल सके।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड न. 16 पर कुछ थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। आज हमारे हरियाणा प्रान्त में बड़ी–बड़ी इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। बड़े–बड़े उद्योगपतियों ने अपने उद्योग–धन्धे चालू किए हुए हैं। उन्होंने न केवल हमारे प्रान्त का नाम अपने देश में अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। उनमें से

फरीदाबाद उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हैं इस क्षेत्र पर हरियाणा के लोगों को बड़ा फख्र होना चाहिए। फरीदाबाद के अन्दर जो चीजें बनती हैं वे न केवल भारत में ही वितरित की जाती है बल्कि संसार के दूसरे देशों में भी जा रही हैं कम्पीटीशन के अन्दर जो माल खरीदा जाता है उसमें फरीदाबाद के अन्दर तैयार किया हुआ माल बाहर के देशों द्वारा ज्यादा खरीदा जा रहा है।

चेयरमैन साहब, एक बड़ी सच्चाई की बात है कि इंडस्ट्रियल आउट पुट या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि वहां के उद्योगपतियों को बिजली दी जाये, वहां पर सरकार की तरफ से रा–मैटीरियल उपलब्ध करवाया जाये और जो सबसे बड़ी ओर जरूरी बात मैं समझता हूं वह यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल उत्पादन बढ़ाने के लिये वहां पर इंडस्ट्रियल पीस का होना बहुत जरूरी है। फरीदाबाद में अकसर देखेन में यह आया है कि 10–20 फैक्ट्रियों के अन्दर स्ट्राईक रहती है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मौजूदा चौ. भजन लाल की सरकार ने इस बारे में काफी ठोस कदम उठाये हैं और वहां पर अब पहले से कम फैक्ट्रीज में स्ट्राईक है। काफी फैक्ट्रीज में स्ट्राईक खुलवायी गयी हैं। अब भी जिन फैक्ट्रीज में स्ट्राईक चल रही है, उसके लिये मैं सरकार के इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वहां पर भी स्ट्राईक खुलवायी जाये। चेयरमैन साहब, मैं इस सम्बन्ध में अपनी सरकार

का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर जो लेबर डिपार्टमैंट का अफसर होता है, अगर वह शुरू से ही अपनी तरफ से कोशिश करे कि स्ट्राईक न हो और जो रिलीफ वर्कर्ज को और मजदूरों को मिलना चाहिए, वे दिलवा दे तो स्ट्राईक को प्रिलीमिनरी स्टेज पर ही टाला जा सकता है। अगर कहीं ऐसा हो जाये तो बड़ी–बड़ी फैक्ट्रीज बन्द होने की नौबत ही न आये। मेरा कहना यह है कि फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जिस वक्त किसी अफसर या कर्मचारी की नियुक्ति की जाये और सरकार को इस इंडस्ट्रियल बैल्ट पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं अब डिमांड न. 17–एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस डिमांड पर बहुत ही थोड़ा बोलूंगा। हमारा प्रदेश एक कृशि प्रधान प्रदेश है। देश में यानी सारे भारतवर्श में सबसे ज्यादा मेहनती किसान हरियाणा प्रदेश का माना जाता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट के अन्दर हमारे वित्तमंत्री महोदय ने किसानों के लिये ओर कृशि का उत्पादन बढ़ाने के लिये, सिंचाई के लिये, बिजली और पानी देने के बारे में कहा है। मुझे पूरी आशा है कि वे एस.वाई.एल. प्रोजैक्ट भी बहुत ही जल्दी पूरा करवायेंगे और हमारे हरियाणा के किसान को पूरा पानी मिल सकेगा। (घंटी) चेयरमैन साहब, बस एक दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। चेयरमैन साहब, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा का किसान बहुत ही मेहनत से उत्पादन बढ़ाता है लेकिन जब वह अनाज मंडी में बेचने के लिये ले जाता है तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। मैं सरकार का ध्यान उस अन्याय की

ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट की जाती है, वह बड़ी डिफैक्टिव सिस्टम से की जाती है। उसके अन्दर इन्होंने ए ग्रेड और बी ग्रेड बनाए हुए हैं यानी एक नम्बर और दो नम्बर ग्रेड बनाए हुए हैं। वहां पर जो प्रोक्योरेमैंट करने के लिये कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनको इतनी ज्यादा डिस्क्रीशन दी हुई हैं कि चाहे कोई गेहूं बढ़िया किस्म का भी क्यों न हो, जब तक उन्को पैसे ने दिये जायें तब तक वे 'ए' ग्रेड के अनाज को भी 'बी' ग्रेड का अनाज दिखाते हैं। यह एक सच्चाई की बात है कि 'बी' ग्रेड के नाम पर जो गेहूं वहां पर खरीदा जाता है, वह होात दरअसल 'ए' ग्रेड का है। सुबह तो उस गेहूं को 'बी' ग्रेड में दर्ज किया जाता है लेकिन जब शाम को उनको पैसे मिल जाते हैं तो उसी गेहूं को 'ए' ग्रेड का कागजों के अन्दर शो किया जाता है। यह जो किसान की मेहनत के ऊपर डाका डाला जाता है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको समाप्त करवायें क्योंकि इससे बहुत झगड़ा होता है। (घंटी) अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री टेक राम (मुंढाल खुर्द): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड न. 14, 15, 17 और 18 पर बोलना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, मेरे आदरणीय दोस्त चौ. रिजक राम जी जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने अभी जिक्र किया .....

श्री सुरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। यह कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

श्री टेक राम: मैं डिमांड न. 14 और 15 पर बोल रहा हूँ। चेयरमैन साहब, इस हाउस में 240 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। एफ.एम. साहब ने प्रैस वालों से बात करते हुए यह माना है कि उसमें से हमारी मांगे 209 करोड़ रूपये की हैं। अपनी स्पीच के अन्दर उन्होंने यह कहा है कि 209 करोड़ रूपया तो हमें यहां पर विभिन्न डिपार्टमैंटस के लिये चाहिए और 13 करोड़ रूपया हमने सैंट्रल गवर्नमैंट को सूद की अदायगी करनी है। चेयरमैन साहब, मैं एक बात यहां हाउस में बताना चाहता हूं और सारे मैम्बर साहेबान भी इस बात को जानते है कि जनवरी के अन्दर अगले साल की योजना बनाई जाती है जिसको स्टेट के अफसर प्लानिंग कमिशन के पास जाकर डिस्कस करते हैं। उस मीटिंग के अन्दर डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग बोर्ड भी जाता है। अब तक जितनी भी डिमान्डज आयी है, उनकी न तो कोई योजना बनी है और न ही योजना आयोग ने उनकी ऐप्रूवल दी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाउस को यह बताना चाहता हूं कि डिप्टी चेयरमैर प्लानिंग बोर्ड ने इस गवर्नमैंट से तकरीबन दो रोज पहले अस्तीफा दिया था, उन्होंने दल बदला था। चेयरमैन साहब, आप देखिए कि प्लानिंग कमीशन ने इनकी कोई योजना ऐप्रूव नहीं की और फिर भी बजट में मांगें रख दी गयी हैं। (शेम शेम की आवाजें) शायद उन्होंने यह सोचा कि मार्च के महीने तक ही गवर्नमैंट रहनी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो फिर प्लानिंग कमीशन से डिस्कस करने का क्या लाभ है? उन्हें यही यकीन नहीं था कि चण्डीगढ़ से दिल्ली जाने तक लोग उनके साथ

रहेंगे भी या नहीं? शायद लोग दल बदल जायें ऐसा उनका ख्याल था इसलिये उन्होंने यही सोचा कि प्लानिंग कमीशन की एप्रूवल को भी छोड़ दिया जाये और डिमान्डज ले आए। चेयरमैन साहब, इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। ऊना स्टेट के अन्दर एक राजा राज करता था। (व्यवधान व शोर)

श्री सभापति: आप किस डिमान्ड पर बोल रहे हैं?

श्री टेक राम: मैं, तायल साहब ने जो डिमान्डज रखी हैं, उन्हीं पर बोल रहा हूं। मैं बता रहा था कि एक राजा ऊना स्टेट के अन्दर राज किया करता था। उसके खजाने की हालत बहुत खस्ता थी। उसने अपने चीफ कमान्डर को बुलाया और यह कह दिया कि तुम मेरे लिये काबिल नहीं हो। उस चीफ कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। उसने दूसरे आदमी को बुलाया ओर उसको ओथ दिया दी। राजा ने यह सोचा कि यह मुझे सलामी देगा (शोर व व्यवधान) मगर उसने भी उसको सलामी नहीं दी। उसने उसको भी निकाल दिया। यहां पर तो यही * * * * मचा हुआ है। (व्यवधान व शोर)

चौ. खुरशीद अहमद: चेयरमैन साहब, टेकराम जी ने बोलते हुए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किय हैं जो लोग आम भाशा में भी इस्तेमाल नहीं करते। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि यह शब्द ऐक्सपंज किया जाये और उनसे यह कहा जाये कि वे आइन्दा सभ्य भाशा बोलें।

श्री सभापतिः वे शब्द ऐक्सपंज कर दिये जायें जो उन्होंने अभी बोले हैं।

चौ. हरि चन्द हुड्डाः चेयरमैन साहब, यहां पर तो यह हालत हो रही है–

सब कहते हैं कि चमन बदला है,

हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है,

शमशान की खामोशी मगर यह कहती है,

है लाश वही सिर्फ कफन बदला है।

श्री टेक रामः चेयरमैन साहब, आज हालत यह है कि लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता। तेल के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। चीनी की भी यही हालत है। हमारे यहां हरियाणा में और दिल्ली के राशन कोटे में काफी फर्क है। दिल्ली में छः सौ ग्राम चीनी मिलती है और हमारे यहां चार सौ ग्राम मिलती है (व्यवधान) –

श्री सुरेन्द्र सिंहः मुझे पता है कि यह कितना ईमानदार है। यह चौदह रूपए किलो चीनी बेचता था। इसकी इंक्वायरी करवा ली जाए। (व्यवधान)

श्री टेक रामः * * * * मैं मवेशियों के बारे में कहना चाहता हूं .....

श्री लहरी सिंह मेहता: अभी माननीय सदस्य ने * * * * कहा है क्या वह अनपार्लियामेंटरी नहीं है?

श्री सभापति: वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री टेक राम: चेयरमैन साहब, मैं मवेशियों के बारे में कह रहा था। आज एक–एक पशु पांच–पांच हजार रूपये का आता है और अगर वह बीमार हो जाता है तो उसके लिए इवाई दुर्लभ (मतलब उपलब्ध से है) नहीं है। वे दवाई की कमी के कारण मर जाते हैं और किसान का बहुत नुक्सान होता है। मेरी सरकार से दरखास्त है कि देहातों में पशुओं के लिए दवाइयों का इन्तजाम किया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, अब मैं डिमान्ड नम्बर 15, जो कि इरीगेशन के बारे में हैं, के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जब चौ. रिजक राम मिनिस्टर थे तो इन्होंने बहुत से माइनर्ज का उदघाटन किया था और बजट पेश करने के समय भी कहा गया था कि सब माइनर्ज चालू कर दी गई हैं। चेयरमैन साहब, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी माइनर्ज हैं जो मन्जूर तो हैं लेकिन उनके लिए सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको जल्दी ही बनवाया जाए। चेयरमैन साहब, अब मैं डिमान्ड नम्बर 22 के बारे में कहना चाहता हूं। कोआप्रेशन मिनिस्टर साहब नक इस महकमें के अन्दर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को लगाया है या एक ही वर्ग के लोगों को लगाया है। किसी और वर्ग के लोगौं को इस डिपार्टमैंट में नहीं लिया गया है। चेयरमैन साहब, इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नम्बर 15, 17, 19 और 23 पर बोलना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, जब मैं बोल रहा हूं तो बाबू मूल चन्द जी बैठे नहीं हैं। ये जितने दिन भी फाइनैंस मिनिस्टर रहे इन्होंने जनता का कोई भला नहीं किया। इन्होंने तो यह किया कि फाइनैंस का महकमा एक किसान के बेटे से छिनकर अपनी छाती से लगा लिया था। (व्यवधान) अब मैं नहरी पानी के बारे में कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, नहरी पानी किसान की जिन्दगी और मौत का सवाल है। आज हरियाणा में सूखा पड़ा हुआ पड़ा हुआ है और लोग एक–एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यह पिछली सरकार और कुदरत की बात है कि सूखा पड़ा हुआ है। चेयरमैन साहब, आज थोड़ा बहुत जो पानी किसान को मिल रहा है वह भी बराबर नहीं बट रहा है। नहर के जो छोटे मुलाजिम हैं वे बड़े–बड़े किसानों से मिल जाते हैं और गरीबों का पानी काटकर उन बड़े किसानों को दे रहे हैं। डिपार्टमैंट का इन छोटे मुलाजिमों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि किसानों को बराबर का पानी मिले तो उसको चाहिए कि वह नहरी इलाकों में पुलिस की गश्त करवाए जिससे कि टेल तक पानी पहुंचे और टेल पर जो गांव हैं वहां के लोगों को नहर का पानी मिल सके। अब तो हालत यह है कि टेल पर पानी पहुंचता ही नहीं क्योंकि बीच में पानी काट किया जाता है। मेरे यहां एक गांव छप्पर है जो चौ. वीरेन्द्र सिंह की कांस्टीचुऐंसी में है वहां पर बिजाई नहीं की गई है और इसका कारण पानी की कमी है। एस.

वाई.एल. का पानी लाने के बारे में मेरी सरकार से दरखास्त है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी कोर्ट से फैसला कराए और पंजाब साइड में जो नहर बनती है उसको बनाकर हरियाणा में पानी लाएं जिससे कि हमारे यहां किसानों की तकलीफ दूर हो सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रजवाहे हैं उनको बनाने का कौट्रेक्ट नहीं देना चाहिए बल्कि एम.एल.ए. ओर वजीर साहिबान मिलकर अपने सरों पर टोकरी उठाकर इन रजवाहों को बनाएं।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौ. राम किशन, पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चर का महकमा बहुत जरूरी है लेकिन आज कल जमीन के ऊपर पापूलेशन बढ़ने के कारण बहुत बोझ पड़ा हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो छोटे किसान हैं उनके बच्चों के लिए पच्चीस परसैंट सीटें जुडिशियरी तथा दूसरी नौकरियों में रिजर्व की जानी चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वह जवानों के बारे में है जो फौज में भर्ती होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सेन्टर से डिमांड करे और इस बारे में एक रेजोलूशन भी पास किया जाना चाहिए कि जो मारशल कौमें हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मिलिटरी में भर्ती होनी चाहिए और फौज में बढ़ौतरी की जानी चाहिए। चेयरमैन साहब, सर शादी लाल ने अपने एक फैसले में जाटों को शूद्र कहा था। यह बिल्कुल गल्त

बात है। मेरी डिमांड है कि अगले सैशन में इस चीज को हटाने के लिए एक बिल लाया जाए। चेयरमैन साहब, जाट एक बहादुर कौम है। पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई तो जाटों ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिये थे और जाटों ने सब से ज्यादा कुर्बानी दी थी। मैं सरकार से एक और बात कहना चाहता हूं कि रोढ़ हैं, बिश्नोई है। इनको मारशल कोम डिक्लेयर किया जाए और इनकी अलग फौज तैयार की जाए। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, मैं एक और जरूश्री बात कहना चाहता हूं और वह है एग्रीकल्चरल प्रोडयूस। चेयरमैन साहब, किसान जो चीज पैदा करता है उसको पूरी कीमत नहीं मिलती है और इसका नतीजा यह है कि आज हमारा किसान कर्जे के नीचे दब गया है। हमारा किसन दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। चेयरमैन साहब, 1967 में राव सरकार आई थी और उन्होंने उस वक्त किसान को उसकी फसल का पूरा भाव दिया था। उस वक्त यह कहावत थी कि राव आया भाव आया, राव गया भाव गया। राव सरकार ने मकई, बाजरा और ज्वार का पूरा भाव दिया था। आज बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि चीनी महंगी हो गई। मैं कहता हूं कि पिछले दो सालों से किसानों को गन्ने की कीमत नहीं दी गई और इसीलिए उसने गन्ना बोना छोड़ दिया। जब गन्ना ही नहीं बोया तो चीनी कहां से सस्ती मिलेगी। राव की मिनिस्ट्री में जब मैं वजीर था तो हमने गन्ने का भाव बाइस रूपए क्विंटल का दिया था। चीनी का भाव उस समय एक रूपया चालीस पैसे था और आटा हमने उस समय आठ आने किलो लोगों को दिया था। आज हमारी

खुशकिस्मती है कि राव साहब सैन्टर में ऐग्रीकल्चार मिनिस्टर हैं। अब किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिलेगा और कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। मैं अपने चीफ मिनिस्टर सहाब से प्रार्थना कता हूं कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी से कहकर डिफैन्स का महकमा भी राव साहब को दिलवा दें क्योंकि डिफैन्स का महकमा और ऐग्रीकल्चर का महकमा कोरिलेटिड हैं, इन्टर–कनेक्टिड हैं। अगर डिफैन्स का महकमा भी राव साहब को दे दिया जाए तो वे अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि जो परचेजिंग सेन्टर सरकार ने बना रखे हैं, उनकी तरफ सरकार जरा ध्यान दे। किसान जो मंडियों में अनाज लाते हैं और ऊपर से बरसात हो जाती है तब वहां सारे का सारा गेहूं किसान का भीग जाता है क्योंकि वहां पर जो अनाज के लिये खाले हैं, वे कच्चे हैं, उनको पक्का किया जाए ताकि किसान को किसी किस्म की तकलीफ न हो और न ही उसका अनाज खराब हो।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं पशु पालन के मंत्री, वर्मा साहब से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो आर्टीफिशल इनसेमीनेशन सेन्टर्ज गांवों में खोल रखे हैं, उनको बन्द कर दिया जाए। चेयरमैन साहब, जब मैं इस विभाग का मंत्री था तब मैंने यह सुझाव दिया था कि इन सेन्टर्ज को बन्द कर दिया जाए क्योंकि इससे केवल काउज ही कामयाब हैं, बफैलोज को इससे कोई

फायदा नहीं है। वे फेल हैं। अतः सरकार से मैं यह कहूंगा कि इन सेन्टर्ज को बन्द करके इस पर से जो पैसा बचे उसे इरीगेशन के कामों पर खर्च किया जाए ताकि लोगों को इससे फायदा हो सके।

इसके साथ–साथ चेयरमैन साहब, मैं एक बात और अपनी सरकार से कहना चाहात हूं कि जो पुराने तालाब हैं, बेकार हो चुके हैं, जिनका पानी न पशु पीते है और न किसी और काम आता है, उन्हें लोगों को पट्टे पर दे देना चाहिये ताकि लोग वहां पर मछली पालन का काम कर सकें। इस तरह से यहां की फूड प्रौबलम भी हल हो सकती है और लोग इससे काफी फायदा भी उठा सकते हैं और ऐसा करने से सफाई वगैरह भी रहेगी। चेयरमैन साहब, मैं यह कहूंगा कि इन अपोजीशन के भाईयों की बातों पर ध्यान न देते हुए, ये तो यूही क्रिटीसिजम करेंगे, इस बजट को पास कर दिया जाए। ठोक बजा कर पास किया जाए, इस तरह का बजट पहले कभी नहीं आया। चेयरमैन साहब, मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं।

चौ. जय नारायण (कलानौर–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं डिमांड नम्बर 17, 14, 18 पर बोलना चाहता हूं। जैसा कि अभी हमारी कई लायक दोस्तों ने काफी डिमांडज पर बोलते हुए अपने ख्यालात रखे और बताया कि हमारा जो हरियाणा प्रदे ा है, यह कृशि प्रधान दे ा है, इसके अन्दर 80–85 प्रति ात लोग खेती के ऊपर निर्भर करते हैं और यह आपको पता ही है

कि खेती करने वाले लोग हमे ा ही मेहनती गिने जाते हैं उनको खेती के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी का महीना हो या गर्मी का महीना हो, वह अपने खेत में काम करता रहता है और खून पसीने की कमाई खाता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस किसान के साथ एक गरीब मजदूर भी उतनी ही मेहनत करता है। लेकिन किसान के सामने काफी दिक्कतें और मुसीबतें होती है। जैसे कि किसान को डीजल की सबसे बड़ी प्रोबलम होती है, खेती के लिए किसान बेचारा मारा मारा फिरता है। सरकार की तरफ से इन चीजों को मुहैया करने के बारे में कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती है। फिर भी यह सरकार कहती है कि हम गरीब किसानों की भलाई के लिए, हरिजनों की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सारे प्रदे ा के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। चेयरमैन साहब, अभी थोड़ा ही समय बीता है मेरे हल्के के 15–20 गांव ऐसे हैं जहां पर कि अभी ओले पड़े हैं। जब इस बारे में सरकार से पूछा गया कि सरकार वहां के लोगों की क्या मदद करने जा रही है तो सरकार ने इतना कह कर टाल दिया कि अभी इस बारे में सूचना हमारे पास नहीं है। इसकी सूचना आने में कुछ समय लगेगा। चेयरमैन साहब, मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से दूसरी चीजों का सरकार बीमा करती है उसी तरह से किसानों की फसलों का भी बीमा होना चाहिए। (तालियां) मेरी यह सरकार से रिकवेस्ट है।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 14 पर बोलना चाहता हूं। जो फूड एंड सप्लाइज के बारे में है। श्रीमति इंदिरा गांधी पब्लिक में और रेडियो पर भी लम्बे लम्बे हाथ करके भाशण देती हैं कि यह जनता पार्टी की हकूमत नहीं जिसने पब्लिक को, दे ा को नीचे ला कर छोड़ दिया। हम तो दे ा को आगे ले जाना चाहते हैं। चेयरमैन साहब, मैं उनको व इस हाउस के मैंबर साहेबान को यह बताना चाहता हूं कि जिस वक्त जनता पार्टी का राज था, तो उस वक्त रा ान कार्डो को खूंटे पर टांग दिया था और हर चीज खुली मिलती थी और उस वक्त सारे दे ा को पता है कि चीनी का भाव कितना नीचा था और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि चीनी हो, मिट्टी का तेल हो, या डीजल हो, सब चीजों के लिए हमारी बहु बेटियों व ीाइयों को लाइनों में लगना पड़ता है। आज ये बात करते हैं कि हमने पब्लिक के लिए पता नहीं क्या कुछ किया। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर महोदय, आज आप देखें बजाारों में महंगाई की वजह से त्राहि त्राहि मची हुई है। चीनी 7 रूपये किलो तक जा रही है और जनता पार्टी के राज में ढाई पौने तीन रूपए किलो तक चीनी बि रही थी। डीजल का मैं आपको बताऊं कि ब्लैक में बिक रहा है यह सब कुछ इस कांग्रेस पार्टी के राज में हो रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप को क्या क्या बताऊं। कांग्रेस पार्टी यहां पर दम भरती है कि हम गरीब किसान, हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे कि वे ऊपर उठें। आपको पता

है और आपने भी पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा और यहां हाउस में भी चर्चा हुई कि हरिजन महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनकी झोंपड़ियों और मकानों को जलाया गया।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 18 के ऊपर बोलना चाहता हूं जोकि प ाुपालन विभाग से सम्बन्धित है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि आजकल प ा भी इन्सान से कम कीमत के नहीं हैं। आप एक एक प ा 5–5 हजार और 10–10 हजार रूपये का है। इसलिये मेरी सरकार से रिकवेस्ट है कि हर गांव में एक मवे ियों का हस्पताल अव य होना चाहिए क्योंकि हमारे गांवों के जा गरीब किसान और मजदूर हैं, उनको प ाुओं को बीमारी के लिए इलाज करवाने के लिए दूर दूर के हस्पतालों में ले जाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुझे पूर्ण आ ाा है कि सरकार अव य इस पर ध्यान देगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 16 पर अपने विचार रखना चाहता हूं जोकि ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित है। मेरे हल्के में जोकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं, वहां पर कम से कम 10, 15, 20 गांवों के आदमी आत जाते हैं और वे वहां से बस पकड़ते हैं। मेरे हल्के कलानौर में मुख्य मंत्री महोदय गये थे और हमने एक बस स्टैण्ड बनाने के बारे में उन से रिकवेस्ट भी की थी और उन्होंने हमें आ वासन भी दिया था कि यहां पर बस स्टैण्ड बना दिया जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस तरफ कोई

ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बारे में अव य कोई कार्यवाही की जाए ताकि जो लोग वहां से आते जाते हैं, उनको आने जाने मे ंकोई दिक्कत न हो।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात कहूंगा कि मेरे हल्के में 5 हजार एकड़ के करीब जमीन ऐसी है जिसकी पानी की कमी के कारण सिंचाई नहीं हो सकती। इतनी उपजाऊ जमीन होतें हुए भी वहां लोग पानी की कमी के कारण का त नही ंकर सकते और किसान बेचारा अपने बच्चों के पालन पोशण के लिए एक–एक किल्ले जमीन गिरबी रखकर के अपना गुजारा करता है। किसानों की इतनी समस्याएं हैं कि वह बेचारे ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। अतः मेरी सरकार से रिकवेस्ट है कि वहां पर जल्दी से जल्दी रजवाहे बनाये जाएं जिससे कि किसानों की मजबूरी दूर हो सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वहां पर काफी लोगों ने ट्यूबवैल्ज लगाने की कोि ा ा की है लेकिन इस भूमि के अन्दर खारा पानी निकलता है। अब मैं पीने के पानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर पीने के पानी की समस्या बड़ी तकड़ी है। मेरे हल्के में एक बांव पटवापुर पड़ता है। वहां के लोग पिछले 30–35 साल से जोहड़ो ं का पानी पीते हैं। बार बार सै ान के अन्दर मैंने जिक्र किया है और मंत्री महोदय को भी कहा है लेकिन उसके बारे में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

उप–श्रम मंत्री (चौधरी लाल सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी मेरे भाई ने बताया कि लोग जोहडों का पानी पीते हैं लेकिन आज तक इन्होंने कभी यह तकलीफ नहीं की कि दो लाइनों की चिट्ठी लिख कर हमें भेज दें।

चौधरी जय नारायण: मैंने इस संबंध में राठी साहब से कई बार बात की है कि उस गांव में पानी की इतनी भारी समस्या है। अगर हम इनको चिट्ठी लिखे तो इनको पढ़ना तो आता नहीं, काम क्या करेंगे। ये अपने को पुराना ग्रेजुएट समझते हैं। (हंसी) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

चौधरी कर्म सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, मैं मांग संख्या 14, 15, 16, 17, 20, 22 और 23 पर बोलूंगा। मांग संख्या 14 फूड एंड सप्लाइज से सम्बन्धित है। इसमें डीजल, मिट्टी का तेल और चीनी का जिक्र करूंगा। आज तक गवर्नमैंट ने डीजल की ब्लैक की रोक थाम के लिए कोई पाबन्दी नहीं लगाई है। मेरे हल्के के साथ पंजाब का एरिया लगता है वहां पर 6 रूपये लिटर के हिसाब से डीजल आम ब्लैक में बिकता है। लेकिन आज तक उसकी कोई रोकथाम नहीं की गई है। इसी तरह से देहातों के अन्दर चीनी इतनी रखी हुई है, जिसका कोइ अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। आज तक उसकी भी कोई इन्कवायरी नहीं की गई है। जो चीनी डिपोज में जाती हैं उसमें लोग सलफर वगैरह मिला देते हैं, उसकी भी रोकथाम नहीं की गई है। अब मैं डिमांड नम्बर

15 पर आता हूं जो इरीगे ान से सम्बन्धित है। एम.आई.टी.सी. द्वारा जो खाल पक्के किये जाते हैं उसके लिये कहा तो यह गया है कि आधा खर्चा किसान देगा और आधा सरकार देगी। पब्लिक के जलसों के अन्दर ऐसी बातें कही गई हैं कि सारा खचर्चा सरकार करेगी लेकिन हो इसके उलट रहा है यानी सारा खर्चा किसान पर पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस खर्चे को किसान पर न डाला जाए। इससे किताब को राहत मिलेगी। इसलिये किसान को इससे छूट देनी चाहिए। यहां पर जिक्र आया कि नहरें पक्की करने की वजह से 1 लाख 37 हार हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का फायदा होगा और इससे आबियाने में 80 लाख रू की सालाना बढ़ौतरी होगी। मेरा कहना है कि इस बढ़ौतरी को देखते हुए किसान को और ज्यादा सहुलियत दी जानी चाहिए। दूसरी बात बिजली के बारे में है। पहले बिजली जब पूरा टाइम मिलती थी तो उस समय बिजली के फलैट रेट मुकर्रर किया गये थे। आज तीसरे दिन 4–5 घंटे बिजली मिलती है और उसमे भी वोलटेज कम होती है। इसलिये यह फलैट रेट भी कम रकने चाहिए। वोलटेज कम होने की वजह से काफी लोगों की मोटरें जल गई हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस खर्चे को भी बर्दा त करना चाहिए। इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 16 पर आता हूं। यह डिमांड इंडस्टरी से संबधित हैं जो पढ़े लिखे नौजवान देहातों में बैठे हैं उनके लिये देहातों में इंडस्ट्रीज लगाई जानी चाहिए। इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 17 पर बोलूगा जो खेती के बारे में हैं। खेती मे ंभी इंडस्टरी की तरह पहले बहुत पैसा खर्च किया

जाता है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। लेकिन कुदरत की तरफ से कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है, तो कभी सूखा पड़ जाता है तथा ओर भी कई किस्म के ऐस नुक्सान होते हैं जिनका मुकाबिला करना किसान के लिए बहुत मु कल हो जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि किसान की फसल का बीमा होना चाहिए। स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आज तीन एकड़ से कम के जो जमींदार हैं या छोटे किसान हैं उनको खाद, बीज और आबियाने पर 50 प्रति ात की छूट दी जानी चाहिए। इसके बाद मै। डिमांड नम्बर 22 पर आता हूं जोकि कोआप्रे ान डिपार्टमैंट के बारे में है। यह बहुत जरूरी महकमा है और अगर इसको ठीक ढंग से चलाया जाए तो इससे किसानों और दूसरे पिछडे वर्गों को बहुत फायदा हो सकता है। बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। इसी से संबंधित मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि 1972–73 में कुछ लोगों ने हरिजनों से अंगूठे लगवा कर झूठे कर्जे ले लिये थे लेकिन उस बारे में आज तक कोई इन्कवायरी नहीं हुई। उन हरिजनों के नाम आज असली रकम से सूद इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। यह केस महकमे के पास मौजूद है। अगर अदालत में हो तब तो देरी के लिए किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन जब केस महकमे के पास है तो इसका निपटारा जल्दी क्यों नहीं किया जाता है। इसके बाद इस महकमें में चार एंडी ानल रजिस्ट्रार्ज की प्रोमो ान की गई हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तहसील लैवल पर एक असिसटैंट रजिस्ट्रार

होना चाहिए। क्योंकि जो गबन होते हैं वे ज्यादा नीचे से ही होते हैं। इसलिये तहसील लैवल पर ए.आर. का होना बहुत जरूरी है। एक बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही थी कि दो हजार की आबादी वाले गांवों में कंज्यूमर स्टोर खोले जाएंगे। मैं कहता हूं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर पटवार सर्कल में मिनी बैंकस है उनके जरिये से सारी चीजें लोगों को मुहैया की जा सकती है। इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो खाद सोसाइटीज की मार्फत मिलती है वह बहुत निकम्मी मिलती है। जब हम बाजार से चीज लेते हैं तो अच्छी तरह से परख कर लेते है। जो सोसाइटीज खाद देती हैं पैसे तो वे भी लेती हैं इसलिये इस चीज में भी सुधार लाया जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला (ाहबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 14 पर बोलना चाहता हूं जोकि फूड एण्ड सप्लाई के बारे में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सराकर से दरख्वास्त करूंगा ओश्र सरकार को इस बारे में पता भी है कि डीजल की कमी सिर्फ हमारे हरियाणा में ही नहीं है बल्कि सारे भारतवर्श में बड़ी भारी मात्रा में कमी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ट्रेक्टरों के लिए जो डीजल का कोटा था वह घटा कर 100 लीटर महीना कर दयिा है इसलिए मेरी फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि आप यह महसूस कीजिए कि

100 लीटर डीजल से एक ट्रेक्टर 16 घंटे चल सकता है और यदि एक ट्रैक्टर 16 घंटे एक महीने में चले तो आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कृशि की क्या हालत होगी। इसलिए मेरी सरकार से अर्ज है कि यह कोटा बढ़ा करके कम से कम 100 लीटर पर सप्ताह कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं डिमान्ड नम्बर 15 पर बोलना चाहता हूं जोकि इरीगे ान के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, इरीगे ान की मांग पर बोलते हुए मैं अपनी कांस्टीच्युऐंसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की कांस्टीच्युऐंसी भी मेरी कांस्टीच्युऐंसी के साथ ही लगती है इनको पता भी है कि हमारी कांस्टीच्युऐंसी मे ंपानी की सतह 10 फिट पर थी। इस वक्त भाखड़ा कैनाल पर ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं। इन ट्यूबवैल्ज के कारण वहां पर पानी की सतह 35–40 फिट नीचे चली गई है इसलिए जमींदारों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आजकल ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली की भी बहुत कमी है, डीजल की भी कमी है और पानी की भी कमी हो गई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो औगमैनटे ान कैनाल पर ट्यूबवैल्ज लगाए हुए हैं यदि उनको बन्द नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका मुंह किसनों के खेतों की तरफ कर दिया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं इरीगे ान के बारे मैं ही एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि मारकन्डा के ऊपर भााहबाद में एक पुल इस वक्त बनाया जा रहा है। हमारे ईगे ान मिनिस्टर साहब यहां हाउस में बैठे हैं और चीफ इंजीनियर साहब भी बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि

भााहबाद में मारकन्डा पर 1100 फिट लम्बा पुल बनाया जा रहा है और इस पुल से 25 किलोमीटर के फासले पर इसी नदी पर एक गांव झांसा है, वहां पर 200 फिट लम्बा पुल बना हुआ है। जो पानी 1100 फिट पुल के नीचे से गुजरेगा क्या वह 200 फिट लम्बे पुल के नीचे से गुजर सकता है ? वह पुल छोटा होने की वजह से पानी ओवरफलो हो जाता है और उस इलाके के 20–25 गांवों के अन्दर दाखिल हो जाता है जिसके कारण गांवों को बहुत ज्यादा नुक्सान होता है। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मेरी इस बात पर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा मेरे हल्के में 15–20 गांव ऐसे हैं कि झांसा गांव में भाखड़ा कैनाल और एस. वाई.एल. पर, उनके नजदीक पुल न हेाने की वजह से उन गांवों से कुरूक्षेत्र आने के लिए उनको 20–25 मील का फासला ज्यादा तय करके आना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर दो पुल बनाये जाएं लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। यह पुल मारकन्डा नदी से उतर की तरफ झांसा गांव में भाखड़ा और एस.वाई.एल. पर बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एग्रीकल्चर की डिमान्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह हमारे सरदार साहब का महकमा है और ये हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैने इनसे पहले भी दरख्वास्त की थी और अब हाउस में भी सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने एक नोटिफिके ान जारी किया था कि कोल्ड स्टोरेज का किराया 10 रूपए पर बैग लिया जाएगा लेकिन इस सरकार ने वह नेाटिफिके ान वापिस ले लियसा है इसलिए मेरी

सरकार से प्रार्थना है कि जमींदारों को राहत देने के लिए यह सरकार भी कोल्ड स्टोरेज के किराया का 10 रूपए पर बैग के हिसाब से नोटिफिके ान जापरी करे ताकि सिाकनों को कुछ राहत मिल सके। आजकल कोल्ड स्टौरेज वाले सढ़े बारह रूपए पर बैग के हिसाब से किराया चार्ज कर रहे हैं। स्पीकर साहब, भााहाबाद में कोल्ड स्टोरेज वालों की इस मनमानी को रोकने के लिए एक हैफैड का कोल्ड स्टोरेज भी भााहबाद में लगना जरूरी है। स्पीकर साहब, मैं इसके अलावा ऐनीमल हसबैंडरी की डिमान्ड नम्बर 18 पर कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वर्मा साहब इस महकमें के वजीर हैं। मैं वर्मा साहब को इस बात के लिए घन्यवाद देता हूं कि वे सभी एम.एल.एज. को पूछ करके इक्वल डिस्ट्रीब्यू ान से गांव गांव में प ुओं के अस्पताल खोल रहे हैं। इसके अलावा मैं फि ारीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के नोटिस में भी यह बात होगी कि गांवों के अन्दर बड़े बड़े जोहड़ होते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक जोहड़ एक गांव के अन्दर होती ही हैं। उन जोहड़ों का पानी सिवाये प ुओं के पिलाने के और कहीं भी युटिलाइज नही ंहोता है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए सरकार एक स्कीम चालू करे। उन जोहड़ों को 99 साल या उससे कम लीज पर किसी भी फार्मर को दे दिया जाए ताकि वे मछली पालन का काम कर सकें। अध्यक्ष्ज्ञ महोदय, इसके अलावा मैं फारेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले इस प्रद ा के अन्दर एक स्कीम थी जो भी कोई किसान अपने खेतों के अन्दर सफेदे

या दूसरे दरखत लगवाना चाहता थ फारेस्ट डिपार्टमैंट उसको फ्री आफ कास्ट दरखत लगा कर, एक साल तक उन दरखतों की देखभाल करने के बाद वह जमीन किसान को सौंप देता था। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि उस स्कीम को अब फिर लागू किया जाए और दरखतों की प्लांटे ान का काम सरकार की तरफ से होना चाएि। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपकी मारफ्त सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में कोआप्रेटिव बैंकों में डायरेक्टर्ज के इलैक ान हो चुके हैं लेकिन चेयरमैंन के इलैक ांज नहीं हुए हैं। मैं समझता हूं कि चेयरमैंन के इलैक ान न होने के कारण ये हैं कि इसमें पोलिटिकल दखलअन्दाजी है। चेयरमैंन के इलैक ान के लिए 10—10 गैर सरकार डायरेक्टर होते हैं और इस समय 6 सरकारी डायरेक्टर हैं। मेरी सरकार से गुजारि ा है कि डैमोक्रेसी को कायम रखने के लिए सरकारी डायरक्टरों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष माहेदय, इसके अलावा मैं ट्रांस्पोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ट्रास्पोर्ट का काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूं कि बस स्टैण्ड की बिल्डिंग्ज के लिए पैसे बहुत कम रखे गए हैं, और कई जगहों पर जहां जरूरत ह वहां वर्क ाप भी नहीं बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर इस बारे में गौर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म डिपार्टमैंट के बारे में हमारे विपक्ष के नेता बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी काफी सुझाव हाउस के सामने रखे। मैं भी इस विभाग के मिनिस्टर साहब को और खास

करके मैं मिश्रा जी को बधाई देना चाहता हूं जोकि उस डिपार्टमैंट के आफिसर हैं। इस डिपार्टमैंट का काम अच्छा होने की वजह से हरियाणा प्रान्त सारे दे ा के अन्दर म ाहूर है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सरकार से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने सुझाब दिए हैं उनके ऊपर गौर करें।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर 14 पर बोलना चाहता हूं जो कि फूड एण्ड सप्लाई के बारे में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आने फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि डीजल, मिट्टी का तेल और सीमेंट का जो वितरण है वह बड़ा डिफैक्टिव हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के पलवल के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर जो सीमेंट का वितरण होता है वह जिन आदमियों को 2–2 सीमेंट के कट्टों की छोटी मोटी मरम्मत के लिए जरूरत होती है उनको तो परमिट दिया नहीं जाता और दूसरे लोगों से पैसा लेकर उनको 200–200, 250–250 और 500–500 सीमेंट के कट्टों का परमिट दे दिया जाता है। मैं परमिट देने वाले मुलाजिम का नाम नहीं लूंगा। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इन चीजों की रोकथाम करवाएं। मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि सीमेंट, डीजल बगैरह का वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। अगर इस प्रणाली को ठीक करवाने की कोि ा ा की जाए तो गरीब आदमियों को उनके हिस्से की चीज मिल सकती हैं।

13.00 बजे

स्पीकर साहब, अब मैं मांग सं. 15 के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में एक आगर कैनाल है। इस नहर में पानी चलता है लेकिन इस नहर का कन्ट्रोल यू.पी. सरकार का है। यू.पी. सरकार के नियंत्रण में होने की वजह से हमारे इलाके के जमीदारों को पानी नहीं मिलता। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस नहर का कन्ट्राले अपने हाथ में ले लिया जाए। अगर अपने हाथ में नहीं ले सकते तो कम से कम यू.पी. सरकार को मजबूर तो करे कि वे हमारे जमींदारों को पानी दे। हमारे जमींदार पानी के बिना परे ाान हैं, सरकार इस औरन ध्यान दे ताकि किसानों की समस्या हल हो सके।

अब मैं उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा। पलवल में एक आई.टी.आई. है। वह बिल्डिग तो बहुत बड़ी है लेकिन ट्रेड्ज बहुत कम हैं और काफी कमरे खाली पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक साल से आई.टी.आई में प्रिंसिपल नहीं हैं, कई प्रोफैसर नहीं है और दो सला से स्टैनों टाईपिस्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि उस आई.टी.आई. का क्या लाभ जहां पर न प्रिंसिपल है और न स्टाफ है। मैं सरकार से गुजारि ा करूंगा कि वहां पर ट्रेड्ज बढ़ाई जाएं और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। जहां तक कृशि का सम्बन्ध है, किसानों को न तो खाद मिल रही है, न बीज और न बिजली। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि दे ा की

प्रोडक्शन बढ़ सकें और जमींदारों की बिजली और खाद की समस्या हल हो सके।

(इस समय कई मैम्बर बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः साहिबान, मैंने सब मैम्बर साहिबान को बोलने के लिए मौका देना है। जो साहिबान बोलने से रह गये हैं, उनको ऐप्रोप्रिएशन बिल पर मौका दिया जाएगा। जो पार्टी लीडर्ज हैं, मैं उनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि वे अपने अपने मैम्बर साहिबान के नाम मुझे भेज दें, जिन मैम्बर साहिबान को गवर्नर ऐड्रेस, बजट डिस्कशन और डिमांड्ज, पर बोलने का मौका नहीं मिला, उनके नाम पार्टी लीडर्ज मेरे पास भेज दं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जिनको पहले मौका नहीं मिला है, उन सब को ऐप्रोप्रिएशन बिल पर टाईम दिया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री जगन्ननाथ): अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं 27 पर बाबू मूल चन्द जैन की तरफ से कट मोशन्ज आई हैं जिसमें लिखा है कि सम्भालखा के अन्दर बस स्टैन्ड नहीं बनाया है। अध्यक्ष महोदय, जैन साहब हमारे हाउस के सबसे सीनियर मैम्बर है, लोक सभी में भी मैम्बर रहे हैं और दो दो महीने कई बार मिनिस्टर भी रह चुके है। ऐसे सीनियर मैम्बर को चाहिए था कि किसी पालिसी मैंटर पर कट मोशन देते तो बात ठीक थी। यह क्या बात हुई कि सम्भालखा में बस स्टैन्ड बनाया जाए ? सम्भालखा में बस स्टैन्ड न बनने का मेरा कसूर नहीं है, आपका

अपना कसूर है, आपने बनाने ही नहीं दिया। आपने यहां पर कह दिया कि इसको न बनाने के लिए आफिसर जिम्मेवार हैं। जिस वक्त आप मंत्री थे उस वक्त आपने रूकावट डाली थी। 50 हजार रूपया अलाट भी कर दिया था, इसके बावजूद भी आपने बस स्टैन्ड बनने नहीं दिया, क्योंकि उस समय आपकी वि ोश दिलचस्पी थी, इसलिए रूकावट डाली गई, इसमें मेरा दोश नहीं है।

श्री मूल चन्द जैनः न बनाने मे मेरा क्या इन्ट्रैस्ट हैं और क्या हो सकता है, न मेरा मकान वहां है, न कोई और इन्ट्रैस्ट हैं, I am very sorry. (व्यवधान)

श्री जगन नाथः आपने यहां कहा कि ट्रांसपोर्ट के आफिसर काम नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि पैसेंजर टैक्स, रोड टैक्स, टोकन टैक्स और दूसरे कई टैक्सिज से 35 करोड़ रूपया मेरे महकमें ने स्टेट एक्सचैकर के लिए दिया और यह पैसा कौन से हैड में डाल दिया है, यह फाइनैंस डिपार्टमैंट वाले जानते हैं। इसके अतिरिक्त अढ़ाई करोड़ के करीब इस साल प्रोफिट हुआ है जबकि इस साल स्टेट में कहर पड़ा हुआ था, हड़ताल हुई और इलैक ान का भी प्रभाव पड़ा। डीजल भी मंहगा है। इन सारी चीजों के होत हुए प्रोफिट हुआ है। ये किस मुंह से कहते हैं कि इस डिपार्टमैंट के आफिसर कामन नहीं करते। जहां तक मैं समझता हूं, यह महकता सबसे ज्यादा एफि ाएंट है। स्पीकर साहब, श्री मूल चन्द मंगला ने कहा था कि पलवल में बस स्टैन्ड

नहीं बनाया जा रहा। अध्यक्ष महोदय, श्री रामपाल सिंह, पी.डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर बैठे हैं, हम बस स्टैन्ड पी.डब्ल्यू.डी. के थ्रू बनवाते हैं। चाहे बस स्टैन्ड है, चाहे वर्क ाप है, जो भी कंस्ट्रक ान करनी हो, पी.डब्ल्यू.डी. करता है और इस काम के लिए हमने इनके पास एक करोड़ 80 लाख रूपया जमा करवा रखा है। जींद के डिपो में भी पानी भर जात है, वहां का बस स्टैन्ड भी खराब है, इसको भी बनाना है लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. की मजबूरी है क्येांकि आजकल सीमेंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम पूरी कोि ा ा कर रहे हैं कि नये बस स्टैन्ड जल्दी से जल्दी बनाये जाएं। श्री हरस्वरूप बूरा ने सरपंचों को फ्री पास देने के सिलसिले में कहा। मास्टर ि ाव प्रसाद जी ने भी कहा कि मास्टरों को फ्री पास होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने विद्यार्थियों को फ्री पास दिए हुए हैं, जो एक समस्या बनही हुई है। इस कंसै ान का विद्यार्थी बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। रोजाना भााम के टाईम पर हर एक डिपो पर, बस स्टैन्ड पर हजारों लड़के जाते है। ये खुद तो चढ़ जाते हैं लेकिन दूसरी सवारियों को चढ़ने नहीं देते। लोगों को तीन–तीन घंटे बस स्टैन्ड पर खड़े हुए हो जाते है। इस कंसै ान के कारण हमें बहुत नुक्सान हो रहा है क्योंकि सवारियों को चढ़ने नहीं देतें, धक्के मार मार कर परे ाान करते हैं। इस विशय पर गम्भीरता से गौर करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों का यह कंसै ान बन्द कर दिया जाए या कंटीन्यू रखा जाए। श्रीमति सुशमा स्वराज ने अम्बाला कैंट में बस स्टैन्ड बनाने के बारे में जिक्र किया। बस स्टैन्ड तो पहले बना हुआ है लेकिन उनकी यह बात सही है कि

वहां पर ज्यादा बसें आती है। यमुनानगर का डिपो बनने से अम्बाला बस स्टैंन्ड पर बसों का प्रै ार कुछ घटा हैं, लेकिन फिर भी हम कोि ा ा कर रह हैं कि अम्बाला कैंट का बस स्टैन्ड बड़ा बनें। लेकिन मुि कल यह है कि वहां जमीन नहीं मिलती। हमने डिफैंस मिनिस्टर के साथ बातचीत की कि उनसे जमीन मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकी। अब वे मान गये हैं, उन्होने लोकल बाडीज को जमीन ट्रांसफर कर दी है। अब लोकल बाडीज के मिनिस्टर चौधरी खुर ाीद अहमद हैं, इनसे कहें कि इस बस स्टैन्ड को जल्दी से जल्दी बड़ा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा हाउस में दलबदलू की बातें करते रहे, हरियाणा के अन्दर दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं हैं। आम तौर पर सभी ने दल बदला है। लेकिन जो कुछ ये लोग कह सकते हैं, वह भाायद दूसरे लोग भी कहेंगे। अध्यक्ष्ज्ञ महोदय, 8 मई, 1978 को दिल्ली में हम सब गए थे, ये साहिबान भी गये थे। वहां पर श्री यज्ञदत भार्मा, एम.पी. के घर मीटिंग हुई। श्री मुख्तियार सिंह भी वहां पर थे, श्री इन्द्रजीत सिंह भी थे। वहां पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग का हवाला आल इंडिया रेडियो पर भी आया। श्री राम लाल वधवा ने आकर कह दिया कि कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये लोग, डा. मंगल सैन .... हैं (व्यवधान) इन्होंने कैसे कह दिया कि मीटिंग नहीं हुई ? (व्यवधान)

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ..... भाब्द का इस्तेमाल किया है। वह ऐक्सपंज होना चाहिए।

Mr. Speaker: I have not heard that. I will examine the record. If there is anything irrelevant, I will get that expunged.

अब मैं हाउस की सैन्स लेना चाहता हूं कि क्या हाउस का कुछ समय बढ़ा लिया जाए क्योंकि अभी तीन मिनिस्टर साहेबान ने बोलना है और उसके बाद डिमांड्ज पास होनी हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अभी काफी समय है। उम्मीद है समय बढ़ाने की कोई आव यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे बारे में जो कहा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं बाद में आपको टाईम दे दूंगा। वैसे डाक्टर साहब ने यह बात पहले कह दी है और अगर ऐसी कोई बात कही गई है तो उसे मैं ऐक्स्पंज करवा दूंगा।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): स्पीकर साहब, जैन साहब ने हाउस में फरमायसा था कि हरियाण टूरिज्म कार्पोरे ान के अन्दर गवर्नमैंट का भोयर कैपिटल हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हरियाणा टूरिज्म कार्पोरे ान जो है उसके अन्दर सरकार का भोयर कैपिटल इन कै ा नहीं है।

हां, यह बात ठीक है कि बिल्डिंग्ज जिनकी कीमत लगभग 116 लाख रूपये बनती है वह जरूर उसको ट्रांसफर हुई हैं। जैन साहब ने दूसरी बात कही कि टूरिज्म कंप्लैक्स के अन्दर बड़े रईस लोगों के ठहरने की जगह है और उनसे चार्जिज ऐप्रोप्रिएटली नहीं किया जाता। यह भी गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, 15 रूपये से लेकर 250 रूपये तक के कमरे वहां मिलते हैं। जैसा कोई कमरा चाहता है वैसे पैसे उससे ठोक कर लिए जाते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, 15 रूपये किराये की हट्स भी वहां बनी हुई हैं। कौमन मैन को वहां केवल साढ़े चार रूपये में खाने की थाली मिलती है। अगर कोई डि ाज का आर्डर अलग से देता है तो उनके पैसे अलाहिदा चार्ज किए जाते हैं। जैन साहब आप तो व्यापरियों से खूब वाकिफ हैं। चौधरी देवी लाल की मिनिस्टरी के वक्त आप व्यापारियों को प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे पास त ारीफ लाए थे। आप जानते हैं कि जब बिजनैस भ्रुरू किया जाता है तो उसमें इनवैस्टमैंट ज्यादा होती है, रिटर्न उतनी नहीं होती। उसको वायबल यूनिट बनने के लिए कुछ टाईम लगता है। हरियाणा टूरिज्म कार्पोरे ान एक कामि ियल डिपार्टमैंट है, कामि ियल अन्डरटेकिंग हैं ओर कामि ियल कार्पोरे ान है। अब लौसिज बहुत कम रह गए हैं और बहुत तेजी से यह आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदया मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि इन टूरिज्म कंप्लैक्सिज में बोटिंग फैसिलिटीज, लान्ज और दूसरे साईट सीइंग आदि के जो प्रोविजन किए गए हैं वे आम

पब्लिक के लिए हैं। कोई भी वहां जाकर उनसे फायदा उठा सकता है।

भाई राजेन्द्र सिंह जी ने भी कुछ बातें कहीं। एक बात उन्होंने डीजल आदि के डिस्ट्रिब्यू ान के बारे में कही और दूसरी बात में उन्होंने एक अफसर के बारे में ि ाकायत की। अफसर के बारे में ि ाकायत का जहां तक ताल्लुक हैं, उसे यदि ये मेरे नोटिस में पहले लाते तो आज तक उस पर ऐक ान भी हो गया होता। खैर, अब इसे मैं जाते ही देखूंगा और जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही संभव होगी वह मैं करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि किसी अफसर के खिलाफ यदि उन्हें कभी कोई ि ाकायत हो उसे ये मेरे नोटिस में लाएं। मैं यदि कोई ऐ ान न लूं तो ये उस बात को हाउस में लाएं। डिस्ट्रिब्यू ान सिस्टम करवा दिए हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, डिस्ट्रिब्यू ान सिस्टम के बारे में यदि कोई भी मैम्बर कोई चीज मेरे नोटिस में लाएगा और मुझे यह बताएगा कि डिस्ट्रिब्यू ान सिस्टम के अन्दर यह कमी है, इसको तरमीम किया जाए मैं फौरन ऐक ान लूंगा। (विघ्न)

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, आज डिमांडज पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने महकमा जरायत के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। मुझे खु ाी हुई हैं कि अपोजी ान के एक बड़े काबिल और तजुर्बेकार मैम्बर ने महकमा जरायज की काफी तारीफ भी की। (विघ्न) वे मैम्बर हैं ब्रिगेडियर रण सिंह जी।

(विघ्न) स्पीकर साहब, दे ा में इस साल जो खु की पड़ी, यह तकरीबन 75–80 साल के बाद पड़ी है। (विघ्न) इतने खु की के मौसम में जिस ढंग से महकमा ऐग्रीकल्चर ने काम किया है और जिसकी वजह से आज खेतों में फसलें खड़ी हैं, उसके लिए मैं महकमा जरायत के अफसरान को मुबारिकबाद दिए बगैर नही ंरह सकता। (विघ्न) माननीय सदस्यों ने कहा कि जीरी तो आधी भी नहीं हुई। यहां तक कहा कि तीसरे हिस्से की भी नहीं हुई। लेकिन मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि पैडी की फसल बहुत थोड़ी कम रही है। इसका सारा श्रेय महकमा जरायत को जाता है। महकमे की ऐफि ायेन्सी है जिसने बहुत अच्छा काम करके दिखया है।

चौधरी गंगा रामः कागजों पर ही हुआ होगा।

सरदार तारा सिंहः कागजों पर नहीं, प्रैक्टिकल रूप से हुआ है। इसी प्रकार से रबी की फसल की भी यही पोजी ान है। रबी की फसल समय पर बिजली और पानी देने की बजाए से है। आपको पता हैं कि पहले जब सूखा पड़ता था तो भूखमरी फैल जाती थी लेकिन हमारा महकमा जरायत ने बड़ी काबलियत से काम किया जिसके कारण किसानों की बड़ी अच्छी फसल खड़ी है। ब्रिगेडियर साहब ने चीन की बड़ी तारीफ की थी और कहा कि चीन के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पंजाब की बड़ी तारीफ की थी। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों डायरैक्टर फूउ एन्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजे ान, डा. भाोभा ने जब

हरियाणा के गांवों का दौरा किया तो उन्होंने हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद दी कि बड़ी अच्छी फसल पैदा की है। जहां पहले मीलों तक कल्लर पड़ा होता था आज वहां लगातार मीलों तक गेहूं खड़ा है।

स्पीकर साहब कुछ बातें मेरे काबिल दोस्त चौधरी रिजक राम जी ने कही है। वे काफी पुराने एम.एल.ए. हैं। मैं उनकी इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि देहातों में कुछ कमियां है। लेकिन उन्होंने उन कमियों को पूरा करने के लिए सदन के सामने कोई सुझाव नहीं दिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और सिक तरह से उन समस्याओं का समाधाना करना चाहिए। इस बारे में अगर वे कुछ सुझाव देंगे तो उने सुझावों पर हम जरूर अमल करेंगे। स्पीकर सहब, कीमतों के बारे में भी यहां कहा गया है कि प्लानिंग कमी ान वाले अच्छे ढंग से कीमत नहीं लगाते। दूसरे यहां कहा गया है कि ऐग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस की कीमतें भी ज्यादा बढ़ गई है। स्पीकर साहब, जहां तक प्लानिंग कमी ान का सवाल है वह तो सैन्टर का महकमा है। इस बारे में स्टेट गवर्नमैंट कुछ नहीं कर सकती। इस बारे मैं अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो हम जरूर गौर करेंगे।

स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम जी ने यह भी कहा था कि महकमा जरायत में 5–6 स्कीमों को इकट्ठा करके बजट में दिखा दिया गया है जबकि वे अलग अलग दिखाई जानी चाहिए थी। स्पीकर साहब, हाउस को वित मंत्री महोदय ने बताया था कि

इस वर्श जो बजट पे ा किया गया है उसमें ज्यादा पैसा ऐग्रीकल्चर के लिए रखा गया है। जिन भाईयों ने उसको पढ़ा होगा उनको यह सोचना चाहिए था कि बजट में पैसा कम दिया गया है या पहले से बढ़ा कर दिया है। अगर सरकार ने ऐग्रीकल्चर के लिए पैसा बढ़ाया है तो वे वह नाजायज नहीं बढ़ाया।

श्री अध्यक्षः अब आप वाईन्ड अप करिए।

सरदार तारा सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहन सुशमा स्वराज जी ने गांवों के अन्दर लेडीज के लिए पाखाने बनायें जाने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक लाख रूपये सरकार ने इन पाखाने को बनाये जाने के लिए रखे थे लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह एक लाख रूपये नहीं थे बल्कि 6 लाख रूपये थे। साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इन गांवों में पाखाने बनाने में रूकावट है और उनके बनाने में कुछ टैक्निकल डिफिक्लटीज हैं। जब वह डिफिकल्टीज सैन्ट्रल गवर्नमैंट से दूर हो जायेगी तो गांवों में लेडीज पाखाने जरूर बनाये जायेंगें।

चौधरी राजेन्द्र सिंह ने फसलों की ग्रेडिंग के बारे में जिक्र किया है कि फसलों की ग्रेडिंग मार्किट में ठीक नहीं होती है। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि यूनियन मिनिस्टर, राव साहब से हमने रिक्वैस्ट की है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि फसलों की ग्रेडिंग अच्छे ढंग से करेंगे। जिस गेहूं के अन्दर

थोड़ी बहुत नमी या कुछ मिट्टी होगी तो उसको भी रिजैक्ट नहीं किया जायेगा और उकसा ठीक भाव मिलेगा। इं ाोरेंस के मुतालिक कल सरकार ने अपनी पालिसी वाजिब तौर पर बता दी है। श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने डीजल की कमी के बारे में कहा था। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सैन्टर से जो डीजल आ रहा है उसमें से 70 परसेन्ट डीजल गांवों में दिया जा रहा है और इसी प्रकार से 70 परसेन्ट बिजली भी गांवों में खेती के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। यदि फिर भी गांवों में खेती के लिए यह कमी बनी रहती है तो सैन्ट्रल सरकार ने वायदा किया है कि हम और अधिक डीजल देंगे ताकि यह कमी न रह पाये।

जहां तक डीप ट्यूबलैल लगाये जाने का संबंध है, वे ट्यूबवैल मेरे हल्के में भी और दूसरे माननीय सदस्यों के हल्कों में भी हैं जिसके कारण वाटर लैवल काफी नीचे तक चला गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं खुद कोि ा ा कर रहा हूं कि इसका कोई न कोई प्रबंध किया जाये।

कोल्ड स्टोरेज के मुतालिक भी यहां पर कहा गया है। स्पीकर साहब हमारी सरकार ने यह मामला एग्जामिन करवा लिया था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो हमारे हैफड के कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें 15.65 रूपये पर टन खर्चा आता है लेकिन फिर भी हमने उस पैसे को बढ़ाया नहीं है। उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि जो डिमान्डज रखी गई हैं वे पास की जायें।

जेल तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): अध्यक्ष महोदय, यहां पर बोलते हुए मैम्बरान ने कुछ बातें कही हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। चौधरी टेकराम ने एक बात कही। अगर मैं उनके ही भाब्दों को यहां हाउस में रखूं तो अपने आप ही उनकी बात ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि प ाुओं के लिए दवाई दुलर्भ नहीं है। लेकिन मैं उनके ही भावार्थ को ले लेता हूं। उनका भावार्थ यह था कि प ाुओं के लिए गांवों में दवाई नहीं मिलती। स्पीकर साहब, मैं इस सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गल्त बात है। सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध दवाइयों का किया गया है। दवाइयों की कहीं पर कोई कमी नहीं ह। दूसरी बात पोहलू साहब ने गांवों के अन्दर सांड और झोटे छोड़े जाने के बारे में कही है। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि आज पहले वाली बात नहीं रही कि गांवों के अन्दर सांड और झोटा छोड़ देते थे और वह किसी के खेत में फसल खा लिया करते थे और कोई एतराज नहीं करता था। अब वह बात नहीं है। इसीलिए सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की योजना बनाई है। स्पीकर साहब अगर हम वैसे ही सांड और झोटे छोड़ दें तो एक सांड या झोटा केवल 100 गायों या भैसों की सेवा कर सकता है। यदि हम कृत्रिम गर्भाधान करायें तो एक सांड या झोटा एक हजार गाय या भैंस की सेवा कर सकता ह। वह हमें सस्ता पड़ता है इसलिये कम पैसा खर्च होता है और प्रति ाातता भी ज्यादा होती है।

स्पीकर साहब, मैंने सभी एम.एल.एज. से भी कहा था कि आप मुझे बताएं कि कहां और किस हल्के में डिस्पैंसरियों की जरूरत है। मुझे आज ये मैंम्बर साहेबान बतायें कि कौन मेरे पास इस विशय में आया कि मेरे हल्के के अन्दर डिस्पैंसरी चालू की जाये। इसके साथ ही साथ मैं सदन को यह भी बताना चाहात हूं कि सदस्यों का प ाुपालन में कितना इन्ट्रैस्ट है। इससे पता लगता है कि जितने भी सदस्य हैं जो कि आने आप को किसान कहते हैं और उसका दम भरते हैं, वे बतायें कि उन्होंने कितने प ा पाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि प ाुपालन भी खेती के बराबर लाभदायक है। आज तक किसी भी सदस्य ने पु ापालन के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। इससे ही पता लगता है कि उनका प ाुपालन में कितना इन्ट्रैस्ट है। एक सवाल चौधरी रामलाल वधवा जी की तरफ से जरूर आया था कि प्रान्त में कितनी गायें हैं और कितनी भैंसे हैं। उनके पास तो अपनी कोई गाय या भैंस तक नहीं है। उस आदमी ने यह सवाल पूछा है जिसके पास अपना कोई प ा तक नहीं है जिन साथियों के पास प ा हैं उनमें से किसी ने भी इस संबंध में सवाल नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, इस विशय में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि पिछले साल चौधरी देवी ला जी की सरकार जो अपने आपको किसानों की सरकार कहती थी और बाबू मूल चन्द जैन जिसमे वजीर थे उस सरकार ने हरियाणा में केवल 20 डिस्पैंसरियां खोली थी ओर अगले साल के लिए उस सरकार ने केवल 20 डिस्पैंसरियां खोलने का प्रावधान रखा था। लेकिन हमारी सरकार

ने बजट के अन्दर 20 डिस्पैंसरियों का प्रावधान होने के बावजूद भी दूसरी गैर जरूरी स्कीमों को पीछे करके बिना कोई ऐडी ानल पैसा लिए 100 डिस्पैंसरियां खोली हैं। इस प्रकार से हमने 200 डिस्पैंसरियों का प्रबन्ध किया। अगर इन लोगों का इन्ट्रैस्ट होता तो ये मेरे पास आते और कहते कि मेरे हल्के में डिस्पैंसरी खोली जाये। सदस्य साहेबान से मैं यह अर्ज करूंगा कि प ुपालन में वे अपना इन्ट्रैस्ट बढ़ाएं और इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाये ताकि हरियाणा की डिवैल्पमैंट हो सके।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: I think we will have to extend the sitting.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): पन्द्रह मिनट के लिए सिटिंग बढ़ा दी जाये।

Mr. Speaker: The sitting is extended by 15 minutes.

वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री बलवन्त राय तायल): स्पीकर साहब, फाइनैन्स पर आज बहस खत्म करते हुए जो डिमान्डज हाउस के

सामने आई हैं उनके बारे में कुछ लोगों ने हाउस के सामने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं और मैं समझता हूं कि उनको मानने मे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू मूल चन्द जैन ने जिस भाान्ति से सुझाव रखे है वे बड़े सराहनीय हैं। एक सुझाव तो उन्होंने कार्पोरे ान्ज के बारे में दिया है कि कार्पोरे ान्ज की बैलन्स भीट हाउस के सामने आनी चाहिए। हमे कार्पेरे ान्ज की बैलन्स भीट्स हाउस के सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भविश्य में इन बैलन्स भीट्स को हाउस के सामने रख दिया जायेगा ताकि सभी मैम्बर साहेबान उनको देख सकें। जैन साहब ने एच.एस.आई. डी.सी. के बारे में भी कुछ सुझाव दिया है। उन्होंने इसको इस बात से जोड़ा है कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं और कम्पनियों भाहरों में लगात हैं उनसे सरकार को ज्यादा फायदा पहुंचता है और दूसरी इन्डस्ट्रीज से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता। मैंस दन को बताना चाहता हूं कि एच.आई.डी.सी. ने 23 प्राईवेट कम्पनियों को एक करोड़ 74 लाख रूपये सब्सक्राईब किए हुए हैं और इनमें 50 करोड़ रूपया कम्पनियों का लगा हुआ है। उनके कारखानों से हरियाणा के दस हजार आदमियों को काम मिलता है। अब आप इससे हिसाब लगा लें कि हमनें जो प्राइवेट कम्पनियों को रूपया दिया हुआ है और जिन्होंने ये कारखाने लगाये हुए हैं उनसे नुक्सान है या फायदा। जो भोयर कैपिटल एच.एस.आई.डी.सी. का है वह 55 लाख 92 हजार रूपया है, वह वसूल कर रहे है। उसमें से 37 लाख 52 हजार रूपये वसूल कर लिए हैं ओर बाकी रूपये वसूल करने के लिए भीघ्र कोि ा ा कर रहे हैं। आज कल तो

रिक्वरी हो सकती हैं जिस प्रकार से तहसीलदार माल की वसूली करता है उसी प्रकार से इसकी भी वसूली तहसीलदार के थ्रू कर सकते हैं। ज्वायन्ट सैक्टर यानी पब्लिक सैक्टर में कुछ यूनिट्स एच.आई.डी.सी. की ओर से खोले गए हैं। जिनमें पौने दो करोड़ रूपये की इन्वैस्टमैंट हुई है। उसमें 2200 मजदूर काम कर रहे हैं। सरकार को उनसे टैक्स आता है जिससे हरियाणा की माली हालत ठीक होती है।

स्पीकर साहब, ट्रान्सपोर्ट के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गये हैं। वैसे तो इसका जवाब ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब देते लेकिन मैं भी इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब यहां पर बतायसा गया है कि भाादी में लोगों को बसों की बड़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार से सैर के लिए जो लोग जाना चाहते है तो उनको बसें नहीं मिलती। मैं मानता हूं कि भाादी के मौके पर बसों के मिलने में काफी कठिनाई आती है। स्पीकर साहब, इसके बारे में सरकार जरूर गौर करेगी। जिस प्रकार प्राईवट लोगों को दिल्ली में परमिट दिए हुए हैं ऐसे ही सैर और भाादी के लिए बसों के परमिट हरियाणा में भी दे दिए जायें तो यह डिफिकल्टी नहीं होगी। जहां तक और मैम्बरों का सवाल है उन्होंने भी अपनी ओर से सुझाव दिए हैं और सरकार उन पर गौर करेगी। श्रीमति सुशमा स्वराज ने एक बात कही कि एच.एस.आई. डी.सी. ने एक करोड़ दस लाख रूपए नए प्रोजैक्ट लगाने के लिए और उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए खर्च करने

हैं। स्पीकर साहब, यह फिगर एक लाख दस हजार है, एक करोड़ दस लाख नहीं है। मुझे तो इस बात को कहते हुए रामायण की एक चौपाई याद आ गई हैं:–

'महिमा घटी समुन्द्र की

जब रावण बसे पडोस'।

स्पीकर साहब, इस बारे में, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर वे अपने आप को भी उनके बराबर समझती हैं तो उनकी मर्जी है। मैं अधिक कहते हुए आज जो डिमान्ड हाउस के सामने पे ा हुई हैं और उन पर जो बहस हुई हैं उस बहस के बाद इन डिमान्डज को हाउस पास करेगा ताकि सरकार का काम ठीक प्रकार से चल सकें।

डा. मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब आज के 'टाईम्स आफ इण्डिया' अखबार में खबर छपी है कि हरियाणा कैबनिट छोटी होने जा रही है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि कौन कौन से मंत्री जाने वाले हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कैबनिट छोटी नहीं हो रही। अखबार में जो खबर छपी है वह गलत है और न ही हमारी तरफ से कोई स्टेटमैंट दी गई है।

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब डिमान्डज पर वोटिंग होंगी। उसके बाद कृपया आप थोड़ा देर के लिए वेट करें, क्योंकि मैंने अभी कुछ अनाउन्समैंट करनी हैं। अब मैं डिमान्डज वोटिंग के लिए प्रस्तुत करूंगा।

डिमान्ड नम्बर 14, 15 पर कोई कट मो ान नहीं है इसलिए मैं ये दोनों इकट्ठी पुट करता हूंः—

Question is:-

That a sum not exceeding Rs. 12821670 for revenue expenditure and Rs. 1135914670 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 454924135 for revenue expenditure and Rs. 713801040 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः डिमान्ड नम्बर 16 पर श्री मूल चन्द जैन की कट मो ान पहले मैं वोटिंग के लिए पुट करता हूंः—

Question is:-

That the Demand be reduced to Rs. 1/-.

The motion was lost.

श्री अध्यक्षः अब मैं डिमान्ड नम्बर 16 वोटिंग के लिए पुट करता हूं:—

Question is:-

That a sum not exceeding Rs. 40339890 for revenue expenditure and Rs. 14139000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः क्योंकि डिमान्डज नम्बर 17 से 22 पर कोई कट मो ान नहीं है इसलिए मैं इन सब को इकट्ठी पुट करता हूं:—

Question is:-

That a sum not exceeding Rs. 311906550 for revenue expenditure and Rs. 15318000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 60658000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6977400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 34184650 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 200309660 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 22828000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 22-Cooperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: डिमान्ड नम्बर 23 पर श्री मूल चन्द जैन की कट–मोशन पहले मैं वोटिंग के लिए पुट करता हूं–

Question is –

That the Demand is reduced to Rs. 1/-.

The motion was lost.

श्री अध्यक्ष: अब मैं डिमान्ड नम्बर 23 वोटिंग के लिए पुट करता हूं–

Question is –

That a sum not exceeding Rs. 432231500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 23-Transport.

The motion was lost.

श्री अध्यक्ष: डिमान्ड नम्बर 24–25 पर कोई कट–मोशन नहीं है इसलिए मैं वोटिंग के लिए दोनों को इकट्ठी पुट करता हूं।

Question is –

That a sum not exceeding Rs. 4279800 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 614697000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was lost.

राज्यपाल से सन्देश

श्री अध्यक्ष: साहेबान, गवर्नर साहब की तरफ से जो हमने उनके एड्रैस पर कान्ग्रैचुलेशन भेजा था उसका जवाब उन्होंने भेजा है, वह मैं आपको पढ़ देता हूं –

"Dear Mr. Speaker,

I write to acknowledge with thanks the receipt of your demi-official letter No. H.V.S.-LA-8-80/8462, dated 7th March, 1980, forwarding a copy of the Motion of Thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held oon the 7th March, 1980. Please convey to the members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind thought in accepting the motion.

With regards,

Your sincerely,

sd/-

(G.D. TAPASE)"

अब सदन कल प्रातः 9.00 बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है।

13.42 बजे

(तत्पश्चात सदन वीरवार दिनांक 20.3.1980 प्रातः 9.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)

Annexure 'A'

Shortage of electricity and non-availability of diesel in the State

***1633. Sh. Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad**: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that many factories in the State have been either forced to close or run much below their production capacity due to stortage of electricity and non-availability of diesel rendering large number of workers/labourers unemployed; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to meet the demand of the factories for electricity and diesel?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): कोई भी इकाई बंद नहीं हुई है, फिर भी बहुत सी इकाईयों में उनकी क्षमता से कम उत्पादन हुआ है और बहुत से मजदूर इस कारण बे–रोजगार हो गए, विद्युत की सप्लाई में प्रगति लाने के लिए सैन्ट्रल पूल से अतिरिक्त बिजली प्रान्त करने हेतू भरमक प्रयत्न किए जा रहे हैं। फरीदाबाद के ताप बिजली घर में भी अधिक बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त पानीपत में 110 मै. वाट का दूसरा ताप घर 27 मार्च, 1980 को लग गया है और विद्युत उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय सरकार से डीजल का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सभी राज्य के उपायुक्तों को हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे उद्योग के लिए

डीजल की कुल प्राप्ति का 5 प्रतिशत सुरक्षित करें और फरीदाबाद में यह मात्रा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।